



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19]  
No. 19]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 11, 1985/वैशाख 21, 1907  
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 11, 1985/Vaisakha 21, 1907

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1985

(आयकर)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1985

आयकर संस्थापन

का. अ. 1944—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (3) के उपखण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनार्थ, "भारतीय विद्या भवन" का कर निर्धारण-वर्ष 1986-87 से 1988-89 के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए अधिसूचित करती है।

[सं 6180 (फा. सं. 197/199/84-आ.का (वि-1))]

आय. के. निहारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 28th March, 1985

(INCOME-TAX)

S.O. 1944—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Bharatiya Vidya Bhavan" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1986-87 to 1988-89.

[No 6180 (F. No. 197/199/84-IT(A))]

R. K. LEWARI, Under Secy

का. अ. 1945.—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (3) के अनुमरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 9-5-83 की अधिसूचना सं. 5169 (फा. सं. 398/14/83-आ. क. (ब.)) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ओ. पी. तंवर को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कर बसूली अधिकारों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2 यह अधिसूचना श्री ओ. पी. तंवर द्वारा कर बसूली अधिकारों के रूप में कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[सं 6186 (फा. सं. 398/7/85-आ.क. (ब))]

बी. ई. प्रलेक्जेडर, अवर सचिव

New Delhi, the 10th April, 1985

### INCOME TAX ESTABLISHMENT

S.O. 1945.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5169 (F. No. 398/14/83 IT(B) dated the 9-5-83, the Central Government hereby authorises Shri O. P. Tanwar, being a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise of the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from the date Shri O. P. Tanwar takes over charge a Tax Recovery Officer.

[No. 6186 (F. No. 398/7/85-IT(B))]

B. E. ALEXANDER, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1985

### आयकर

का. आ. 1946.—इस कार्यालय की दिनांक 1 मई 1974 की अधिसूचना संख्या 605 फा. सं. 203/27/74-का.आ.नि. II) के अधिक्रमण में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली के निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनार्थ मामले पर पुनर्धार करने पर भारतीय विद्या भवन, बम्बई की "संगम" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदन की अवधि को 31-12-1985 तक सीमित किया है :—

1. यह कि भारतीय विद्या भवन बम्बई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दशति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

[सं. 6191 (फा सं. 203/31/85-आ. क. नि-II)]

New Delhi, the 10th April, 1985

### INCOME-TAX

S.O. 1946.—In supersession of this Office Notification No. 605 (F. No. 203/27/74-ITA II) dated the 1st May, 1974, it is hereby notified for general information that the Secretary, Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read

with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 on a reconsideration of the case has restricted the period of approval to Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay in the category of "Institution" upto 31-12-1985, subject to the following conditions :—

(i) That the Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.

(ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.

(iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax

[No. 6191 (F. No. 203/31/85-IIA. II)]

### (आय-कर)

का.आ. 1947.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (3) के प्रयोजनों के लिए संस्था प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदन किया है अर्थात् :—

1. यह कि एशियन सेण्टर फार आर्गेनाइजेशन रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट, नई दिल्ली वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिक विवरणी, विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

यह कि उक्त संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दशति हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां, देनदारियां दशति हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित आय का आयुक्त को भेजेगी।

### संस्था

"एशियन सेण्टर फार आर्गेनाइजेशन रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट नई दिल्ली"

यह अधिसूचना 20-11-1984 से 31 मार्च, 1986 तक के लिए प्रभावी है।

[सं. 6190 (फा.सं. 203/123/84-आ.क.नि.-II)]

### INCOME-TAX

S.O. 1947.—It is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (iii) of sub-

tion (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Asian Centre for Organisation Research and Development, New Delhi will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

#### INSTITUTION

"Asian Centre for Organisation Research and Development, New Delhi".

This Notification is effective for a period from 20th November, 1984 to 31st March, 1986.

[No. 6190 (F. No. 203/123/84-ITA. II)]

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1985

(आयकर)

का.आ. 1948:—इस कार्यालय की दिनांक 28/5/1983 की अधिसूचना सं. 5205 (फा.सं. 203/62/83-आ.क.नि. II) के सिलसिले में, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी अर्थात् विज्ञान और औद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ-पठित आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए संस्था प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :—

1. यह कि विवेकानन्द आयुर्विज्ञान संस्थान (रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान), कलकत्ता वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का पृथक् लेखा रखेगा।

2. यह कि उक्त संस्था अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी क्रियाकलापों की वार्षिकी विवरणी विहित प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्रारूप प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सूचित किया जाए।

3. यह कि संस्था अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए अपने संपरीक्षित वार्षिक लेखों की तथा अपनी परिसंपत्तियां देनदारियां दर्शाते हुए तुलन-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष 30 जून तक विहित प्राधिकारी की प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक एक प्रति संबंधित आयकर आयुक्त को भेजेगी।

संस्था

"रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठान, कलकत्ता का विवेकानन्द आयुर्विज्ञान संस्थान"

यह अधिसूचना 17/11/1984 से 31/3/1986 तक के लिए प्रभावी है।

[सं. 6200 (फा.सं. 20335/85-आ.क.नि.-II)]

New Delhi, the 19th April, 1985

#### INCOME-TAX

S.O. 1948.—In continuation of this Office Notification No. 5205 (F. No. 203/62/83-ITA. II) dated 28-5-1983 it is hereby notified for general information that the Institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the Prescribed Authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) That the Vivekananda Institution of Medical Sciences of Rama Krishna Mission Seva Pratishthan, Calcutta will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- (ii) That the said Institution will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- (iii) That the said Institution will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax

#### INSTITUTION

"Vivekananda Institute of Medical Sciences of Rama Krishna Mission Seva Pratishthan, Calcutta".  
This Notification is effective for a period from 17th November, 1984 to 31st March, 1986.

[No. 6200 (F. No. 203/35/85-ITA. II)]

(आय-कर)

का.आ. 1949:—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2) (XII) के प्रयोजनार्थ तत्काली वित्त विभाग द्वारा दिनांक 23-11-1946 को जारी की गई अधिसूचना संख्या 34 से निम्नलिखित समितियों के नामों को 26/12/1984 से हटाया जाता है :—

1. इण्डियन सैन्ट्रल काटन कमिटी बम्बई.
2. इण्डियन सैन्ट्रल कोकोनट कमिटी, एर्णाकुलम।
3. इण्डियन सैन्ट्रल जूट कमिटी।
4. इण्डियन सैन्ट्रल आयलसीडस कमिटी।
5. इण्डियन सैन्ट्रल शुगर केन कमिटी, नई दिल्ली।
6. इण्डियन सैन्ट्रल टबैको कमिटी, बम्बई।

[सं. 6201 (फा.सं. 203/27/85-आ.क.नि.-II)]

गिरीश दवे, अवर सचिव

#### INCOME-TAX

S.O. 1949.—It is hereby notified for general information that the names of the following Committees deleted with effect from 26-12-1984 from the Notification No. 34 of dated 23-11-1946 issued by the then Finance Department for the purposes of Section 10(2) (XIII) of the Indian Income-tax Act, 1922 :—

1. Indian Central Cotton Committee, Bombay.
2. Indian Central Coconut Committee, Ernakulam.

3. Indian Central Jute Committee.
4. Indian Central Oilseeds Committee.
5. Indian Central Sugar-Cane Committee, New Delhi.
6. Indian Central Tobacco Committee, Bombay.

[No. 6201 (F. No. 203, 37/85-I[A, II])]

GIRISH DAVE, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1985

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 1950.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, बम्बई को मात्र दो लाख बीस हजार रुपये की समेकित स्टाम्प शुल्क की अदा करने की अनुमति देती है जो उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले दो करोड़ बीस लाख रुपये के अंकित मूल्य के प्रामिसरी नोटों के रूप में "8.75 प्रतिशत म. ओ. वि. नि. बंधपत्र 2000" पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभाय है।

[सं. 14/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/66/84-बि. क.]

New Delhi, the 20th April, 1985

ORDER

STAMPS

S.O. 1950.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra Industrial Development Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of rupees two lakhs twenty thousand only, chargeable on account of the stamp duty on "8.75 per cent M.I.D.C. Bonds, 2000" in the form of promissory notes of the face value of rupees two crores twenty lakhs to be issued by the said corporation.

[No. 14/85-Stamp-F. No. 33/66/84-ST]

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 1951.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो कर्नाटक राज्य वित्त निगम बंगलूर द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र तीन करोड़ सत्तावन लाख पचास हजार रुपये मूल्य के "32" संख्या वाले तथा "9 प्रतिशत बंधपत्र 2000" के रूप में वर्णित प्रामिसरी नोटों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभाय है।

[सं. 15/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/8/85-बि. क.]

ORDER

STAMPS

S.O. 1951.—In exercise of the powers conferred by clause, a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp

Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes bearing the number "32" and described as "9 per cent Bonds-2000" to the value of rupees Three crores fifty Seven lakhs fifty thousand only to be issued by the Karnataka State Financial Corporation, Bangalore are chargeable under the said Act.

[No. 15/85-Stamp-F. No. 33/8/85-ST]

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 1952.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो पंजाब वित्त निगम चंडीगढ़ द्वारा किए जाने वाले मात्र एक सौ सत्तीस लाख पचास हजार रुपये मूल्य के ऋणपत्रों (27 वा निर्गम) के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभाय है।

[सं. 16/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/12/85-बि. क.]

ORDER

STAMPS

S.O. 1952.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Debentures (27th Issue) to the value of rupees One hundred thirty seven lakhs and fifty thousand only to be issued by the Punjab Financial Corporation, Chandigarh, are chargeable under the said Act.

[No. 16/85-Stamp-F. No. 33/12/85-ST]

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 1953.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो तमिलनाडू विद्युत बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र तेइस करोड़ छम्पन लाख बयासी हजार रुपये मूल्य के प्रामिसरी नोटों [9 प्रतिशत तमिलनाडू विद्युत बोर्ड ऋण 1999 (दूसरी श्रृंखला)] के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभाय है।

[सं. 17/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/7/85-बि. क.]

ORDER

STAMPS

S.O. 1953.—In exercise of the powers conferred by clause (A) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes [9 per cent Tamil Nadu Electricity Board loan 1999 (Second Series)] to the value of rupees Twenty three crores fifty six lakhs eighty two thousand only to be issued by the Tamil Nadu Electricity Board are chargeable under the said Act.

[No. 17/85-Stamp-F. No. 33/7/85-ST]



आदेश

स्टाम्प

का.आ. 1954.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बम्बई को केवल तीन लाख नौ हजार तीन सौ पचाहत्तर रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क को अदा-यगी करने की अनुमति देती है जो उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले केवल चार करोड़ बारह लाख पचास हजार रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों के रूप में बंधपत्रों (9 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बन्धपत्र 1999 श्रृंखला 11) पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है।

[सं. 18/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/11/85-बि. क.]

ORDER

STAMPS

S.O. 1954.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay, to pay consolidated stamp duty of rupees Three lakhs nine thousand three hundred seventy five only, chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of Debentures [9 per cent Maharashtra State Financial Corporation Bonds 1999 (IIS)] of the face value of four crores twelve lakhs and fifty thousand rupees only to be issued by the said Corporation.

[No. 18/85-Stamps-F. No. 33/11/85-S1]

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1985

आदेश

स्टाम्प

का.आ. 1955.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैक्सिमो लेबरटोरीज (इंडिया) लिमिटेड को मात्र एक लाख सत्तारो हजार पांच सौ रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है जो उक्त कंपनी द्वारा जारी किए जाने वाले दो करोड़ पचास लाख रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों (प्रति ऋणपत्र प्रदत्त राशि 100 रु. (प्रथम श्रृंखला) 15 प्रतिशत मोचनीय मुरक्षित ऋणपत्र) के रूप में बंधपत्रों पर स्टाम्प शुल्क के रूप में प्रभार्य है।

[सं. 19/85 स्टाम्प-फा. सं. 33/4/85-बि. क.]

New Delhi, the 22nd April, 1985

ORDER

STAMPS

S.O. 1955.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. Glaxo Laboratories (India) Ltd., Bombay, to pay consolidated stamp duty of rupees One lakh eighty seven thousand five hundred only chargeable on account of the stamp duty on bonds in the form of Debentures (amount

paid up per debenture Rs. 100 (First series) 15 per cent redeemable secured debentures) of the face value of Two Crores fifty lakhs of rupees to be issued by the said company.

[No. 19/85-Stamps-F. No. 33/4/85-ST]

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

आदेश

स्टाम्प

का. आ. 1956.— भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम बम्बई को मात्र तीन लाख नौ हजार तीन सौ पचाहत्तर रुपये का समेकित स्टाम्प शुल्क अदा करने की अनुमति प्रदान करती है जो उक्त निगम द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र चार करोड़ बारह लाख पचास हजार रुपये के अंकित मूल्य के ऋणपत्रों के रूप में "9 प्रतिशत म.रा.वि.नि. बन्धपत्र 1999" पर प्रभार्य है।

[सं. 21/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/34/84-बि. क.]

New Delhi, the 26th April, 1985

ORDER

STAMPS

S.O. 1956.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits the Maharashtra State Financial Corporation, Bombay to pay consolidated stamp duty of rupees three lakhs nine thousand three hundred seventy five only, chargeable on account of the stamp duty on "9% M.S.F.C. Bonds 1999" in the form of debentures of the face value of rupees four crores twelve lakhs fifty thousand only to be issued by the said corporation.

[No. 21/85-Stamps-F. No. 33/34/84-ST.]

का.आ. 1957.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा जारी किए जाने वाले मात्र सात करोड़ पचाहत्तर लाख रुपये के मूल्य के प्रामिसरी नोटों (9 प्रतिशत-15 वर्ष आई. आर. सी. आई. बंधपत्र-1989) 11 श्रृंखला) के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य है।

[सं. 20/85-स्टाम्प-फा. सं. 33/61/84-बि. क.]

भगवान दास, अवर सचिव

S.O. 1957.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes [9%-15 years IRCI Bonds 1999 (11th Series)] to the value of rupees Seven crores Seventy five lakhs only to be issued by the Industrial Reconstruction Corporation of India Ltd., Calcutta, are chargeable under the said Act.

[No. 20/85-Stamps-F. No. 33/61/84-ST]

BHAGWAN DAS, Under Secy.

(अध्यक्ष विभाग)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1985

शुद्धि-पत्र

का.आ. 1958.—भारत के राजपत्र, भाग-2 खण्ड (3), उपखण्ड (ii) तारीख 5 जनवरी, 1985 के पृष्ठ 14

पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिसूचना सं. का. आ. 22(एफ 1) (21)-स्था. II (क)/84 तारीख 14 दिसम्बर, 1984 द्वारा प्रकाशित नियमों में नियम 1 के उपनियम (1) में,

(क) "दूसरा" के स्थान पर "पहला" पढ़ें और

(ख) "1984" के स्थान पर "1985" पढ़ें।

[फा. सं. 1 (2) - संस्था II (क)/84]

आर. एल. चौधरी, अव. सचिव

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 25th April, 1985

#### CORRIGENDUM

S.O. 1958—In the rules published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Expenditure), No. S. O. 22 (F. 1 (21)-E. II(A)/84), dated the 14th December, 1984, in the Gazette of India, Part II, Section (3), Sub-section (ii), dated the 5th January, 1985, at page 14, in rule 1, in sub-rule (1) —

(a) for 'Second' read 'First', and

(b) for '1984' read '1985'.

[No. F. 1(21)-E. II(A)/84]

R. L. CHAUDHRY, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1985

का.आ. 1959.—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ड) के उपबन्धों के अनुसूचन में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के परामर्श से एतद् द्वारा कृषि और सहकारिता विभाग कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव श्री एम. सुब्रह्मण्यन को श्री एस.पी. मुखर्जी के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का निदेशक नियुक्त करती है।

[सं. एफ. 7/10/85-बो. ओ. -1]

एस.एम. हसूरकर, निदेशक

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 19th April, 1985

S.O. 1959—In pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the National Bank of Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government in consultation with Reserve Bank of India, hereby appoints Shri M. Subramanian, Secretary in the Department

of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture and Rural Development, New Delhi as the Director of the National Bank for Agriculture and Rural Development vice Shri S. P. Mukherjee.

[No. F. 7/10/85-B.O. I]

S. S. HASURKAR, Director

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 1985

का.आ. 1960.—बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय रिजर्व बैंक का सिफारिश पर एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में फॉर्म "क" के साथ संगत टिप्पणी (च) के उपबन्ध निम्नलिखित बैंकों पर जहां तक उनका संबंध 31 दिसम्बर, 1984 की उनके तुलनापत्रों से है लागू नहीं होगा:

1. रत्नाकर बैंक लि.
2. दि सांगली बैंक लि.
3. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि.
4. इंडियन ओवरसीज बैंक
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक

[संख्या 15/1/85-बो. ओ.-III]

एम. के. एम. कुट्टी, अव. सचिव

New Delhi, the 23rd April, 1985

S.O. 1960.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Note (f) appended to the form 'A' in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the following banks, viz:—

1. The Ratnakar Bank Limited,
2. The Sangli Bank Limited,
3. The Lakshmi Commercial Bank Ltd.,
4. Indian Overseas Bank,
5. Punjab and Sind Bank.

in respect of their balance sheet as at the 31st December, 1984.

[No. 15/1/85 B.O.III]

M. K. M. KUTTY, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 11 मई, 1985

सं. 144/85-सीमाशुल्क

का.आ. 1961.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक राज्य में दक्षिण कन्नड़ जिले में उर्वरी के समीप पुथुर ग्राम को शतप्रतिशत निर्यातानुमुख उपक्रम बनाने के प्रयोजन के लिये भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करने है।

[फा. सं. 473/17/85-सं. शु. VII]

## CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 11th May, 1985

NO. 144/85 CUSTOMS

S.O. 1961.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares village Puthur near Udupi in the Dakshina Kannada District in the State of Karnataka to be a warehousing station for the purposes of setting up hundred per cent export-oriented undertakings.

[F. No. 473/17/85-CUS. VII]

सं० 145/85-संसाधन

का० आ० 1982.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और संसाधन बोर्ड संसाधन अधिनियम, 1932 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, पाँडेचेरा संघ राज्य क्षेत्र में यानम (कार्क नाडा के समीप) को शनप्रतिष्ठान नियमितोन्मुख उपक्रम बनाने के प्रयोजन के लिये भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करता है।

[फा० सं० 473/214/85 सी० शु०-VII]

टी. एच. के. गौरी, प्रवर सचिव

NO. 145/85-CUSTOMS

S.O. 1962.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Yanam (near Kakinada) in the Union territory of Pondicherry to be a warehousing station for the purposes of setting up of hundred percent export-oriented undertakings.

[F. No. 473/214/85-CUS. VII]

T.H.K. GHOURI, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तलिय, मध्य प्रदेश

इन्दौर; 20 अप्रैल, 1985

अधिसूचना, सं. 5/85

का. आ. 1963.—अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, समूह 'ख' के पद पर पदोन्नत होने पर निम्नलिखित निरीक्षकों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (च.श्रे.) ने उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथियों को अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह 'ख' के पद पर कार्य सार ग्रहण कर लिये हैं।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	तैनाती स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
सर्वश्री			
1.	जी. एस. बोढे	रेंज-II, अकोला	15-3-85
		समाहर्तलिय, (पूर्वार्ध) नागपुर	
2.	ए. बी. ठाकूर	अधीक्षक (तकनीकी), मुख्य कार्यालय इन्दौर।	30-3-85 (पूर्वार्ध)

[फा. सं. II (3) 7-गोप/85/2262]

एस. के. धर, समाहर्ता

## CENTRAL EXCISE COLLECTORATE : M.P.

Indore, the 20th April, 1985

NOTIFICATION NO. 5,85

S.O. 1963.—Consequent upon their promotion as Superintendent, Central Excise, Group 'B' the following Inspectors of Central Excise (SG) have assumed their charges as Superintendent, Central Excise, Group 'B' with effect from the dates as shown against each:—

S. No.	Name of the officer	Place of Posting	Date of Assumption of charge
	S/Shri		
1.	G.S. Bobde	Range II Akola. Nagpur Collectorate	15-3-1985 (F.N)
2.	A.B. Thakur	Supdt. (Tech.) Hqrs. Office, Indore.	30-3-1985 (F.N)

[C.No.II(3)7-Con/85/2262]

S. K. DHAR, Collector

## वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1985

रबड़ कंट्रोल

का. आ. 1964.—केन्द्रीय सरकार, रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ऊ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनद्वारा अधिसूचित करती है कि सर्वश्री दिलीप सिंह भूरिया तथा जार्ज जोसेफ मन्डेकल, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा रबड़ बोर्ड कोट्टायम के सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए हैं और यह भी विनिर्दिष्ट करती है कि वे इस पद पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या तब तक, जब तक कि वे लोक सभा के सदस्य रहते हैं, इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे।

[फा. सं. 12/1/84-प्लांट-बी]

आर. बद्रि नाथ, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 23rd April, 1985

(RUBBER CONTROL)

S.O. 1964.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of section 4 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947), read with sub-rule (1) of rule 4 of the Rubber Rules, 1955, the Central Government hereby notifies that Sarvashri Dileep Singh Bhuria and George Joseph Mundackal Member of Parliament, have been elected by the House of the People to be members of the Rubber Board, Kottayam and further specifies that they shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette or for so long as they continue to be members of the House of the People, whichever is earlier.

[F. No. 12/1/84-Plant(B)]

R. BADRINATH, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1985

(काफी नियंत्रण)

का. आ. 1965.—केन्द्रीय सरकार, काफी नियम, 1955 के नियम 3 और नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आर. अन्ना नम्बो और श्री वी. एस. विजयाराघवन, संसद सदस्य, लोक सभा के सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा तब तक के लिए जब तक वे लोकसभा के सदस्य रहते हैं जो भी पहले हो काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में निर्वाचित को एतद्वारा अधिसूचित करती है।

[फाइल सं. 2/2/84-प्लाट (बी)]

पवन चोपड़ा, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 23rd April, 1985

(COFFEE CONTROL)

S.O. 1965.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 4 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942) read with rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Coffee Rules, 1955, the Central Government hereby notifies the election of Shri R. Anna Nambi and Shri V. S. Vijayaraghavan, Members of Parliament, House of the People, to serve as members of Coffee Board for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette or for so long as they continue to be members of the House of the People, whichever is earlier.

[F. No. 2/2/84-Plant(B)]  
PAWAN CHOPRA, Jt. Secy.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

मद्रास, 12 फरवरी, 1985

आदेश

का. आ. 1966.—मर्वेथ्री ट्यूब प्रोडक्ट्स आफ इंडिया (एकल कोल्ट रोल मिल लिमिटेड) मालिक : ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आफ इंडिया लिमिटेड आवडी, मद्रास-600054 को अप्रैल-84/मार्च-85 अधि के लिए रुपये 7,30,556/- तक प्रतिबन्धित फालत पुर्जों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी/डी/2248007/सी/एकएमएम/94/एम/84 दिनांक 31-10-84 जारी किया गया था। उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण तथा सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रतियां जारी करने के लिए लाइसेंसधारी ने इसलिए आवेदन किया है कि उपर्युक्त लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत करवाये बिना या उपयोग में लाये बिना खो दी गयी है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदन ने एक शपथपत्र दाखिल किया है। अवोह्वनाक्षरी इस बात में संतुष्ट है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण तथा सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रतियां खो दी गई हैं और आदेश देती है कि उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण तथा सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां आवेदक को जारी किया जाये। लाइसेंस की मूल प्रति एतद्वारा रद्द किया जाता है।

सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ तथा मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियों की अनुलिपि प्रतियां क्रमशः संख्या डी. 2464846 तथा डी. 2464847 दिनांक 1-2-82 अलग जारी किये जाते हैं।

[संख्या आईटीसी/आटोमेटिक/182/एमएम 85/एयु. 1]

मो. जी. फेरनान्डेज, उपमुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात।

(Office of the Joint Chief Controller of Imports &amp; Exports)

Madras, the 12th February, 1985

ORDER

S.O. 1966.—M/s. Tube Products of India (Unit : Cold Roll Mill Division) Prop. : Tube Investments of India Ltd., Avadi, Madras-600054 were granted import licence No. P/D/2248007/C/XX/93/M/84 dated 31-10-84 for restricted spares for a value of Rs. 7,30,556 for the period April 1984-March 1985. They have requested this office to issue duplicate exchange control copy and customs purpose copy of above mentioned licences which have been lost without having been registered with any Customs Authority and utilised at all.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the original copies of the licence (Exchange Control copy and Customs Purpose Copy) have been lost and directs that duplicates of the said licence (Exchange Control and Customs Purpose Copies) should be issued to them. The original copies of the licence is hereby cancelled.

Duplicate licences (Customs & Exchange Copies) No. D. 2464846 and D. 2464847 dated 1-2-85 respectively have been issued separately.

[No. ITC/Automatic/182/AM85/AU.I]

C. G. FERNANDEZ, Dy. Chief Controller of  
Imports & Exports

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1985

का. आ. 1967.—राजनयिक एवं कंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (क) के अनुपालन में केन्द्र सरकार इसके द्वारा, मस्केट स्थित भारतीय राजदूतावास में सहायक श्री के. पी. आर. मेनन को 1.3.1985 में कंसली एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/1/85]

बी आर. घुलियानी, उप-सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 27th March, 1985

S.O. 1967.—In pursuance of the clause (a) of Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorise Shri K. P. R. Menon, Assistant in the Embassy of India, Muscat to perform the duties of Consular Agent with effect from 1-3-85.

[No. T. 4330/1/85]

B. R. GHULIANI, Dy. Secy.

(हज मेल)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1985

का. आ. 1968.—हज समिति नियम, 1959 (1959 का 51वां) की धारा 17 की उपधारा 2 के खंड "घ" और धारा 18 की उपधारा 1 के खंड "ग" के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हज समिति, बम्बई की 30 मार्च, 1985 को हुई बैठक में अध्यक्ष के रूप में श्री मुस्तफा फकीह और उपाध्यक्ष के रूप में श्री गहज़ादा शब्बीर भाई साहेब नुरुद्दीन

के चुनाव को उनके पूर्वाधिकारियों क्रमशः श्री एम. ए. खडवानो और श्री युसुफ हफोज का शेष अवधि के लिए 24 अगस्त, 1985 तक अथवा हज समिति का पुनर्गठन होने तक इनमें से जो भी पहले हो, अधिसूचित करती है।

[एम (हज) 118-1/15/80]

आरिफ कमरेन, संयुक्त सचिव (अफ्रीका/हज)

(Haj Cell)

New Delhi, the 22nd April, 1985

S.O. 1968.—In pursuance of clause (d) of Sub-section 2 of Section 17 and clause C of Sub-section 1 of Section 12 of the Haj Committee Act, 1959 (51 of 1959), the Central Government hereby notify the election of Shri Mustafa Fakih as Chairman and Shri Shahzada Shabbir Bhai Saheb Nuruddin as Vice-Chairman of the Haj Committee. Bombay at its meeting held on 30th March, 1985 for the un-expired portion of the term of their predecessors namely Sh. M. A. Khandwani and Sh. Yusuf Hafiz respectively till 24th August 1985 or till the reconstitution of the Haj Committee, whichever is earlier.

[No. M(Haj)/118-1/15/80]

ARIF QAMARAIN, Jt. Secy. (Afr./Haj)

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 1985

का. आ. 1969—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित उपक्रमों के पंजीकरण के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विलयन, समांमेलन, राष्ट्रीयकरण और अधिग्रहण के कारण अब अस्तित्व में नहीं हैं।

उपक्रम का काम	पंजीकरण संख्या	निरस्तीकरण का कारण
1	2	3
1. अलगप्पा टेक्सटाइल्स (कोचीन) लि०	623/70	राष्ट्रीयकृत
2. एटलस आयरन एण्ड अलायज लि.	782/70	परिसमापन में
3. बिड़ला ग्वालियर लि.	1038/75	समांमेलित
4. ब्रेवियाइट एण्ड कम्पनी (इंडिया) लि.	360/70	सरकार द्वारा अधिकार में ले ली गई।
5. कालटेक्स (इंडिया) लि.	22/70	—यद्योपरि—
6. कालटेक्स आयरन रिफ़ाइनिंग (इंडिया) लि.	98/70	—यद्योपरि—

1	2	3	4
7. कैम्पबेल एण्ड कम्पनी (साउथ इंडिया) लि.	1265/76	समांमेलित	
8. डी. सी. एम. इन्टर-नैशनल लि.	381/70	परिसमापन में	
9. गोहपुर टी कम्पनी लि.	1157/75	समांमेलित	
10. इन्टरनैशनल टैक्टर्स कम्पनी आफ इंडिया लि.	938/74	समांमेलित	
11. केरल लक्ष्मी मिल्स लि.	567/70	राष्ट्रीयकृत	
12. खटाऊ होलिडैस लि.	701/71	समांमेलित	
13. कुलु बैली डबलपमेंट कम्पनी लि.	795/71	परिसमापन में	
14. एल. एण्ड टी. ड्रिलिंग डबलपमेंट लि.	375/70	समांमेलित	
15. एल. एण्ड टी. (मैनेज-मेंट) प्रा. लि.	1116/75	परिसमापन	
16. मडुरा इन्सोरेस कम्पनी लि.	599/70	राष्ट्रीयकृत	
17. मैसूर मेटल्स लि.	50/70	परिसमापन में	
18. न्यू असम वेली टी. कम्पनी लि.	116/70	समांमेलित	
19. न्यू मनखुशी टी. कम्पनी लि.	390/70	समांमेलित	
20. पार्वती मिल्स लि.	620/70	राष्ट्रीयकृत	
21. श्री सादुल टेक्सटाइल्स लि.	802/71	विलयन	
22. श्री शारदा मिल्स लि.	614/70	राष्ट्रीयकृत	
23. स्टेन्डर्ड टायर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1083/75	परिसमापन	
24. त्रिमूर्ति मिल्स लि.	785/75	समांमेलित	
25. विजयमोहिनी मिल्स लि.	565/70	राष्ट्रीयकृत	
26. बैस्ट बोकारो लि.	167/70	समांमेलित	
27. नैशनल लाइफलेस लि.	531/70	समांमेलित	
28. कलिंगा ट्यूब्स लि.	1488/80	समांमेलित	
29. बाली जुट कम्पनी लि.	913/73	समांमेलित	
30. आयुर्वेदिक एण्ड बूनानी मेडीसिन्स लि.	720/71	विलयन	
31. कमानी ब्रादर्स प्रा. लि.	32/70	परिसमापन	
32. मध्य प्रदेश इन्डस्ट्रीज लि.	710/71	समांमेलित	
33. श्रीगोपाल इन्डस्ट्रीज लि.	991/74	विलयन	

1	2	3	4
34. भुटीचिंग टी. कम्पनी लि.	46/70	समामेलित	
35. युरोकोटा (इंडिया) लि.	1374/78	समामेलित	
36. हिन्दुस्तान ट्रेडर्स लि.	236/70	सरकार द्वारा अधिकृत	
37. लिप्टन (इंडिया) लि.	1263/76	समामेलित	
38. नागरी फार्म टी कम्पनी लि.	1156/75	समामेलित	
39. नैशनल पाइप्स एण्ड ट्यूब्स कम्पनी लि.	831/72	परिसमापित	
40. एस. जी. केमिकल्स एण्ड फार्मोस्यूटीकल्स लि.	811/71	समामेलित	
41. युनियन जूट कम्पनी लि.	1118/75	सरकार द्वारा अधिकृत	
42. बसन्ती फाटन मिल्स लि.	1514/81	समामेलित	
43. जे.के. कमर्शियल कारपोरेशन लि.	655/70	समामेलित	

[सं. 16/12/85-एम-3]

वी. पी. गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF INDUSTRY &amp; COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 20th April, 1985

S.O. 1969.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of the following undertakings which are no longer in existence on account of merger, amalgamation, nationalisation and take-over under the said Act;

Name of the Undertaking	Regn. No.	Reasons for Cancellation
1	2	3
1. Alagappa Textiles (Cochin) Limited.	623/70	Nationalised.
2. Atlas Iron & Alloys Limited.	782/70	In Liquidation
3. Birla Gwalior Limited.	1038/75	amalgamated
4. Braithwaite & Co. (India) Ltd.	360/70	Take over by Govt.
5. Caltex (India) Limited.	22/70	-Do-
6. Caltex Oil Refining (India) Ltd.	98/70	-Do-
7. Campbell & Co. (South India) Ltd.	1265/76	Amalgamated
8. D.C.M. International Limited.	381/70	In Liquidation
9. Gohpur Tea Company Limited.	1157/75	Amalgamated
10. International Tractors Company of India Limited.	938/74	Amalgamated
11. Kerala Lakshmi Mills Limited.	567/70	Nationalised

1	2	3	4
12. Khatau Holdings Limited.	701/71	Amalgamated	
13. Kulu Valley Development Co. Ltd.	795/71	In Liquidation	
14. L&T Drilling Equipment Ltd.	315/70	Amalgamated	
15. L&T (Management) Private Ltd.	1116/75	Liquidation	
16. Madura Insurance Co. Ltd.	599/70	Nationalised	
17. Mysore Metal Limited.	50/70	Liquidation	
18. New Assam Valley Tea Co. Ltd.	116/70	Amalgamated	
19. New Monkhooshi Tea Co. Ltd. f	390/70	Amalgamated	
20. Parvathi Mills Limited.	620/70	Nationalised	
21. Shree Sadul Textiles Ltd.	802/71	Merged	
22. Sri Sarada Mills Limited.	614/70	Nationalised	
23. Standard Tyre Products P. Ltd.	1083/75	Liquidation	
24. Tirumurti Mills Limited	785/75	Amalgamated	
25. Vijaymohini Mills Limited	565/70	Nationalised	
26. West Bokaro Limited	167/70	Amalgamated	
27. National Lifes Limited.	531/70	Amalgamated	
28. Kalinga Tubes Limited.	1488/80	Amalgamated	
29. Balley Jute Co. Ltd.	913/73	Amalgamated	
30. Ayurvedic & Unani Medicines Ltd.	720/71	Merged	
31. Kamani Brothers Pvt. Ltd.	32/70	Liquidation	
32. Madhya Pradesh Industries Ltd.	710/71	Amalgamated	
33. Shree Gopal Industries Ltd.	991/74	Merged	
34. Bhooteaching Tea Co. Ltd.	46/70	Amalgamated	
35. Burokota (India) Limited.	1374/78	Amalgamated	
36. Hindustan Tractors Limited.	236/70	Take over by Government.	
37. Lipton (India) Limited.	1263/76	Amalgamated	
38. Nagri Farm Tea Co. Ltd.	1156/75	Amalgamated	
39. National Pipes & Tubes Co. Ltd.	831/72	Liquidation	
40. S.G. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	811/71	Amalgamated	
41. Union Jute Co. Ltd.	1118/75	Taken over by Government	
42. Basanti Cotton Mills Limited	1514/81	Amalgamated	
43. J.K. Commercial Corpn. Ltd.	655/70	Amalgamated	

[No. 16/12/85—M.III]

V.P. GUPTA, Director

## भारी उद्योग विभाग

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1985

का. अ. 1970—सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिकारियों की देखरेखी) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतेद्वारा भारत के राजपत्र भाग-2 खंड-3 उपखण्ड (ii), दिनांक 9 अगस्त, 1975 में प्रकाशित भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या का. अ. 2553 दिनांक 28 जुलाई, 1975 में विमलखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में दी गई सारणी में, कॉलम (1) के अन्तर्गत दी गई प्रविष्टि में, शब्द "वर्षिक कार्मिक अधिकारी" शब्दों के स्थान पर "उप-प्रबन्धक" शब्दों को रखा जायेगा।

[फाइल सं. 10-71/74-एन.ई.पी. II/एन ई पी-III]

सहज पास गुप्त, अवर सचिव

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 23rd April, 1985

S.O. 1970.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Heavy

Industry No. S.O. 2553, dated the 28th July, 1975, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th August, 1975, namely :—

In the said notification, in the Table, in the entry under column (I), for the words "Senior Personnel Officer" the words "Deputy Manager" shall be substituted.

[File No. 10-71/74-HEP-II/HEP-I]

M. P. GUPTA, Under Secy.

## पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1985

का. आ. 1971.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिये नामरूप जिला डिब्रूगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एकसूचना योजना के लिये ओ. एन. जी. सी. जी. सी. जी. एस. नं. एक (सी. टी. एफ.) लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एनद्पावड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायुक्त शिवसागर, आसाम की कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. जी. एस. नं. एक लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना

राज्य—आसाम जिला—शिवसागर

तालुका—अभयपुर

क्रम संख्या	गांव	पाटा नं.	दांग नं.	एरिया			मन्तव्य
				बी.	क.	ल.	
1	2	3	4	5			6
1. मोहन गांव (खसरा नं.)							
		107 नं.	मियाडी	364	--	2	4
		1	,,	495	--	2	11
		1	,,	367	--	1	3
		17	,,	366	--	0	2
		17	,,	368	2	0	0
		124	,,	372	1	3	15
		54	,,	505	--	2	0
		54	,,	511	--	1	2

1	2	3	4	5	6
	54	„	512	---	3 4
	54	„	506	---	1 8
	54	„	507	---	2 8
	9	„	509	---	2 8
	54	„	510	---	1 2
	54	„	515	---	0 7
	15	„	462	---	1 10
	15	„	395	---	0 7
	45	„	475	---	0 7
	15	„	469	---	19
	7	„	498	---	2 15
	104	„	499	---	1 2
	54	„	508	---	0 2
	एकसता	„	494	---	1 4
कुल क्षेत्रफल				10	3 14

[सं. 0-12016/12/85 ओ. एन. जी.-डी 4]

## MINISTRY OF ENERGY

New Delhi, the 22nd April, 1985

S.O. 1971.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion Project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ANGC G.G. Sl. No. 1 (CTF) Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizers Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

## LAND SCHEDULE

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Abhoypur

Name of village	Patta No.	Dag No.	Area		
	P.P. No. 107	364	0B	2K	4L
	P.P. No. 1	495	0B	2K	11L
		367	0B	1K	3L
	Annual Patta	494	0B	1K	4L
	P.P. No. 17	366	0B	0K	2L
		368	2B	0K	0L
Mohan Gaon	P.P. No. 124	372	1B	4K	15L
Part II.	P.P. No. 54	505	0B	2K	0L
		511	0B	1K	2L
		512	0B	3K	4L
		506	0B	1K	8L
		507	0B	2K	8L
		510	0B	1K	2L
		515	0B	0K	7L
		508	0B	0K	2L
	P.P. No. 9	509	0B	2K	8L
	P.P. No. 15	462	0B	1K	10L
		395	0B	0K	7L
		469	0B	2K	19L
	P.P. No. 45	475	0B	0K	7L
	P.P. No. 7	498	0B	2K	15L
	P.P. No. 104	499	0B	1K	2L
Total:			10B	3K	14L

[No. 0-12016/12/85-ONG-D 4]



रा. आ. 1972.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरवहाह के लिए नामरूप जिला डिब्रुगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप-III एक्सपन्शन योजना के लिये ओ. एन. जी. सी. जी. एस. नं. एक (सी. टी. एफ.) लाकूवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी उपामुक्त शिवसागर, आसाम की कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर दर्ज न करेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई व्याक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. जी. एस. नं. एक लाकूवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम तक नामरूप गैस पाइप लाइन बिछाना

राज्य—आसाम		जिला—शिवसागर		तालूका—अभयपुर		
क्र. संख्या	गांव	पाटा नं.	दांग नं.	एरिया		
				बी.	क.	ल.
1		2	3	4	5	6
1. ग्राण्ट नं. 288	288/	नं. मियादी	48	—	0	13
313 बी और तीन भाग	313					
	59	”	54	—	4	15
	87	”	55	1	1	1
	39	”	57	—	2	15
	6	”	67	—	1	13
				कुल क्षेत्रफल		
				4—0—17		

[सं. ओ.-12016/10/85--ओ एन जी डी-4]

S.O. 1972.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

#### LAND SCHEDULE

State : Assam	District : Sibsagar	Taluk : Abhoypur				
Name of village	Patta No.	Dag No.	Area			
	288					
	P.P. No. 313	48	0B	0K	13L	
	P.P. No. 5	54	0B	4K	15L	
Grant No.	P.P. No. 8	55	1B	1K	1L	
288/313	P.P. No. 3	57	0B	2K	15L	
	P.P. No. 6	67	0B	1K	13L	
			Total:	3B	0K	17L

[No. O-12016/10/85-ONG-D4]

का.आ. 1973.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिये नामरू, जिला डिब्रूगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप-III एक्सपैन्शन योजना के लिये ओ. एन. जी. सी. जी. जी. एस. नं. एक (सी. टी. एफ.) लाकुबा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाईप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग को अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्षों कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपमुख्य शिवसागर, आसाम की कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. जी. एस. नं. एक लाकुबा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना

राज्य—आसाम

जिला—शिवसागर

तालुक—अभयपुर

क. सं.	गांव	पाटा नं.	वाग नं.	एरिया			मातव्य
				बी.	क.	ल.	
	बराही ग्राण्ट	147/427 नं. मियादी	5	6	4	9	
	पहला और दूसरा भाग	1 नं. चाय मियादी	12	0	4	15	
		1 " "	74	1	3	0	
		1 " "	29	0	0	4	
		1 " "	28	1	1	1	
		1 " "	30	0	0	6	
		1 " "	32	0	0	15	
		1 " "	76	0	1	15	
		1 " "	36	0	1	8	
		1 " "	41	0	0	3	
		1 " "	42	3	0	4	
		1 " "	78	1	4	3	
		1 " "	43	0	0	3	
		1 " "	44	2	1	11	
		1 " "	45	0	0	6	
	30 वर्ष चाय						
		142/426 नं. मियादी	47	4	1	16	
कुल क्षेत्रफल				23	0	19	

S.O. 1973.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Dultajan.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

LAND SCHEDULE					
State : Assam	District : Sibsagar	Taluk : Abhoypur			
Name of village	Patta No.	Dag No.	Area		
	147				
	P.P. No. 427	5	6B	4K	9L
Borahi Grant No. I & II	T.P. No. 1	12	0B	4K	15L
		74	1B	3K	0L
		29	0B	0K	4L
		28	1B	1K	1L
		30	0B	0K	6L
		32	0B	0K	15L
		76	0B	1K	15L
		36	0B	1K	8L
		41	0B	0K	3L
		42	3B	0K	4L
		78	1B	4K	3L
		43	0B	0B	3L
		44	2B	1K	11L
		45	0B	0K	6L
	142				
	P.P.No. 426	47	4B	1K	16L
	Total		23B	0K	19L

[No. O-12016/11/85-ONG-D4]

का० आ० 1974—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिये नामरूप, जिला डिब्रुगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप-III एक्सपैन्शन योजना के लिये ओ. एन. जी. सी. जी. जी. एस. न. एक (सी. टी. एफ.) लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाईप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग को अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए सक्षम अधिकारी, उपायुक्त शिवसागर, आसाम की कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. जी. एस. न. एक लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइपलाइन बिछाना

राज्य—आसाम

जिला—शिवसागर

तालुक—सापेकाटी

क. सं.	गांव	पाटा नं.	दाग नं.	एरिया		मन्ताव्य
				बी.	क.	ल.
1.	3 न. मेडनपारा	30	समा 1 नं.			
	30 समा ग्रन्ट	(380/13-10)	1	15	4	6
कुल क्षेत्रफल				15	4	6

[सं. ओ. 12016/15/85-ओ. एन. जी. सी. जी. एस. न. 4]

S.O. 1974.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Dulajjan.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the

laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### LAND SCHEDULE

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Sapekhati

Nome of Village	Patta No.	Dag No.	Area		
Modela Jan No. 3	30 years P.P. No. 1 (380/13/10)	1	15B	4K	6L
Total			15B	4K	6L

[No. O-12016/15/85-ONG-D4]

का आ. 1975—यत्. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिए नामरूप, जिला डिब्रूगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिये ओ. एन. जी. सी. जी. जी. एम. नं. एक (सी. टी. एफ.) लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाईप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड बुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत्. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग को अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायुक्त शिवसागर, आसाम की कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

ओ० एन० जी० सी० जी० एम० नं० एक लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाईप लाइन बिछाना।

राज्य : आसाम

जिला : शिवसागर

तालुक : अभयपुर

क.सं. गांव	पाटा नं.	दाग नं.	एरिया			मन्तव्य
			बी.	क.	ल.	
1. टियक गांव (तृतीय भाग)	138 नं. मियादी	709	1	2	14	
	199 " "	710	—	4	19	
	144 " "	886	—	1	4	
	213 " "	733	2	2	4	
	57 " "	831	—	2	10	
	94 " "	833	—	1	11	
	255 " "	834	2	2	2	
	58 " "	836	—	1	11	
	58 " "	838	—	0	18	
	58 " "	837	1	3	12	
	206 " "	857	—	0	9	
	238 " "	850	—	0	11	
	345 " "	853	—	2	11	
	238 " "	855	—	0	11	
	238 " "	854	—	2	11	
	1 " "	979	2	1	18	
	132 " "	724	—	0	2	
	एकसना	856	—	3	10	

कुल क्षेत्रफल

15 0 8

[सं. O-12016/16/85—ओ एन जी—डी 4]

S.O. 1975.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

LAND SCHEDULE					
State : Assam		District : Sibsagar		Taluk : Abhoypur	
Name of village	Patta No.	Dag No.	Area		
Teok Gaon Part-III	P.P. No. 138	709	1B	2K	14L
	P. P. No. 199	710	0B	4K	19L
	P.P. No. 144	886	0B	1K	4L
	P.P. No. 213	733	2B	2K	4L
	P.P. No. 57	831	0B	2K	10L
	P.P. No. 94	833	0B	1K	11L
	P.P. No. 245	834	2B	2K	2L
	P.P. No. 58	836	0B	1K	11L
		838	0B	0K	18L
		837	1B	3K	12L
	P.P. No. 206	857	0B	0K	9L
	P.P. No. 238	850	0B	0K	11L
	P.P. No. 345	853	0B	2K	11L
	P.P. No. 238	855	0B	0K	11L
		854	0B	2K	11L
	P.P. No. 1	979	2B	1K	18L
	P.P. No. 132	724	0B	0K	2L
	Annual Patta	856	0B	3K	10L
Total			15B	0K	8L

[No. O-12016/16/85-ONG-D4]

का.आ. 1976.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबराह के लिये नामरूप, जिला डिब्रुगढ़, असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिये ओ. एन. जी. सी. जी. जी. एस. नं. एक (सी. टी. एफ.) लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड, दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग को अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद् द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम अधिकारी, उपायुक्त शिवसागर, आसाम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. जी. एस. नं. एक लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना।

राज्य : आसाम

जिला : शिवसागर

तालुक : शीलाकुटी

क्र.सं.	गांव	पाटा नं.	दाग नं.	एरिया			मन्तव्य
				बी.	क.	ल.	
1.	शला पथार						
		80 न. मियादी	79	—	0	7	
		58 " "	80	—	3	2	
		58 " "	82	—	0	15	
		7 " "	86	—	1	9	

1 शला पथार	7 न० मियादी	85	—	1	13
	7 " "	87	—	1	13
	35 " "	71	—	1	2
	10 " "	72	—	1	2
	10 " "	106	—	1	10
	20 " "	74	—	1	13
	13 " "	108	—	0	18
	17 " "	109	—	1	11
	24 " "	165	—	1	6
	17 " "	161	—	0	10
	17 " "	156	—	0	5
	6 " "	115	—	1	9
	6 " "	166	—	0	7
	21 " "	164	—	1	2
	18 " "	163	—	1	1
	3 " "	162	—	0	9
	3 " "	155	—	0	9
	23 " "	188	—	1	2
	23 " "	151	—	0	2
	14 " "	150	—	0	18
	25 " "	149	—	1	17
	7 " "	148	—	1	2
	30 " "	147	—	2	2
	17 " "	199	—	2	4
	17 " "	226	—	1	17
	18 " "	225	—	3	8
	18 " "	318	—	1	6
	19 " "	300	—	0	15
	33 " "	301	—	1	7
	एकसना	28	—	1	4
	"	83	—	2	8
	33 न. मियादी	344	—	0	18
	14 " "	312	—	2	11
	2 " "	311	—	1	13
	40 " "	310	—	2	11
	40 " "	354	1	0	5
	40 " "	362	—	1	8
	40 " "	363	—	0	9
	40 " "	386	—	0	13
	71 " "	387	—	0	8
	15 " "	388	—	1	13
	11 " "	396	—	2	0
	11 " "	397	—	1	7
	69 " "	400	—	2	0
	69 " "	395	—	1	13
	32 " "	84	—	1	11
	36 " "	313	—	1	1
	36 " "	314	—	1	7
कुल क्षेत्रफल			14	3	13

S.O. 1976.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### LAND SCHEDULE

State : Assam District : Sibsagar Taluk : Silakuti

Name of village	Patta No.	Dag No.	Area		
			B	K	L
Chola Pathar	Annual Patta	28	0	1	4
	Annual Patta	83	0	2	8
	P.P. No. 80	79	0	0	7
	P.P. No. 58	80	0	3	2
	-do-	82	0	0	15
	P.P. No. 7	86	0	1	9
	-do-	85	0	1	13
	-do-	87	0	1	13
	P.P. No. 35	71	0	1	2
	P.P. No. 10	72	0	1	2
	-do-	106	0	1	10
	P.P. No. 20	74	0	1	13
	P.P. No. 13	108	0	0	18

P.P. No. 17	109	0	1	11
P.P. No. 24	165	0	1	6
P.P. No. 17	161	0	0	10
-do-	156	0	0	5
P.P. No. 6	115	0	1	9
-do-	166	0	0	7
P.P. No. 21	164	0	1	2
P.P. No. 18	163	0	1	1
P.P. No. 3	162	0	0	9
-do-	155	0	0	9
P.P. No. 23	188	0	1	2
-do-	151	0	0	2
P.P. No. 14	150	0	0	18
P.P. No. 25	149	0	1	17
P.P. No. 7	148	0	1	2
P.P. No. 30	147	0	2	2
P.P. No. 17	199	0	2	4
-do-	226	0	1	17
P.P. No. 18	225	0	3	8
-do-	318	0	1	6
P.P. No. 19	300	0	0	15
P.P. No. 33	301	0	1	7
-do-	344	0	0	18
P.P. No. 14	312	0	2	11
P.P. No. 2	311	0	1	13
P.P. No. 40	310	0	2	11
	354	1	0	5
	362	0	1	8
	363	0	0	9
	386	0	0	13
P.P. No. 71	387	0	0	8
P.P. No. 15	388	0	1	13
P.P. No. 11	396	0	2	0
	297	0	1	7
P.P. No. 69	400	0	2	0
	395	0	1	13
P.P. No. 32	84	0	1	11
P.P. No. 36	313	0	1	1
	314	0	1	7
Total		14	3	13

[No. O—12016/134/84-ONG—D4]

का.आ. 1977.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि प्राकृतिक गैस सरबहाराह के लिये नामरूप जिला डिब्रुगढ़ असम में हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के नामरूप III एक्सपैन्शन योजना के लिये ओ. एन. जी. सी० जी. जी. एस. नं. एक (सी. टी. एफ.) लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक पाइप लाइन आसाम गैस कम्पनी लिमिटेड दुलियाजान द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आदेश एतद्द्वारा घोषित किया है।

वशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के सीने पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी उपायुक्त शिवसागर आसाम के कार्यालय में इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

ओ. एन. जी. सी. जी. एस. नं. एक लाकुवा से हिन्दुस्तान उर्वरक निगम नामरूप तक गैस पाइप लाइन बिछाना।

राज्य : आसाम

जिला : शिवसागर

तालुक : शीलाकुटी

क्र.सं.	गांव	पाटा नं.	दाग नं.	एरिया			मन्तव्य
				बी.	क.	ल.	
1.	शीला चाय बगीचा (1. 2 खण्ड)	1 नं० चाय मियादी	63	3	1	1	
		4 " मियादी	60	—	0	10	
		1 " चाय मियादी	72	—	0	18	
		1 " 30 सना मियादी	71	1	4	18	
		एकसना —	74	—	0	15	
कुल क्षेत्रफल				5	3	2	

[सं. ओ-12016/135/84-ओ एन जी-डी 4]

S.O. 1977.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for supply of natural gas for expansion project-III of M/s. Hindustan Fertilizer Corpn. Ltd., Namrup, District Dibrugarh, Assam pipeline should be laid from ONGC, G.G. Sl. No. 1 (CTF), Lakwa to M/s. Hindustan Fertilizer Corporation Ltd., Namrup by Assam Gas Company Limited, Duliajan.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 day from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the competent Authority viz. Deputy Commissioner/Addl. Deputy Commissioner, Sibsagar, District, Sibsagar, Assam.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## LAND SCHEDULE -

State : Assam		District : Sibsagar		Taluk : Silakuti		
Name of village	Patta No.	Dag No.	Area			
			B	K	L	
Chola Tea Estate Part I & II	T.P. No. 1	63	3	1	1	
	P.P. No. 4	60	0	0	10	
	P.P. No. 1	72	0	0	18	
	30 yrs PP No. 1	71	1	4	18	
	Annual Patta	74	0	0	15	
Total			5	3	2	

[No. O-12016/135/84-ONG-D4]

क्रा. आ. 1978:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम

विवरण की अधिसूचना का. आ. सं. 4577 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब उतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।



## अनुसूची

सोभासण-29 से सोभासण-17 तक पाइप लाइन  
बिछाने के लिये।

राज्य — गुजरात जिला और तालुका — मेहसाणा

गांव	ब्लॉक न.	हे.	एआर.	सें.
कुकस	80	0	07	68
	81	0	00	75
	78	0	09	36
	76	0	01	44

[सं. ओ-12016/119/84-ओ एन जी-डी-4]

S.O. 1978.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 4577 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

## SCHEDULE

Pipe line from SOB-29 to SOB-15.

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana

Village	Block No.	Hecta- tare	Are	Centi- tiare
Kukas	80	0	07	68
	81	0	00	75
	78	0	09	36
	76	0	01	44

[No. O-12016/119/84-ONG-D4]

का० प्रा० 1979.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 292 (12016/1/85-ओ एन जी-डी-4) तारीख 26.1.85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः सश्रम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधिनियम सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

अतः अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है, कि इस अधिसूचना से सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्र सरकार में विहित होने को बचाये हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बंबई के क्षेत्रीकरण में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन का तात्पर्य को निहित होगा।

## अनुसूची

पाइप लाइन आवर्द्ध गांव से, तालुका पनवले, जिला. रायगड

## महाराष्ट्र

गांव	खसरा नम्बर	हिस्सा नम्बर	क्षेत्रफल हेक्टर	एयर
आवर्द्ध	6 का भाग	--	00	01
	114 "	--	00	05
	115 "	--	00	09
	116 "	--	00	07
	117 "	--	00	52
	125 "	--	00	09
	126 "	--	00	03
	127 "	--	00	22
	128 "	--	00	11
	129 "	--	00	01
	131 "	--	00	16

[सं. O-12016/1/85-ओएनजी-डी-4]

पा. के. राजगोपालन, डेप्ट. अधिकारी

S.O. 1979.—Whereas by a notification of Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 292 (O-12016/2/85-ONG-D4) dated 26-1-85 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline.

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government.

And further the Central Government has after considering the said report decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore in exercise of the power conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification are hereby acquired for laying the pipelines.

And further in exercise of the power conferred by Sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Bombay free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Pipeline passing through village Adaac.

Taluka : Panvel, Dist. : Raigad, Maharashtra.

Village	Survey No./Gut No.	Hissa No.	AREA	
			H	R
Adaac	6Part	—	00	01
"	114 Part	—	00	05
"	115 Part	—	00	09
"	116 Part	—	00	07
"	117 Part	—	00	52
"	125 Part	—	00	09
"	126 Part	—	00	03
"	127 Part	—	00	22
"	128 Part	—	00	11
"	129 Part	—	00	01
"	131 Part	—	00	16

[No. O—12016/1/85— ONG— D4]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1985

का. आ. 1980.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3467 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

### अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीश पुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला		तहसील परगना ग्राम का लिखा गया नाम		विवरण रकबा	
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	उन्नाव	हुड्डा	टिकरी पदमरा	50	0-0-10
				49	1-9-10
				48	0-7-4
				47	0-17-0
				45	0-18-0
				42	0-0-15
				36	0-4-11
				89	1-8-0
				24	0-3-4
				91	0-4-4
				92	0-0-16
				23	0-9-10
				22	0-5-16
				20	0-1-15
				18	0-13-5
				17	0-10-10
				16	0-4-0
				15	0-12-3
				14	0-7-0
				8	3-11-16
				9	0-8-9
				97	0-8-9
				139	0-12-12
				141	0-3-10

[सं. 14016 / 13/84 - जी पी]

New Delhi, the 24th April, 1985

S.O. 1980.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3467 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances

## SCHEDULE

## Hajira Barielly Jagdishpur Pipe line Project

Distt :	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area	Required
1	2	3	4	5	6	
Unnao	Unnao	Hadha	Tikri			
			Padmara	50	0	0 10
				49	1	9 10
				48	0	7 4
				47	0	17 0
				45	0	18 0
				42	0	0 15
				36	0	4 11
				89	1	8 0
				24	0	3 4
				91	0	4 4
				92	0	0 16
				23	0	9 10
				22	0	5 16
				20	0	1 15
				18	0	13 5
				17	0	10 10
				16	0	4 0
				15	0	12 3
				14	0	7 0
				8	3	11 16
				9	0	8 9
				97	0	8 9
				139	0	12 12
				141	0	3 10

[No. O-14016/13/84-GP]

का. आ. 1981.—यत:पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4108 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्टें दे दी हैं।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लियागया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
कानपुर शहर	कानपुर शहर	कानपुर शहर	सजारी	14	0-4-18
				22	1-4-4
				23	0-6-9
				24	0-1-0
				27/3	2-6-18
				29	0-0-10
				86	0-2-12
				90	0-11-18
				91	0-12-7
				92	0-4-16
				94	0-2-8
				97	0-1-12
				98	0-9-16
				99	0-2-0
				100	0-2-0
				101	0-2-8
				102	0-0-16
				103	1-1-12
				104	0-11-14
				105	0-7-1
				106/7	0-12-1
				106/14	2-10-0
				134	0-6-16
				148	0-4-4
				149	0-12-4
				150	0-15-6

1	2	3	4	5	6
				151	0-12-12
				152	1-4-3
				168	0-1-0
				169	0-2-12
				170	0-0-18
				171	0-5-0
				172	0-2-8
				173	0-1-15
				174	0-6-0
				175	0-2-8
				180	0-0-10
				181	0-2-5
				218	0-0-16
				219	0-7-0
				220	0-5-11
				221	0-12-3
				222	0-2-0
				224	0-3-12
				227	0-0-12
				228	0-6-0
				229	0-6-14
				230	0-0-5
				233	0-3-0
				246	0-2-8
				247	0-10-0
				248	0-0-8
				249	0-4-0
				250	0-2-12
				305	0-1-0
				306	1-5-0

८ (सं. आ०-१४०१६/६/८४ — जी. पी.)

S.O. 1981.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4108 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE						
Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project						
Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired	
1	2	3	4	5	6	
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Sajari	14	0	4 18
				22	1	1 4
				23	0	6 9
				24	0	1 0
				27/3	2	6 18
				29	0	0 10
				86	0	2 12
				90	0	11 18
				91	0	12 7
				92	0	4 16
				94	0	2 8
				97	0	1 12
				98	0	9 16
				99	0	2 0
				100	0	2 0
				101	0	2 8
				102	0	0 16
				103	1	1 12
				104	0	11 14
				105	0	7 1
				106/7	0	12 1
				106/14	2	10 0
				134	0	6 16
				148	0	4 4
				149	0	12 4
				150	0	15 6
				151	0	12 12
				152	1	4 3
				168	0	1 0
				169	0	2 12
				170	0	0 18
				171	0	5 0
				172	0	2 8
				173	0	1 15
				174	0	6 0
				175	0	2 8
				180	0	0 10
				181	0	2 5
				218	0	0 16
				219	0	7 0
				220	0	5 11
				221	0	12 3
				222	0	2 2
				224	0	3 12
				227	0	0 12
				228	0	6 0
				229	0	6 14
				230	0	0 5
				233	0	3 0
				246	0	2 8
				247	0	10 0
				248	0	0 8
				249	0	4 0
				250	0	2 12
				305	0	1 0
				306	1	5 0

का. आ. 1982.-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3463 तारीख 31-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीश पुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का लिया गया नाम	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
रायबरेली	मोहर	सेमराता	कक्केपुर		
	गंज			139	0-3-8
				151	0-0-1
				153	0-1-0
				154	0-16-6
				155	1-8-15
				159	0-5-5
				165	0-0-17
				166	1-7-6
				167	0-0-4
				168	1-1-1
				169	0-0-8
				187	0-3-8

1	2	3	4	5	6
				188	0-8-2
				190	0-7-10
				191	0-16-0
				192	0-2-15
				193	0-1-15
				241	0-2-14
				242	0-5-3
				243	0-9-5
				244	0-0-4
				192/273	0-2-15
				57	0-12-6
				59	0-7-0
				60	0-6-8
				56	0-15-10
				185	0-1-10

[सं. O-14016/9/84-जी पी]

S.O. 1982 -Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3463 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Rae-Bareilly	Mohar-Ganj	Semrauta	Kakkey Pur	139	0 3 8
				151	0 0 1
				153	0 1 0
				154	0 16 6
				155	1 8 15
				159	0 5 5
				165	0 0 17
				166	1 7 6

1	2	3	4	5	6
		167	0	0	4
		168	1	1	1
		169	0	0	6
		187	0	3	8
		188	0	8	2
		190	0	7	10
		191	0	16	0
		192	0	2	15
		193	0	1	15
		241	0	2	14
		242	0	5	3
		243	0	9	5
		244	0	0	4
		192/273	0	2	15
		57	0	12	6
		59	0	7	0
		60	0	6	8
		56	0	15	10
		185	0	1	10

[No. O—14016/9/84—GP]

का. आ. 1983—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3464 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची					
हजिरा बरेली जगदीश पुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट					
जिला	तहसील	परगना	ग्रामा का नाम	का लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
रायबरेली महाराज- सेमरीता गंगापुर					
	गंज			66	0-0-5
				68	0-7-0
				69	0-8-10
				70	0-3-0
				71	0-5-10
				72	0-1-5
				75	0-5-0
				76	0-0-15
				102	0-3-10
				107	0-5-5
				108	1-3-0

[सं. 14016 / 10 / 84-जी पी]

S.O. 1983.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3464 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tahsil	Pargana Village	Plot No.	Area Acquired		
1	2	3	4	5	6	
Rae-Bareilly	Maharaj Ganj	Semra-uta	Ganga-pur	66	0	0
				68	0	7
				69	0	8
				70	0	3

5	6
71	0 5 10
72	0 1 5
75	0 5 0
76	0 0 15
102	0 3 10
107	0 5 5
108	1 3 0

[No. O-14016/10/84—GP]

का. आ. 1984—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3469 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाईप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकारण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हार्जिरा बरेली जगदीशपुर पाईप लाईन प्रोजेक्ट।

तहसील	परगना	ग्रामीक नाम	लिया गया	विवरण
1	2	3	4	5
रायबरेली	महाराज गंज	सेमरौला जमराबा	655	0-9-0
			656	0-7-10
			657	0-16-10
			662	0-1-7
			765	0-1-10
			766	0-7-0

767	0-12-10
769	0-5-15
1723	0-11-0
1724	0-2-0
1725	0-6-4
1726	0-1-10
1727	0-0-10
1728	0-6-0
1729	0-9-10
1738	0-15-10
1739	0-7-12
1747	0-4-10
1748	0-11-0
1749	0-11-10
1750	0-12-00
1755	0-18-10
1756	0-4-10
1764	0-14-5
1793	0-5-5
1794	0-2-0
1797	0-3-0
1798	0-7-5
1799	0-8-0
1800	0-6-0
1801	0-7-10
1802	0-2-0
1829	0-6-10
1830	0-8-0
1831	0-5-10
1832	0-16-0
1833	0-5-0
1834	0-13-0
1867	0-7-0
1869	0-7-0
1871	0-1-10
1872	0-8-0
1880	0-9-10
1881	0-11-10
1887	0-9-10
1888	0-3-0
1889	0-9-1
1890	0-1-15
1891	0-1-10
1893	0-5-10
1895	0-2-10
1899	0-7-0
1900	0-3-0

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
				1902	0-1-10					662	0-1-7
				1904	0-5-10					765	0-1-10
				1905	0-13-0					766	0-7-0
				1907	0-1-10					767	0-12-10
				1908	0-12-10					769	0-5-15
				1910	0-2-5					1723	0-11-0
				1914	0-10-10					1724	0-2-0
				1915	0-0-10					1725	0-6-4
				1916	0-8-10					1726	0-18-10
				1917	0-3-15					1727	0-0-10
				1919	0-1-10					1728	
				1928	0-4-10					1729	0-9-10
				1929	0-8-0					1738	0-15-10
				1931	0-2-10					1739	0-7-12
				1932	0-0-13					1747	0-4-10
				1933	0-11-10					1748	0-11-0
				1934	0-1-2					1749	0-11-10
				1792	0-0-2					1750	0-12-0
				1962	0-1-1 <sup>9</sup>					1755	0-18-10
				1866	0-0-2					1756	0-4-10
				1722	0-1-0					1764	0-14-5

[N. O.—14016/15/84-श्री श्री]

S.O. 1984.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3469 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

Hajira : Bareilly Jodeshpur Pipeline Project.

Dist.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Rae Bareilly	Maharaj Ganj	Semāruta	Jamunawan	655	0-9-0
				656	0-7-10
				657	0-16-10

1800	0-6-0
1801	0-7-10
1802	0-2-0
1829	9-6-10
1830	0-8-0
1831	0-5-10
1832	0-16-0
1833	0-5-0
1834	0-13-0
1867	0-7-0
1869	0-7-0
1871	0-1-10
1872	0-8-0
1880	0-9-10
1881	0-11-10
1887	0-9-10
1888	0-3-0
1889	0-9-10
1890	0-1-15
1891	0-1-10
1893	0-5-10
1895	0-2-10
1899	0-7-0
1900	0-3-0
1902	0-1-10
1904	0-5-10
1905	0-13-0
1907	0-1-10
1908	0-12-10
1910	0-2-5
1914	0-10-10
1915	0-0-10
1916	0-8-10
1917	0-3-15
1919	0-1-10
1928	0-4-10
1929	0-8-0
1931	0-2-10
1932	0-0-13



1	2	3	4	5	6	5	6
			1933	0-11-10		232	0-12-0
			1934	0-1-2		278	0-1-10
			1792	0 0-2		275	0-3-0
			1962	0-1-19		276	0-7-0
			1866	0-0-2		277	1-2-2
			1722	0-1 0		279	1-1-0

[No. O-141016/15/84-G.P.]

का. आ. 1985 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3470 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाईप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का लिया गया विवरण	नाम	रकबा
1	2	3	4	5	6
राय बरेली	महाराज गंज	सेमरीवां हिलहा	133	0-2-0	
			134	0-11-0	
			135	0-11-0	
			137	0-7-0	
			139	0-17-5	
			144	0-3-0	
			147	1-3-10	

## SCHEDULE

Hajira : Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Rae-Bareilly	Moharaj Ganj	Semaria	Hilha	133	0-2-0
				134	0-11-0
				135	0-11-0
				137	0-7-0
				139	0-17-5
				144	0-3-0
				147	1-3-10
				232	0-12-0
				278	0-1-0
				275	0-3-0
				276	0-7-0
				277	1-2-2
				279	1-1-0
				280	0-2-0
				284	0-0-10
				285	0 6-10
				286	0-1-0
				138	0-1-0

[No. O-141016/16/84-G.P.]

का. आ. 1986 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3458 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

#### हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाईप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना ग्रामाका	लियागया	विवरण
		नाम	रकबा	
1	2	3	4	5
रायबरेली	महाराज-गंज	हर्दोई पुरासी	110	0-10-10
			111	0-18-15
			127	0-15-0
			126	0-3-0
			134	0-11-5
			159	0-0-17
			160	0-3-0
			161	0-3-10
			162	0-2-10
			163	0-14-0
			178	0-0-2
			179	0-14-0
			181	0-5-6
			182	0-0-15

180	0-0-9
183	0-2-0
184	0-0-1
185	0-19-0
187	0-0-5
188	0-9-10
190	0-3-5
199	0-15-0
200	0-4-0
201	0-3-0
202	0-2-0
204	0-0-3
205	0-3-0
206	0-4-0
210	0-0-10
211	1-4-0
212	0-13-0
322	0-1-12
327	0-6-16
328	0-11-10
329	1-2-0
331	0-0-2
332	0-0-2
333	0-0-7
354	0-16-0
355	0-4-0
365	0-7-0
366	0-5-0
367	0-6-15
368	0-1-0
370	0-6-0
373	0-6-0
374	0-7-0
386	0-7-0
387	0-2-10
389	0-9-5
166	0-0-18
337	0-0-11
338	0-0-10

[सं. O-4016/21/84-जी. पी.]

S.O. 1986.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3458 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances

## Schedule

Hajira Bareilly Jagdishpur		Pipe Line		Project	
Distt	Tehsil	Paragna	Village	Plot No	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Rae-Barh	Moharaj Ganj	Hardoi	Purani	110	0-10-10
				111	0-18-15
				127	0-15-0
				126	0-3-0
				134	0-11-5
				159	0-0-17
				160	0-3-0
				161	0-3-10
				162	0-2-10
				163	0-14-0
				178	0-0-2
				179	0-14-0
				181	0-5-6
				182	0-0-15
				180	0-0-9
				183	0-2-0
				184	0-0-1
				185	0-19-0
				187	0-0-5
				188	0-9-10
				190	0-3-5
				199	0-15-0
				200	0-4-0
				201	0-3-0
				202	0-2-0
				204	0-0-3
				205	0-3-0
				206	0-4-0
				210	0-0-10
				211	1-4-0
				212	0-13-0
				322	0-1-12
				327	0-6-16
				328	0-11-10
				329	1-2-0
				331	0-0-7
				332	0-0-2
				333	0-0-7
				334	0-16-0
				355	0-4-0
				365	0-7-0
				366	0-5-0
				367	0-6-15
				368	0-1-0
				370	0-6-0
				373	0-6-0
				374	0-7-0
				386	0-7-0

1	2	3	4	5	6
				387	0-2-10
				389	0-9-5
				166	0-0-18
				337	0-0-11
				338	0-0-10

[No O-14016/21/84-GP]

का आ 1987 --यन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ स. 3459 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाईन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
रायबरेली	महाराज गंज	समरौली	कडरिया	1	0-0-15
				4	0-1-10
				5	0-11-0
				6	0-15-0

1	2	3	4	5	6
				31	0-1-2
				32	0-2-0
				33	0-0-9
				34	0-9-10
				35	0-17-0
				40	0-13-0
				41	0-4-16
				44	0-9-10
				48	1-6-0
				49	0-0-6
				50	0-1-1
				51	0-18-0
				52	0-1-16
				53	0-1-10

[सं. O-14016/22/84-जीपी]

S.O. 1987.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3459 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira Bareilly Jagdeshpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Rae-Bareilly	Moharj Ganj	Semrauta	Kararia	1	0-0-15
				4	0-1-10
				5	0-11-0
				6	0-15-0
				31	0-1-2
				32	0-2-0
				33	0-0-9
				34	0-9-10
				35	0-17-0

1	2	3	4	5	6
				40	0-13-0
				41	0-4-16
				44	0-9-10
				48	1-6-0
				49	0-0-6
				50	0-1-1
				51	0-18-0
				52	0-1-16
				52	0-1-10

[No. O-14016/22/84-GP]

का. आ 1988—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 3440 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के वजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटामं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटवा	और्या	और्या	करीदपुर	124	1-2 6
				126	0-0 6

1	2	3	4	5	6
				127	0-8 6
				129	1-1 5
				142	0-08
				143	0-1 6
				144	0-3 0

[सं० O-14016 / 39/84-जी.पी.]

S.O. 1988.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3440 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the Lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira Barielly Jagdeshpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Awraiya	Awraiya	Faridpur	124	1-26
				126	0-06
				127	0-86
				129	1-15
				142	0-08
				143	0-16
				144	0-30

[No. O-14016/39/84-GP]

का. आ. 1989—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. म. 3442 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् नक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में धोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा —बरेली जगदीशपुर पाइप लाईन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	औरया	औरया	भरतपुर	1	0-13
				4	0-58
				5	0-92
				7	0-03
				11	0-38
				62	0-73
				63	0-01
				64	0-01
				65	0-42
				66	0-55
				67	0-21
				68	0-03
				12	0-01
				17	0-01
				69	0-36

[सं. O-14016 / 40/ 84-जी. पी.]

S.O. 1989.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3442 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project					
Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Awraiya	Awraiya	Bharatpur	1	0-13
				4	0-58
				5	0-92
				7	0-03
				11	0-38
				62	0-73
				63	0-01
				64	0-01
				65	0-42
				66	0-55
				67	0-21
				68	0-03
				12	0-01
				17	0-01
				69	0-36

[No. O-14016/40/84-GP

का. आ. 1990:—यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 3443 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का आपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

#### हाजिरा-बरेली-जगदीश पुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्रामा	गाटा स.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	ओरया	ओरया	करबावत		
				21	0-09
				17	1-94
				42	0-24
				44	0-15
				33	0-14
				54	0-11
				65	0-03
				66	0-78
				77	0-02
				83	0-59
				82	0-01
				84	0-23
				80	0-57
				79	0-35
				90	0-07
				91	0-86
				92	0-12
				133	0-03
				134	1-44
				142	0-01
				135	0-02
				143	0-19
				131	1-22
				148	0-13
				124	0-02
				123	0-53
				120	0-24
				121	0-21

[सं. O-14016 / 45 / 84 जी पी]

S.O. 1990.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3443 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Auraiya	Auraiya	Kakha-wat	21	0-09
				17	1-94
				42	0-24
				44	0-15
				33	0-14
				54	0-11
				65	0-03
				66	0-78
				77	0-02
				83	0-59
				82	0-01
				84	0-23
				80	0-57
				79	0-35
				90	0-07
				91	0-86
				92	0-12
				133	0-03
				134	1-44
				142	0-01
				135	0-02
				143	0-19
				131	1-22
				148	0-13
				124	0-02
				123	1-53
				120	0-24
				121	0-21

[No O-14016/45/84-GP]

का. आ. 1991:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कां. आ. सं. 3747 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के वजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

##### हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	औरैया	ओरैया	शाहबदिया	49	0-01
				48	1-17
				46	0-48
				28	0-01
				29	0-35
				30	0-40
				31	0-15
				34	0-01
				35	0-01
				22	1-29
				104	0-01
				105	0-01
				106	0-10
				21	1-21
				114	0-01
हाजिरा	औरैया	ओरैया	शाहबदिया	115	0-14
				20	0-05
				19	0-01
				118	0-01

1	2	3	4	5	6
				119	0-06
				120	1-09
				121	0-53
				122	0-18
				113	0-01

[सं. O-14016/81/84-जी पी]

S.O. 1991.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3747 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Paragana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Awariya	Awariya	Shah-badiya	49	0-01
				48	1-17
				46	0-48
				28	0-01
				29	0-35
				30	0-40
				31	0-15
				34	0-01
				35	0-01
				22	1-29
				104	0-01
				105	0-01
				106	0-10
				21	1-21
				114	0-01
				115	0-14
				20	0-05
				19	0-01
				118	0-01
				119	0-06
				120	1-09
				121	0-53
				122	0-18
				113	0-01

[No. O-14016/81/84-GP]

क. आ. 1992.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3750 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
इटावा	औरिया	औरिया	ब्रह्मपुर	6	1-55
				16	0-07
				36	0-12
				39	0-45
				51	0-10
				52	0-31
				53	0-02
				54	0-51

[सं. O-14016/84/84-जी.पी.]

S.O. 1992.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3750 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;



And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Etawah	Awariya	Awariya	Brahmpur	6	1-55
				16	0-07
				36	0-12
				39	0-45
				51	0-10
				52	0-31
				53	0-02
				54	0-51

[No. O-14016/84/84-GP]

का. आ. 1993:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 3481 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी

बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

##### हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा नं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	उन्नाव	हरहा	हरहा	548	0-13-13
				549	0-1-4
				551	0-4-11
				552	0-3-12
				553	0-1-4
				555	2-11-0
				572	1-4-18
				576	0-0-12
				578	0-4-7
				580	0-18-10
				581	1-16-0
				614	0-3-12
				615	1-5-0
				621	0-6-10
				622	0-1-16
				623	0-10-12
				639	1-2-7
				640	0-6-10
				643	0-1-8
				644	1-1-5
				645	0-0-5
				646	0-0-10
				650	0-11-15
				655	0-0-5
				658	0-10-5
				659	0-2-10
				661	0-18-0
				662	0-8-0
				667	0-3-10
				672	0-18-6
				673	0-3-15
				675	1-0-8
				685	0-19-16
				686	1-2-16
				689	0-2-14
				728	0-3-0
				729	0-16-0
				731	0-1-0
				745	1-5-16
				746	0-4-1

1	2	3	4	5	6
				749	0-2-15
				750	0-14-0
				1288	0-7-3
				1289	0-17-2
				1295	0-10-16
				1296	0-3-0
				1298	0-2-8
				1299	0-12-0
				1303	0-7-10
				1304	0-2-5
				1305	0-18-0
				1308	0-9-12
				1357	0-1-10
				1358	0-3-15
				1359	1-0-0
				1360	0-12-0
				1361	0-3-10
				1362	1-3-2
				1365	1-0-8
				1366	0-4-1
				624	0-2-8
				550	1-3-0
				579	0-1-15
				647	0-0-10

[सं. O-14016/93/84-जी.पी.]

S.O. 1993.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3481 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE					
Hajira	Bareilly	Jagdishpur	Pipe Line	Project	
Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1 *	2	3	4	5	6
Unnao	Unnao	Harha	Harha	548	0-13-13
				549	0-1-4
				551	0-4-11
				552	0-3-12
				553	0-1-4
				555	2-11-0
				572	1-4-1 8
				576	0-0-12
				578	0-4-7
				580	0-18-10
				581	1-16-0
				614	0-3-12
				615	1-5-0
				621	0-6-10
				622	0-1-16
				623	0-10-12
				639	1-2-7
				640	0-6-10
				643	0-1-8
				644	1-1-5
				645	0-0-5
				646	0-0-10
				650	0-11-15
				655	0-0-5
				658	0-10-5
				659	0-2-10
				661	0-18-0
				662	0-8-0
				667	0-3-10
				672	0-18-6
				673	0-3-15
				675	1-0-8
				685	0-19-16
				686	1-2-16
				689	0-2-14
				728	0-3-0
				729	0-16-0
				731	0-1-0
				745	1-5-16
				746	0-4-1
				749	0-2-15
				750	0-14-0
				1288	0-7-3
				1289	0-17-2
				1295	0-10-16
				1296	0-3-0
				1298	0-2-8
				1299	0-12-0
				1303	0-7-10
				1304	0-2-5
				1305	0-18-0
				1308	0-9-12
				1357	0-1-10
				1358	0-3-15
				1359	1-0-0
				1360	0-12-0
				1361	0-3-10
				1362	1-3-2
				1365	1-0-8
				1366	0-4-1
				624	0-2-8
				550	1-3-0
				579	0-1-15
				647	0-0-10

[No. O-14016/93/84-GP]

का. आ. 1994. यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन की भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4106 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
ग्राम कालाखूट तहसील आबुआ जिला-आबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची		
अनु०	खसरा नं. 1	उपयोग अधिकार
क्र.		अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3
1.	55	0-129
2.	57	0-841
3.	221	0-065
4.	222	0-129
5.	223	0-089
6.	224	0-275
7.	234	0-890
8.	235	0-987
9.	235	0-202
10.	316	0-210

1	2	3
11.	317/3	0-462
12.	319	0-849
13.	320	0-040
14.	300	0-040
योग कुल क्षेत्रफल :		5-208

[सं. O-14016/203/84-जी.पी.]

S.O. 1994.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4166 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT  
Village : Kalakhot Tehsil : Zabua Distt. : Zabua  
SCHEDULE

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	55	0.129
2.	27	0.841
3.	221	0.065
4.	222	0.129
5.	223	0.089
6.	224	0.275
7.	234	0.890
8.	235	0.987
9.	236	0.202
10.	316	0.210
11.	317/1	0.462
12.	319	0.849
13.	320	0.040
14.	300	0.040
Total Area		5.208

[No. O-14016/203/84-G.P.]

का. आ. 1995. यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3719 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट  
ग्राम रूपारेल तहसील प्रैतलाव जिला—भाबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्र.	खसरा नं.	अनुसूची उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	2	3
1.	2	0-235
	7	0-223
2.	3	0-235
3.	1	0-117
4.	4	0-008
5.	8	0-016
योग कुल क्षेत्रफल :		0-834

[सं. O-14016/208/84-जी.पी.]

S.O. 1995.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3719 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Ruparel Tehsil : Petlawad Distt. : Zabua  
SCHEDULE

Sl. No.	Surve. No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hecture
1.	2	0.235
2.	7	0.223
	3	0.235
3.	1	0.117
4.	4	0.008
5.	8	0.016
Total Area		0.834

[No. O-14016/208/84-GP]

का. आ. 1996—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का. आ. सं. 3899 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा बरेली—जगदीशपुर—गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लॉट नम्बर	रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	भैसई कोयल	885	0-5-0	
				886	0-3-6	
				887	0-3-6	
				888	1-9-0	
				890	0-0-5	
				891	0-11-8	
				895	0-0-5	
				905	0-19-4	
				926	0-0-16	
				927	0-3-10	
				928	0-6-0	
				932	0-10-0	
				929	0-8-7	
				1071	0-13-16	
				1072	0-0-12	
				1073	0-12-12	
				1074	0-1-15	
				1075	0-3-0	
				1076	0-5-0	
				1978	0-0-16	
				1079	0-8-8	
				1085	0-6-0	
				1086	0-3-10	
				1159	1-0-0	
				1176	0-10-10	
				1177	0-5-2	
				1178	0-3-0	
				1179	0-2-0	
				1181	0-10-10	
				1183	0-0-10	
				1184	0-0-15	
				1185	0-7-4	
				1193	0-0-16	
				930	0-3-0	
				1087	0-15-0	
				1088	0-0-10	

[सं. O-14016/237/84-जी.पी.]

S.O. 1996.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3899 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user

in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hazira-Bareilly-Sagdishpur Gas pipeline Project.

Dist.	Tehsil	Pargana	Village No.	Plot No.	Acquired Area
1	2	3	4		6
Unnao	Unnao	Harha	Bhaisal	885	0-5-0
			Kocl	886	0-3-6
				887	0-3-6
				888	1-9-0
				890	0-0-5
				891	0-11-8
				895	0-0-5
				905	0-19-4
				926	0-0-16
				927	0-3-10
				928	0-6-0
				932	0-10-0
				929	0-8-7
				1071	0-13-16
				1072	0-0-12
				1073	0-12-12
				1074	0-1-15
				1075	0-3-0
				1076	0-5-0
				1078	0-0-16
				1079	0-8-8
				1085	0-6-0
				1086	0-3-10
				1159	1-0-0
				1176	0-10-10
				1177	0-5-2
				1178	0-3-0
				1179	0-2-0
				1181	0-10-10
				1183	0-0-10
				1184	0-0-15
				1185	0-7-4
				1193	0-0-16
				930	0-3-0
				1087	0-15-0
				1088	0-0-10

[No O-14016/237/84-GP]

का.आ. 1997—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 3905 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को विछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने का समय होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम भमरदा तहसील झाबुआ जिला-झाबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

#### अनुसूची

अनु क्रम 1 खसरा नं. उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

1	2	3
1.	146	0.010
2.	150/1	0.486
3.	150/3	0.121
4.	154	0.162
5.	150/2	0.283
6.	151	0.040
7.	149	0.040
8.	127	0.056
9.	147	0.324
10.	145/2	0.081
11.	145/1	0.040
12.	145/4	0.262
13.	145/3	0.324
14.	145/162	0.040
15.	155	0.008
16.	157	0.024

योग :—कुल क्षेत्रफल 2.301

[सं. O-14016/243/84-जीपी]

S.O. 1997.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3905 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bhamarda Tehsil : Zabua Distt : Zabua

#### SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	146	0.010
2.	150/1	0.486
3.	150/3	0.121
4.	154	0.162
5.	150/2	0.283
6.	151	0.040
7.	149	0.040
8.	127	0.056
9.	147	0.324
10.	145/2	0.081
11.	145/1	0.040
12.	145/4	0.262
13.	145/3	0.324
14.	145/162	0.040
15.	155	0.008
16.	157	0.024
Total Area		2.301

[No. O-14016/243/84—GP]

का.आ. 1998.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3916 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम.सजेलिया सहसोल-पेटलावद जिला:झाबुआ राज्य (मध्यप्रदेश)

#### अनुसूची

अनुक्रम	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	95	0.005
2.	94/1	0.097
3.	125	0.093
4.	85	0.032
5.	93	0.413
6.	127	0.065
7.	86	0.020
8.	87	0.008
9.	96	0.093
10.	71	0.291
11.	72	0.218
12.	73	0.024
13.	74	0.004
14.	75	0.319
15.	140	0.142
16.	77/1	0.020
17.	78/1	0.008
18.	77/2	0.032
19.	78/2	0.024
20.	77/3	0.024
21.	78/3	0.065
22.	94/2	0.004
23.	70	0.016
24.	126	0.214

1	2	3
25.	128	0.412
26.	134	0.016
27.	144	0.032
28.	147	0.004
29.	40/6	0.137
30.	151	0.097
31.	152	0.263
32.	153	0.010
योग कुल क्षेत्रफल:—		3.202

[सं. ओ/14016/254/84-जी पी]

S.O. 1998.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3916 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Sajeliya Tehsil : Petlawad Distt : Jabua

#### SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	95	0.005
2.	94/1	0.097
3.	125	0.093
4.	85	0.032
5.	93	0.413
6.	127	0.065
7.	86	0.020
8.	87	0.008
9.	96	0.093
10.	71	0.291
11.	72	0.218
12.	73	0.024
13.	74	0.004
14.	75	0.319
15.	140	0.142
16.	77/1	0.020
17.	78/1	0.008
18.	77/2	0.032

1	2	3
19. 78/2		0.024
20. 78/1		0.024
21. 78/3		0.065
22. 9/42		0.004
23. 70		0.016
24. 126		0.214
25. 128		0.412
26. 134		0.016
27. 144		0.032
28. 147		0.004
		0.137
30. 151		0.097
31. 152		0.263
32. 153		0.010
Total Area		3.202

[No. O—14016/254/84—GP]

का.भा. 1999.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय अधिसूचना का. आ. सं. 3919 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकारण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख

का।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम गब्बापाडा तहसील पेटलावद जिला—झारखण्ड राज्य मध्यप्रदेश

अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	59	0.032
2.	61	0.640
3.	55	0.291
4.	53	0.500
5.	56	0.065
6.	54	0.005
7.	57	0.025
योग कुल क्षेत्रफल :—		1.558

[सं. ओ—4016/257/84—जी पी]

S.O. 1999.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3919 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Gabba Pada Tehsil : Petlawad Distt. : Zabua

## SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	59	0.032
2.	61	0.640
3.	55	0.291
4.	53	0.500
5.	56	0.065
6.	54	0.005
7.	57	0.025
Total Area		1.558

[No. O—14016/257/84—GP]



कॉ.ओ. 2000 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 3938 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम लालपुरा तहसील पेलवाड जिला भाबूभा राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनुसूची		
अनुक्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	40	0.117
2.	67	0.344
3.	68	0.170
4.	69	0.170
5.	70	0.231
6.	71	0.121
7.	77	0.032
8.	94	0.817
9.	96	0.093
10.	98	0.397
11.	161	0.024
12.	162	0.085

1	2	3
13.	163	0.142
14.	164	0.486
15.	169	0.174
16.	170	0.024
17.	171	0.809
18.	172	0.024
19.	149/1	0.174
20.	176	0.158
21.	97	0.008
योग कुल क्षेत्रफल —		4.600

[स. अं.—14016/266/84—जीपी]

S.O. 2000.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3928 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Lalpura Tehsil : Petlawad Distt. : Zabua

#### SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	40	0.117
2.	67	0.344
3.	68	0.170
4.	69	0.170
5.	70	0.231
6.	71	0.121
7.	77	0.032
8.	94	0.817
9.	96	0.093
10.	98	0.397
11.	161	0.024
12.	162	0.085
13.	163	0.142
14.	164	0.486

1	2	3
15.	169	0.174
16.	170	0.024
17.	171	0.809
18.	172	0.024
19.	149/1	0.174
20.	176	0.158
21.	97	0.008
Total Area		4.55

[N.O. 14012/286/84—G.P.]

का. भा. — 2001 : यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. स. 3930 तारीख 24.11.84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन का इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम झाबसिया तहसील पेटलवाड जिला— झाबझा राज्य (मध्य प्रदेश)

#### अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	391	0.364
2.	396	0.283
3.	390	0.121
4.	395	0.194
5.	414	0.032

1	2	3
6.	401/1	1.720
7.	392	0.016
योग कुल क्षेत्रफल		2.730

[स. अ 14016/268/84—जीपी]

S.O. 2001.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy, Department of Petroleum S.O. 3930 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (30 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section 4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### HBI GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Zavalia Tehsil : Petlawad Distt. : Zabu

#### SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1	2	3
1.	391	0.364
2.	396	0.283
3.	390	0.121
4.	395	0.194
5.	414	0.032
6.	401/1	1.720
7.	392	0.016
Total Area		2.730

[No. O—14016/268/84—GP]

का. भा. 2002 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. स. 3935 तारीख 24.11.84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग

के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम बोडायता तहसील पेटलावद जिला—झारखण्ड राज्य (मध्य-प्रदेश)

#### अनुसूची

अनुक्र.	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	6	0.340
2.	4	0.004
3.	8	0.194
4.	14	0.036
5.	15	0.182
6.	16	0.178
7.	50	0.223
8.	51	0.142
योग कुल क्षेत्रफल :—		1.299

[मं. अं-14016/278/84-जीपी]

S.O. 2002.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3935 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 5 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bodayata Tehsil : Petlawad Distt. : Zabua

#### SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1.	6	0.340
2.	4	0.004
3.	8	0.194
4.	14	0.036
5.	15	0.182
6.	16	0.178
7.	50	0.223
8.	51	0.142
Total Area		1.299

[No. O-14016/278/84-GP]

का. आ. 2003:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3944 तारीख 24.11.84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची

में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उम धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन के इस तारीख को निहा होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : बेगनबरडी : तहसील : पेटलावद : जिला साबुआ. राज्य  
(मध्य प्रदेश)

#### अनुसूची

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग क्षेत्र (हेक्टर्स में)	अधिकार अर्ज का क्षेत्र (हेक्टर्स में)
1	2	3	
1.	518/1	0.008	
2.	520	0.218	
3.	521/1	0.073	
4.	521/2	0.073	
5.	522/1	0.049	
6.	523/1	0.008	
7.	522/2	0.129	
8.	527	0.235	
9.	528	0.057	
10.	529	0.097	
11.	530	0.081	
12.	531	0.097	
13.	504/1	0.381	
14.	561	0.235	
15.	560	0.009	
16.	562	0.041	
17.	564	0.089	
18.	568	0.032	
19.	572/2	0.057	
20.	567	0.226	
21.	569	0.202	
22.	570	0.004	
23.	571	0.145	
24.	573	0.291	
25.	574/1	0.178	
कुल क्षेत्रफल		3.015	

[सं. ओ—14016/287/84-ज.प.]

S.O. 2003.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3944 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act,

1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has, under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Began Baradi, Tehsil : Petlawad Dist. : Zabua  
SCHEDULE

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	518/1	0.008
2.	520	0.218
3.	521/1	0.073
4.	521/2	0.073
5.	522/1	0.049
6.	523/1	0.008
7.	522/2	0.129
8.	527	0.235
9.	528	0.057
10.	529	0.097
11.	530	0.081
12.	531	0.097
13.	504/1	0.381
14.	561	0.235
15.	560	0.009
16.	562	0.041
17.	564	0.089
18.	568	0.032
19.	572/2	0.057
20.	567	0.226
21.	569	0.202
22.	570	0.004
23.	571	0.145
24.	573	0.291
25.	574/1	0.178
Total Area		3.015

[No. O-14016/287/84-GP]

का.धा 2004—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, (1962 का 50 का) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को अधिसूचना सं. ओ. सं. 4051 तारीख 1/12/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

#### हाजिरा बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	सिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	बति-गांव	1266	0-13-0	
				1270	0-2-0	
				1271	0-14-0	
				1272	0-1-10	
				1275	0-4-0	
				1275	0-1-10	
				1275	0-1-10	
				1276	0-0-10	
				1277	0-10-10	
				1279	0-1-0	
				1283	1-1-0	
				1284	0-4-0	
				1285	0-2-0	
				1287	0-8-0	
				1288	0-4-0	
				1289	0-1-0	
				1290	1-16-0	
				1300	0-2-0	
				1302	2-14-10	
				1304	1-4-0	
				1305	1-0-0	
				1305	0-6-0	
				1305	0-18-0	
				1306	0-1-0	
				1307	0-15-0	
				1308	0-5-0	
				1308	1-0-0	
				1309	0-3-0	
				1309	0-4-0	
				1310	0-5-0	
				1311	0-1-0	

1	2	3	4	5	6	7
				1311	0-1-0	
				1427	0-8-0	
				1502	0-6-0	
				1503	0-3-0	
				1536/1	1-15-0	
				1536/3	0-13-0	
				1540	0-0-10	
				1541	0-4-0	
				1542	0-1-0	
				1544	1-0-0	
				1545	0-5-0	
				1548	0-4-0	
				1549	0-1-10	
				1556	0-9-0	
				1560	0-1-10	
				1564	0-2-0	
				1564	0-2-0	
				1565	0-10-0	
				1566	0-4-0	
				1567	0-5-0	
				1570	1-16-0	
				1570	0-5-0	
				1570	0-17-0	
				1571/1	0-10-0	
				1571/2	0-1-0	
				1571/3	0-2-0	
				1571/4	0-9-0	
				1571/5	0-9-0	
				1571/6	0-4-0	
				1295	0-6-10	
				1551	0-1-0	

[सं. श्री-14016/289/84-जी पी]

S.O. 2004.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4051 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances,

**SCHEDULE**  
**Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe line Project**

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Unnao	Purva	Purva	Vanigaon	1266	0-13-0
				1270	0-2-0
				1271	0-14-0
				1272	0-1-10
				1275	0-4-0
				1275	0-1-10
				1275	0-1-10
				1276	0-0-10
				1277	0-10-10
				1279	0-1-0
				1283	1-1-0
				1284	0-4-0
				1285	0-2-0
				1287	0-8-0
				1288	0-4-0
				1289	0-1-0
				1290	1-16-0
				1300 Ka	0-2-0
				1302 Ka	2-14-10
				1304	1-4-0
				1305 Ka	1-0-0
				1305 Ga	0-6-0
				1305 Na	0-18-0
				1306	0-1-0
				1307 Gha	0-15-0
				1308 Gha	0-5-0
				1308 Ga	1-0-0
				1309 Ka	0-3-0
				1309 Kha	0-4-0
				1310	0-5-0
				1311 Ka	0-1-0
				1311 Kha	0-1-0
				1427	0-8-0
				1502	0-6-0
				1503	0-3-0
				1536/1	1-15-0
				1536/3	0-13-0
				1540	0-0-10
				1541	0-4-0
				1542	0-1-0
				1544	1-0-0
				1545	0-5-0
				1548	0-4-0
				1549	0-1-10
				1556	0-9-0
				1560	0-1-10
				1564 Ka	0-2-0
				1564 Kha	0-2-0
				1565	0-10-0
				1566	0-4-0
				1567	0-5-0
				1570 Gha	1-16-0
				1570 Ga	0-5-0
				1570 Jha	0-17-0
				1571/1	0-10-0
				1571/2	0-1-0
				1571/3	0-2-0
				1571/4	0-9-0
				1571/5	0-9-0
				1571/6	0-4-0
				1295	0-6-10
				1551	0-1-0

[No. O-14016/289/84-GP]

का. भा. 2005 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 4053 तारीख 1/12/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

**अनुसूची**

**हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट**

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
अजमेर	पुरवा	भदनांग	978	0-0-5	
			977	0-3-6	
			958/4	1-12-5	
			964	0-3-6	
			967	0-5-11	
			956/3	0-18-18	
			968	0-7-19	
			969	0-2-16	
			914 एम	0-5-5	
			912	0-1-0	
			913/2	0-1-13	
			911/1	0-5-8	
			924	0-1-12	
			927	0-1-0	
			929	0-1-10	
			910	0-7-0	
			909	0-3-0	
			903	0-4-16	
			930	0-4-0	
			915/1	0-9-12	
			885	0-0-12	
			702/213	1-3-10	

1	2	3	4	5	6
				703	0-13-19
				716	0-7-4
				722	0-1-0
				717	0-1-19
				715	0-4-16
				736	0-4-10
				735 एम	0-8-0
				734	0-11-10
				731	0-8-0
				727	0-0-6
				740	1-6-9
				741	0-2-10
				743	0-2-19
				453	0-8-0
				448	0-10-10
				449	0-18-19
				445	0-2-0
				446	0-4-0
				4 0	0-0-5
				444	0-12-0
				443	0-5-15
				441	0-1-6
				439	0-1-15
				438	0-2-10
				442	0-3-8
				429	0-8-0
				428	0-6-5
				427	0-1-19
				426	0-6-10
				425	0-2-10
				1130/2	0-12-10
				1131	0-19-16
				1132	0-11-19
				1133	0-0-7
				1136	0-17-6
				1182	0-3-10
				1237/4	1-8-0
				1244	2-6-0
				1246	0-1-0
				1268	0-0-10
				1269	0-1-7
				1270	0-2-10
				1274	0-16-0
				1275	0-0-16
				1277	0-12-10
				1284	0-18-0
				1285	0-2-0
				1287/1	0-12-0
				1287/2	0-5-0
				958/2	0-11-6
				958/3	0-3-0
				908	0-1-15
				907	0-1-9
				886	0-0-10
				887	0-0-4

1	2	3	4	5	5
				854	1-18-10
				742	0-0-19
				454	0-4-0
				440	0-2-16
				1286	0-1-0
				1271	0-2-10

[सं. प्रो-14016/291/84-जी. प्रो.]

S.O. 2005.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4053 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira—Baricilly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Unnao	Purua	Purua	Bhadnag	978	0-0-5
				977	0-3-6
				958	1-12-5
				964	0-3-6
				967	0-5-11
				956	0-18-18
				968	0-7-19
				969	0-2-16
				914 M	0-5-5
				912	0-1-0
				913	0-1-13
				911	0-5-8
				924	0-1-12
				927	0-1-0
				929	0-1-10
				910	0-7-0
				909	0-3-0
				903	0-4-16
				930	0-4-0
				915	0-9-12
				885	0-0-12
				702	1-3-10
				703	0-13-19
				716	0-7-4

1	2	3	4	5	6
				722	0-1-0
				717	0-1-19
				715	0-4-16
				736	0-4-10
				735M	0-8-0
				734	0-11-10
				731	0-6-0
				727	0-0-6
				740	1-6-9
				741	0-2-10
				734	0-2-19
				453	0-8-0
				448	0-10-10
				449	0-18-19
				445	0-2-0
				446	0-4-0
				450	0-0-5
				444	0-12-0
				443	0-5-16
				441	0-1-6
				439	0-1-15
				438	0-2-10
				442	0-3-8
				429	0-8-0
				428	0-6-5
				427	0-1-19
				426	0-6-10
				425	0-2-16
				1130/2	0-12-10
				1131	0-19-16
				1132	0-11-19
				1133	0-0-7
				1136	0-17-6
				1182	0-3-10
				1237/4	1-8-0
				1244	2-6-0
				1246	0-1-0
				1268	0-0-10
				1269	0-1-7
				1270	0-2-10
				1274	0-16-0
				1275	0-0-16
				1277	0-12-10
				1284	0-18-0
				1285	0-2-0
				1287	0-12-0
				1287	0-5-0
				958	0-11-6
				958	0-3-0
				908	0-1-15
				907	0-1-9
				886	0-0-10
				887	0-0-4
				854	1-18-10
				742	0-0-19
				454	0-4-0
				440	0-2-16
				1286	0-1-0
				2171	0-2-10

[No. O-14016/291/84-GP]

लियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ. सं. 4054 तारीख 1/12/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार की पाहप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्थात् सरकार को रिपोर्ट दे वा है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा इस प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाहपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन करती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय नैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाहप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया रकबा	विबरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	मोरावा	मोरावा	8 एम	0-10-0	
				8 एम	0-1-0	
				33/2	0-1-0	
				34	1-7-0	
				59	0-13-16	
				62	0-1-10	
				63	0-10-4	
				70	0-8-8	
				71	1-3-8	
				75	0-8-10	
				76	0-13-10	
				77	0-1-5	
				80	0-12-0	
				84	0-15-0	
				85	0-5-0	
				86	0-8-10	
				208	0-1-0	
				209	1-2-0	
				260	0-5-10	
				262	0-14-6	
				263	0-0-16	
				264	0-10-10	
				2631	1-4-0	
				2632	0-19-14	
				2633	0-0-14	
				2641	1-1-16	
				2643	0-19-0	

का. आ. 2006 :- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाहपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रो-



1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
				2644/2	0-2-0						80	0-12-0
				2646	0-0-6						84	0-15-0
				2647	0-14-8						85	0-5-0
				2648	0-2-2						86	0-6-10
				2649	0-10-16						208	0-1-0
				2650	0-15-0						209	1-2-0
				2651	1-2-15						260	0-5-10
				2652	0-3-0						262	0-14-6
				2653	0-16-5						263	0-0-16
				2658	0-2-4						264	0-10-10
				2659	0-10-4						2631	1-4-0
				2660	0-0-12						2632	0-19-14
				2661	0-11-0						2633	0-0-14
				261	0-1-10						2641	1-1-16
				265	0-0-5						2436	0-19-0
				2687	0-0-5						2644	0-2-0
											2446	0-0-6
											2647	0-14-8
											2648	0-2-2
											2649	0-10-16
											2650	0-15-0
											2651	1-2-15
											2652	0-3-0
											2653	0-16-5
											2658	0-2-4
											2659	0-10-4
											2661	0-11-0
											261	0-1-10
											265	0-0-5
											2687	0-0-5

[स. अ. 14016/2 / 84-जो. पा.]

S.O. 2006.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4054 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Hajira : Barielly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Unnao	Purva	Mauravan	Mauravan	8M	0-10-0
				8M	0-1-0
				33	0-1-0
				34	1-7-0
				59	0-13-16
				62	0-1-10
				63	0-10-4
				70	0-8-8
				71	1-3-8
				75	0-8-10
				76	0-13-10
				77	0-1-5

[No. O-14016/293/84-GP]

का.आ. 2007 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 4061 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

##### हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	पूरवा	मौरवा	करदहा	8	0-3-2
				9	0-9-0
				68	0-8-0
				69	0-4-4
				70	0-2-8

[सं० ओ-14016/299/84-जी०पी०]

S.O. 2007.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4061 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### Hajira Barielly Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Unnao	Purva	Mauravan	Kardaha	8	0-3-2
				9	0-9-0
				68	0-8-0
				69	0-4-4
				70	0-2-8

[No. O-14016/299/84-GP]

का०आ० 2008:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 4410 तारीख 3-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हाजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य—गुजरात जिला—पंचमहाल तालुका—हालोल

गांव	सर्वे नं०	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
अराद	30	0	20	00
	29/2	0	24	00
	32/1	0	26	00
	32/2	0	20	00
	32/3	0	22	00
	32/4	0	08	00
	33/1	0	00	50
	33/2 + 3 + 4	0	48	00
	34	0	03	00
काटे ट्रेक		0	03	25
	20/1 + 2	0	38	00
	21/2	0	14	00
	19	0	24	00
	10/1	0	17	00
	10/2—A	0	23	00

[सं० ओ- 14016/375/84-जी पी]

S.O. 2008.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4410 dated 3-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ,

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances

#### SCHEDULE

Pipeline from Hazira to Baria to Jagdishpur  
State Gujarat, District Panchmahal Taluka Halol

Village	Survey	Hec- tare	Are	Cent- tare
Arad	30	0	20	00
	29/2	0	24	00
	32/1	0	26	00
	32/2	0	20	00
	32/3	0	22	00
	32/4	0	08	00
	33/1	0	00	50
	33/2—2 + 2 + 4	0	48	00
	34	0	03	00
	Cart track	0	03	25
	20/1 + 2	0	38	00
	21/2	0	14	00
	19	0	24	00
	10/1	0	17	00
	10/2-A	0	23	00

[No O-14016/375/84-GP]

का०आ० 2009.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 4395, तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था,

और यत् सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है .

और आगे यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ,

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है ,

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा ।

#### अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर	देरापुर	देरापुर	मुरी	436	0-2-0
देहात				440 घ	0-2-10
				448	0-18-0
				441	0-5-10

[सं० ओ-14016/409/84-जी पी]

S.O. 2009.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4395 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ,

And whereas the Competent Authority has under Sub section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd free from encumbrances

## SCHEDULE

Hajira—Barielly—Jagdeshpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area. Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur	Derapur	Derapur	Murra	436	0-2-0
Dekhat				440	0-2-10
				448	0-18-0
				441	0-5-10

[No. O—14016/409/84-GP]

का०आ० 2010.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 4527 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विश्वास करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर-	देरपुर	देरपुर	कुदोली	838	0-1-0
देहलत			मुडोली	839	0-8-10
				840	1-0-10

1	2	3	4	5	6
				841	0-6-0
				842	0-0-7
				843	0-6-0
				845	0-3-12
				844	0-7-0
				846	0-1-0
				882	0-6-10
				883	0-6-0
				884	0-9-0
				885	0-6-10
				887	0-0-12
				888	1-6-16
				889	0-2-4
				891	0-2-5
				893/1	0-1-5
				895/1	0-7-4
				980	1-3-8
				981	0-18-17
				892/2	0-18-17
				983	0-17-15
				890	0-7-0
				820	0-0-19
				985/1	0-14-10
				378/1	0-0-5

[सं० ओ-14016/415/84-जी पी]

S.O. 2010.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4527 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

Hajira—Barielly—Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur Dehat	Dorapur	Dorapur	Kudauli Marauli	838	0-1-0
				839	0-8-10
				840	1-0-10
				841	0-6-0
				842	0-0-7
				843	0-6-0
				845	0-3-12
				844	0-7-0
				846	0-1-0
				882	0-6-10
				883	0-6-0
				884	0-9-0
				885	0-6-10
				887	0-0-12
				888	1-6-16
				889	0-2-4
				891	0-2-5
				893/1	0-1-5
				895/1	0-7-4
				980	1-3-8
				981	0-18-17
				982/2	0-18-17
				983	0-17-15
				890	0-7-0
				870	0-0-19
				985/1	0-14-10
				378/1	0-0-5

JNo C—14016/415/84-GPJ

का०आ० 2011.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 4521 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

127 GI/85—8

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

हाजिरा—बरेली—जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर-देहात	देरापुर	देरापुर	जौरा	99	0-1-10
				100	1-2-0
				104	0-2-0
				105	0-17-14
				110	0-2-0
				113/1	0-5-12
				118	0-2-10
				119	0-5-10
				210	2-13-0
				216	0-18-0
				217	0-14-0
				220	0-8-0
				36/2	1-0-0
				37	0-2-12
				38	0-10-0
				42	0-13-10
				43	0-8-14
				44	0-17-0
				45	0-5-10
				46	0-0-5
				49	0-0-19
				51	0-1-10
				52	1-0-0
				53	0-0-12
				215	0-0-5
				97	0-0-08
				56	0-1-13

[स० ओ-14016/416/84-जी पी]

SO 2011—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum SO 4521 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government, declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### Hajira-Barielly-Jagdeshpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur-Dehat	Derapur	Derapur	Jaura	99	0-1-10
				100	1-2-0
				104	0-2-0
				105	0-17-14
				110	0-2-0
				113/1	0-5-12
				118	0-2-10
				119	0-5-10
				210	2-13-0
				216	0-18-0
				217	0-14-0
				220	0-8-0
				36/2	1-0-0
				37	0-2-12
				38	0-10-0
				42	0-13-10
				43	0-8-14
				44	0-17-0
				45	0-5-10
				46	0-0-5
				49	0-0-19
				51	0-1-10
				52	1-0-0
				53	0-0-12
				215	0-0-5
				97	0-0-08
				56	0-1-13

[No. O-14016/416/84-GP]

का०आ० 2012:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 4522 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

##### हाजिरा-बरैली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर-देहात	देरापुर	देरापुर	विसोहा	961	0-15-0
				960	1-15-0
				963	0-4-19
				267	0-11-0
				886	0-3-3
				884	3-6-0
				873	0-4-0
				543	0-13-16
				657	0-16-0
				883	0-2-0
				655	0-2-5
				656	0-8-15
				654	0-14-10
				659	0-3-5
				1104	0-3-0
				(पु०न०)	
				661	0-7-4
				663	1-2-0
				669	0-6-0
				670	0-17-0
				185	0-0-13
				668 का	0-8-10
				686	2-17-0
				687	02-10

5	6
171	0-3-18
210	
330	
1113	
1159	
1196	
962	0-1-0
887	0-3-0
630	0-0-10
884	0-0-10

[सं. O-14016/417/84-जी.पी.]

SO 2012—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S O 4522 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government,

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

## SCHEDULE

## Hajira Barielly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur-Dehat	Derapur	Derapur	Visoha	961	0-15-0
				960	1-15-0
				963	0-4-19
				267	0-11-0
				886	0-3-3
				884	3-6-0
				873	0-4-0
				543	0-13-16
				657	0-16-0
				883	0-2-0
				655	0-2-5
				656	0-8-15
				654	0-14-10
				659	0-3-5

5	6
1104	0-3-0
(old No)	
661	0-7-4
663	1-2-0
669	0-6-0
670	0-17-0
185	0-0-13
668ka	0-8-10
686	2-17-0
687	0-2-10
171	0-3-18
210	
330	
1113	
1159	
1196	
962	0-1-0
887	0-3-0
630	0-0-10
884	0-0-10

[No O-14016/417/84-GP]

का आ 2013.—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भागत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ स 4529 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भागतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधों से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## बरेली जगवीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर	देरापुर	देरापुर	भन्देमऊ	398	0-1-6
देहात				1	2-3-1
				2	0-7-19
				3	1-11-10
				4	0-9-15

[सं. O-14016/424/84—जीपी]

S.O.2013.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4140 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira-Barielly-Jagdeshpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur	Derapur	Derapur	Bhanday-	398	0-1-6
Dehat			mau	1	2-3-1
				2	0-7-19
				3	1-11-10
				4	0-9-15

[No. O-14016/424/84—GP]

का. आ. 2014.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4396 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार

को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरी बरेली जगवीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर-	देरापुर	देरापुर	खुजुरा	1	0-0-15
देहात				183	0-17-5
				182	0-1-2
				180	1-11-0
				181	0-0-15
				177	0-1-0
				175	0-2-15
				174	0-6-0
				173	0-8-10
				172	0-6-12
				171	0-6-12
				170	0-0-13
				169	0-12-10
				93	0-1-2
				39	0-4-10
				40	0-0-12
				49	0-5-0
				48	0-6-0
				47	0-6-0



1	2	3	4	5	6	5	6
				46	0-5-5	175	0-2-15
				45	0-1-3	174	0-6-0
				44	1-9-0	173	0-8-10
				58	0-1-0	172	0-6-12
				50	0-0-14	171	0-6-12
				57	1-4-5	170	0-0-13
				55	0-3-3	169	0-12-10
				56	1-5-5	93	0-1-2
				53	0-2-0	39	0-4-10
				54	0-0-11	40	0-0-12
				60	0-0-13	49	0-5-0
				71	0-0-10	48	0-6-0
				69	0-1-10	47	0-6-0
				72	2-16-10	46	0-5-5
				73	0-0-15	45	0-1-3
				74	1-5-15	44	1-9-0
				51	0-1-10	58	0-1-0
						50	0-0-14
						57	1-4-5
						55	0-3-3
						56	1-5-5
						53	0-2-0
						54	0-0-11
						60	0-0-13
						71	0-0-10
						69	0-1-10
						72	2-16-10
						73	0-0-15
						74	1-5-15
						51	0-1-10

[सं. O-14016/427/84-जी पी]

S.O. 2014.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4396 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances,

## SCHEDULE

## Hajira-Barielly-Jagdeshpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur-Dehat	Derapur	Derapur	Khajurra	1	0-0-15
				183	0-17-5
				182	0-1-2
				180	1-11-0
				181	0-0-15
				177	0-1-0

[No. O-14016/427/84-GP]

का. आ. 2015.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4397 तारीख 15-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

#### हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	लिखा गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर	देरापुर	देरापुर	महुवा	414	1-02-0
				415	0-14-0
				416	0-02-02
				417	0-03-10

[सं. O-14016/428/84-जी पी]

S.O. 2015.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4397 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

#### Hajira-Bareilly-Jagdeshpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur	Derapur	Drapur	Mahuwa	414	1-02-0
Dehat				415	0-14-0
				416	0-02-02
				417	0-03-10

[No. O-14016/428/84-GP]

का. आ. 2016.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधि-

नियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 120 तारीख 2-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस जारी तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात	जिला-पंचमहल	तालुका-काकोल			
गांव	सर्वे नं.	सर्वे नं.	हेक्टर	आर	सेन्टीयर
मुखी	212/1/P		0	00	32
	213/1		0	20	00
	213/2		0	10	00
	313		0	05	00
	311/1		0	11	00
	311/2		0	13	00
	311/3		0	01	00
	316/1		0	07	50
	316/2		0	06	00
	318/2		0	14	00
	318/3		0	02	00
	319		0	02	00

[सं. O-14016/513/84-जी पी]

S.O. 2016.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 120 dated 2-1-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in

Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Pipeline From Hazira-Bareilly-Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Acre	Centi-are
Bhukhi	212/1/P	0	00	32
	213/1	0	20	00
	213/2	0	10	00
	313	0	05	00
	311/1	0	11	00
	311/2	0	13	00
	311/3	0	01	00
	316/1	0	07	50
	316/2	0	06	00
	318/2	0	14	00
	318/3	0	02	00
	319	0	02	00

[No. O-14016/513/84-GP]

का. आ. 2017.--यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करने है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	जाना	218	0-4-2
शहर	शहर	शहर		219	0-3-10
				220	0-7-15
				221	0-13-7
				222	0-11-8
				223	0-9-16
				224	0-3-12
				226	0-5-4
				227	0-9-4
				228	0-9-5
				229	0-14-14
				230	0-14-12
				231	0-0-6
				238	0-7-10
				237	0-9-6
				239	0-0-18
				245	0-1-19
				269	0-7-4
				270	0-6-0
				271	0-10-9
				272	0-11-12
				328	0-13-13
				346	3-4-4
				347	3-7-12
				349	1-4-12
				356	2-8-6
				357	0-9-18
				390	0-5-2
				391	0-7-11

1	2	3	4	5	6
				392	0-0-15
				409	0-0-8
				410	0-12-13
				411	0-0-15
				415	0-4-11
				416	0-14-14
				418	0-11-08
				420	0-0-02
				421	0-9-15
				422	0-12-12
				426	0-3-11

[सं. O-14016/6/84—जी. पी.]

S.O. 2017.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired.
1	2	3	4	5	6
Kanhur City	Kanpur City	Kanpur City	Jana	218	0-4-2
				219	0-3-10
				220	0-7-15
				221	0-13-7
				222	0-11-8
				223	0-9-16
				224	0-3-12
				226	0-5-4
				227	0-9-4
				228	0-9-5
				229	0-14-14
				230	0-14-12
				231	0-0-6
				238	0-7-10

1	2	3	4	5	6
				237	0-9-6
				239	0-0-18
				245	0-1-19
				269	0-7-4
				270	0-6-0
				271	0-10-9
				272	0-11-12
				328	0-13-13
				346	3-4-4
				347	3-7-12
				349	1-4-12
				356	2-8-6
				357	0-9-18
				390	0-5-2
				391	0-7-11
				392	0-0-15
				409	0-0-8
				410	0-12-13
				411	0-0-15
				415	0-4-11
				416	0-14-14
				418	0-11-08
				420	0-0-02
				421	0-9-15
				422	0-12-12
				426	0-3-11

[No. O-14016/6/84—GP]

का.प्रा. 2018.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962) (1962 का 50) के धारा 3 का उपधारा (1) के अधिनियम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रिय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम के धारा 6 की उपधारा (1) के अधिनियम सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रिय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब अतः उक्त अधिनियम के धारा 6 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रिय सरकार में निहित होने के बजाय भारत में सैन्य प्राधिकरण में सैन्य बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

## अनुसूची

## हजिरा-बरिली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	पर्गना	ग्राम का नाम	विवादास्पद रकबा	विबरण
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	बिनगावा	568 म.म.	0-16-18
मिर्जापुर	मिर्जापुर	मिर्जापुर		567	0-10-08
				566	0-11-19
				565	0-0-01
				564	0-7-03
				571	0-7-03
				597	0-7-02
				599	0-15-05
				600	0-11-10
				601	0-8-14
				596	0-3-06
				602	0-3-11
				605	0-5-05
				555	0-7-15
				554	0-7-06
				556	0-1-18
				553	0-5-13
				606	0-10-08
				631	0-16-2
				630	0-18-04
				633	0-17-17
				634	0-17-03
				646	0-1-07
				647	0-1-01
				652	0-7-08
				653	0-3-05
				650	0-6-17
				657	0-9-14
				958	0-5-0
				954	0-1-0
				957	0-9-0
				960	0-3-11
				955	0-2-11
				956	0-8-0
				917	0-7-18
				946	0-5-04
				943	0-6-0
				940	0-1-4
				941	0-13-0
				938	0-0-12
				937	0-12-7
				935	0-4-0
				902	1-15-0
				903	0-0-9
				900	0-3-12
				899	0-9-0
				898	0-0-9

S.O. 2018.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gazette of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira-Barielly-Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur	Kanpur	Kanpur	Bingawa	568m	0-16-18
City	City	City		567	0-10-08
				566	0-11-19
				565	0-0-01
				564	0-7-03
				571	0-7-03
				597	0-7-02
				599	0-15-05
				600	0-11-10
				601	0-8-14
				596	0-3-06
				602	0-3-11
				605	0-5-05
				555	0-7-15
				554	0-7-06
				556	0-1-18
				553	0-5-13
				606	0-10-08
				631	0-16-2
				630	0-18-04
				633	0-17-17
				634	0-17-03
				646	0-1-07
				647	0-1-01
				652	0-7-08
				653	0-3-05
				650	0-6-17
				657	0-9-14
				958	0-5-0
				954	0-1-0
				957	0-9-0
				960	0-3-11
				955	0-2-11
				956	0-8-0
				917	0-7-18
				946	0-5-04
				943	0-6-0
				940	0-1-4
				941	0-13-0
				938	0-0-12
				937	0-12-7
				935	0-4-0
				902	1-15-0
				903	0-0-9
				900	0-3-12
				899	0-9-0
				898	0-0-9

[सं० O-14016/88 संकीर्ण]

1	2	3	4	5	6
				947	0-7-18
				946	0-5-04
				943	0-6-0
				940	0-1-4
				941	0-13-0
				938	0-0-12
				937	0-12-7
				935	0-4-0
				902	1-15-0
				903	0-0-9
				900	0-3-12
				899	0-9-0
				898	-0-0-9

[No. O-14016/6/84—GP]

का.आ. 2019.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्थन (अधिनियम 1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्थन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में, उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जात है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन के इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	सेन पूरवा	411	0-3-12
शहर	शहर	शहर	पार	427	0-7-10
				450	0-1-12
				428	0-12-0
				438	0-10-0
				439	0-11-0
				440	0-1-0
				441	0-9-0
				442	0-4-0
				451	0-5-0
				452	0-15-10
				453	2-1-0

1	2	3	4	5	6
				493	2-1-0
				466	0-7-0
				465	9-15-0
				463	1-8-0
				461	0-1-16
				462	0-1-0
				460	1-3-0
				507	0-0-4
				508	0-5-12
				515	1-6-0
				519	1-10-0
				522	0-0-15
				514	0-2-17
				513	0-2-8
				520	0-1-12
				521	1-14-0
				509	0-1-1
				510	0-0-8
				1054	0-3-18
				1055	0-10-4
				1058	0-5-0
				1059	1-4-10
				1065	0-5-12
				1064	0-15-12
				1082	0-17-0
				1081	0-4-11
				1083	2-7-18
				1297	0-1-7
				1296	0-11-4
				1298	2-7-0
				1299	1-2-0
				1287	0-9-0
				1286	0-9-15
				1284	0-12-12
				1281	0-7-12
				1276	1-2-0
				1277	0-1-10
				1313	0-7-15
				1315	0-1-10
				1319	0-1-19
				1320	0-8-6
				1321	0-8-0
				1329	0-9-0
				1327	0-5-14
				1330	0-16-8
				1331	2-6-0
				1332	1-17-14

[स. O-14016/6/84-जीपी]

S.O. 2019.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Hajira Bareilly Jogdishpur Pipe line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	3	4	5	6	
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Senpurat Para	411	0-3-12
				427	0-7-10
				450	0-1-12
				428	0-12-0
				438	0-10-0
				439	0-11-0
				440	0-1-0
				441	0-9-0
				442	0-4-0
				451	0-5-0
				452	0-15-10
				453	2-1-0
				493	2-1-0
				466	0-7-0
				465	9-15-0
				463	1-8-0
				461	0-1-16
				462	0-1-0
				460	1-3-0
				507	0-0-4
				508	0-5-12
				515	1-6-0
				519	1-10-0
				522	0-0-15
				514	0-2-17
				513	0-2-8
				520	0-1-12
				521	1-14-0
				509	0-1-1
				510	0-0-8
				1054	0-3-18
				1055	0-10-4
				1058	0-5-0
				1059	1-4-10
				1965	0-5-12
				1064	0-15-12
				1082	0-17-0
				1081	0-4-11
				1083	2-7-18
				1297	0-1-7
				1296	0-11-4

1	2	3	4	5	6
				1298	2-7-0
				1299	1-2-0
				1287	0-9-0
				1286	0-9-15
				1284	0-12-12
				1281	0-3-12
				1276	1-2-0
				1277	0-1-10
				1313	0-7-15
				1315	0-1-10
				1319	0-1-19
				1320	0-8-6
				1321	0-8-0
				1329	0-9-0
				1327	0-5-14
				1330	0-16-8
				1331	2-6-0
				1332	1-17-14

[No. O-14016/6/84-G.P.]

का.आ. 2020—यतः पेट्रोलियम और बनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. से. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में व्यवसाय के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

#### अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	पारगना	ग्राम का नाम	गांवा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	सोना	1379	0-0-10
गहर,	गहर,	गहर		1378	0-0-16
				1372	1-2-0
				1377	1-9-0
				1376	0-18-10

1	2	3	4	5	6
				1333	0-15-5
				1335	0-15-17
				1334	0-3-7
				1331	1-15-2
				1329	0-1-5
				1327	0-6-0
				1323	0-0-13
				1322	0-11-14
				1327	0-9-0
				1320	0-16-13
				1314	0-13-16
				1315	0-14-0
				1313	0-8-15
				1299	1-0-0
				1295	0-0-13
				1294	0-13-10
				1288	0-9-15
				1095	1-7-15
				1097	0-4-15
				1098	2-1-5
				1084	0-8-0
				1085	0-6-12
				1070	2-4-0
				1069	0-7-10
				1068	1-1-10
				1066	1-7-5
				1064	1-2-5
				1063	0-10-0
				755	0-19-0
				757	0-8-5
				756	0-0-13
				754	0-13-0
				1087	0-0-6
				1316	0-0-5
				1086	0-0-7
				761	0-11-2
				758	0-1-15

[सं. O-14016/6/84-जीपी]

S.O. 2020.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4529 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira Baroilly Jagdishpur Pipe line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Sona	1379	0-0-10
				1378	0-0-16
				1372	1-2-0
				1377	1-9-0
				1376	0-18-10
				1333	0-15-5
				1335	0-15-17
				1334	0-3-7
				1331	1-15-2
				1329	0-1-5
				1327	0-6-0
				1323	0-0-13
				1322	0-11-14
				1321	0-9-0
				1320	0-16-13
				1314	0-13-16
				1315	0-14-0
				1313	0-8-15
				1299	1-0-0
				1295	0-0-13
				1294	0-13-10
				1288	0-9-15
				1095	1-7-15
				1097	0-4-15
				1098	2-1-5
				1084	0-8-0
				1085	0-6-12
				1070	2-4-0
				1069	0-7-10
				1068	1-1-10
				1066	1-7-5
				1064	1-2-5
				1063	0-10-0
				755	0-19-0
				757	0-8-5
				756	0-0-13
				754	0-15-0
				1087	0-0-6
				1316	0-0-5
				1086	0-0-7
				761	0-11-2
				758	0-1-15

[No. O-14016/6/84-G.P.]

का.आ. 2021.—यतः पेट्रोसियम और बनिज पाइपलाइन (भूमि) के उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोसियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।



और यह सक्षम प्राधिकारी न उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्थात् सरकार का रिपोर्ट देवी है।

और आगे यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियां उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा धारित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाठगलाइत विधान के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हाजिरा बंगली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गांवा में	विस्तार गवा रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	मनिगवा	152	1-0-8
गहर	गहर	गहर		162	0-18-0
				165	0-13-12
				167	0-7-14
				168	0-11-4
				169	0-0-8
				189	0-10-4
				190	0-5-3
				191	0-4-0
				192	0-1-16
				193	0-0-12
				195	0-2-16
				240	0-0-15
				241	0-1-15
				242	0-14-0
				243	0-2-8
				245	0-7-14
				247	0-6-6
				248	0-3-3
				249	0-3-3
				252	0-2-0
				257	0-17-4
				267	0-6-4
				268	0-9-18
				269	0-3-0
				270	0-0-12
				271	1-9-4
				730	0-0-16
				732	0-0-16
				890	0-9-7
				891	0-1-0
				392	0-9-15

[म O 14016/8/84 जीपी

S.O. 2021.--Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Soni Gawan	152	1-0-8
				162	0-18-0
				165	0-13-12
				167	0-7-14
				168	0-11-4
				169	0-0-8
				189	0-10-4
				190	0-5-3
				191	0-4-0
				192	0-1-16
				193	0-0-12
				195	0-2-16
				240	0-0-15
				241	0-1-15
				242	0-14-0
				243	0-2-8
				245	0-7-14
				247	0-6-6
				248	0-3-3
				249	0-3-3
				252	0-2-0
				257	0-17-4
				267	0-6-4
				268	0-9-18
				269	0-3-0
				270	0-0-12
				271	1-9-4
				730	0-0-16
				732	0-0-16
				890	0-9-7
				891	0-1-0
				892	0-9-15
				894/2	1-10-0
				895	0-8-0
				896	0-18-14
				935	0-19-19
				936	1-2-9
				937	0-6-0
				944	0-1-4
				945	0-7-16
				947	0-16-0
				965	0-7-16
				966	0-6-2
				1010	0-2-14
				1011	0-2-2
				1012	0-1-10
				1013	0-17-14
				1014	0-8-0
				1018	0-6-0
				1019	0-10-9
				1020	0-0-12
				1021	0-5-16
				1022	0-2-0
				1023	0-2-0
				1023	0-3-0
				1024	0-10-8
				1029	0-4-0
				1078	0-4-0

का. आ. 2022.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

हजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं.	भिया गया रकबा का नाम
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	भैरम-	54	0-4-17
सिटी	सिटी	सिटी	पुर	55	1-5-17
				57	0-3-0
				63	0-5-6
				64	0-5-1
				65	0-10-4
				66	1-6-0
				70	1-16-0
				76	1-2-1
				77	0-5-5
				78	0-13-0
				84	0-0-1
				87/3	0-3-2
				87/4	1-5-0
				87/2	0-10-0
				90	0-11-11
				91	1-6-10
				92	1-1-10
				98	0-16-0
				99	1-4-8)
					1-2-4 }
				100	0-1-1

1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6
				114	0-0-8					84	0-0-1	
				1056	0-0-7					87/3	0-3-2	
				1058	0-10-1					87/4	1-5-0	
				1059	0-0-10					87/2	0-10-0	
				1067	0-5-0					90	0-11-11	
				1068	0-0-10					91	1-6-10	
				1071	0-2-10					92	1-1-10	
				1072	1-4-0					98	0-16-0	
				1088	0-7-10					99	1-4-8,	
				1090	0-5-0						1-2-4	
				1091	0-17-0						2-6-12	
				1092	1-3-0					100	0-1-1	
				1097	3-15-0					114	0-0-6	
				1098	1-1-15					1056	0-0-7	
				73	0-3-0					1058	0-10-1	

[स. O-14016/6/84-जीपी]

S.O. 2022.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances,

## SCHEDULE

## Hajira Barielly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur	Kanpur	Kanpur	Bhairam	54	0-4-17
City	City	City	pur	55	1-5-17
	Sadar			57	0-3-0
				63	0-5-6
				64	0-5-1
				65	0-10-4
				66	1-6-0
				70	1-16-0
				76	1-2-1
				77	0-5-5
				78	0-13-0

84 0-0-1  
87/3 0-3-2  
87/4 1-5-0  
87/2 0-10-0  
90 0-11-11  
91 1-6-10  
92 1-1-10  
98 0-16-0  
99 1-4-8,  
1-2-4  
2-6-12  
100 0-1-1  
114 0-0-6  
1056 0-0-7  
1058 0-10-1  
1059 0-0-10  
1067 0-5-0  
1068 0-0-10  
1071 0-2-10  
1072 1-4-0  
1088 0-7-10  
1090 0-5-0  
1091 0-17-0  
1092 1-3-0  
1097 3-15-0  
1098 1-1-15  
73 0-3-0

[No. O-14016/6/84—G.P.]

का. आ. 2023:—यन. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को प्राप्त लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सशम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार प्राप्त लाइनों को बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्विशेष वेती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषण के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	पगना	ग्राम	भूट्टा म	बिघा गवा
			का नाम		रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	कौंधा	479	0-4-0
मिर्जा	मिर्जा	मिर्जा			
				495	1-13-18
				496	0-3-8
				498	4-8-15
				499	0-9-15
				500	0-0-16
				520	0-2-17
				521	0-2-15
				522	0-11-5
				525	0-6-15
				527	0-9-15
				528	0-8-15
				534	0-7-15
				538	1-11-0
				539	0-8-15
				542	0-0-13
				602	0-15-10
				603	0-10-13
				604	0-12-12
				606	0-9-0
				609	1-5-0
				610	0-0-13
				618	1-0-0
				620	2-0-10
				621	0-0-13
				628	1-9-0
				630	0-9-14
				634	0-1-16
				640	1-0-5
				641 एम	0-12-10
				एम	0-12-10
				646	0-19-5
				647	0-1-5
				654	0-2-10
				655	0-19-0
				656	0-8-5
				657	0-2-10
				660	0-0-15
				718	0-15-0
				730	0-5-5
				1078	0-11-3
				1079	0-5-15
				1084	4-0-1
				1085	1-1-10
				1086	0-8-11

2023.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 41001 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances,

## SCHEDULE

## Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur	Kanpur	Kanpur	Kaindha	479	0-4-0
City	City	City		495	1-13-18
				496	0-3-8
				498	4-8-15
				499	0-9-15
				500	0-0-16
				520	0-2-17
				521	0-2-15
				522	0-11-5
				525	0-6-15
				527	0-9-15
				528	0-8-15
				534	0-7-15
				538	1-11-0
				539	0-8-15
				542	0-0-13
				602	0-15-10
				603	0-10-13
				604	0-12-12
				606	0-9-0
				609	1-5-0
				610	0-0-13
				618	1-0-0
				620	2-0-10
				621	0-0-13
				628	1-9-0
				630	0-9-14
				634	0-1-16
				640	1-0-5
				641m	0-12-10
				m	0-12-10
				646	0-19-5
				647	0-1-5
				654	0-2-10
				655	0-19-0

1	2	3	4	5	6
				656	0-8-5
				657	0-2-10
				660	0-0-15
				718	0-15-0
				730	0-5-5
				1078	0-11-3
				1079	0-5-15
				1084	4-0-1
				1085	1-1-10
				1086	0-8-11

[No O-14016/6/84-G.P.]

का. आ. 1034:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आणख घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जन किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख की तिथि होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीनपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	ताँका-मिटी	286	0-13-7
				287	0-11-16
				295	0-6-0
				294	0-8-5
				297	0-15-8
				281	0-2-10
				292	0-4-0
				280	0-10-1
				278	0-0-1
				279	0-12-16
				230	0-6-10

[सं. O-14016/6/84-जं०-पी०]

S.O. 2013.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Tauchhak Pur	286	0-13-7
				287	0-11-16
				295	0-6-0
				294	0-8-5
				297	0-15-8
				281	0-2-10
				282	0-4-0
				280	0-10-1
				278	0-0-1
				279	0-12-16
				230	0-6-10
				233	1-2-3
				235	0-3-20
				234	0-0-12
				216	0-13-19
				239	0-4-0
				215	0-14-6
				214	0-16-19
				243	0-0-5
				212	0-18-0
				165	0-1-0
				166	0-16-6
				162	0-3-0
				167	0-8-11
				161	0-1-10
				153	1-4-10
				156	0-5-0
				155	0-6-5
				154	0-4-10
				147	2-7-0
				107	0-14-9
				106	0-16-0
				109	0-1-0

[No.—O-14016/6/84-G.P.)

का. आ. 2025:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी भाषाओं में मुक्त रूप से बोधना के प्रकाशन की इस सारीख की निहित होगी।

## अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा	लिया गया
			का नाम	सं	रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर	कानपुर	गबन	1	0-5-0
मिटी	मिटी	सिटी	खेड़ा		
				191	2-2-0
				192	0-1-0
				193	0-0-14
				194	1-13-0
				195	0-1-0
				196	0-18-0
				201	0-0-14
				201/250	0-14-0
				202	0-0-14
				204	1-1-0
				205	1-8-0
				206	0-5-0

[सं. O-14016/6/84-जी पी]

S.O. 2025.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

1 2 3 4 5 6 7

## Hajira Bareilly Jagdishhpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur City	Gadan Kheda	1	0-5-0
				191	2-2-0
				192	0-1-0
				193	0-0-14
				194	1-13-0
				195	0-1-0
				196	0-18-0
				201	0-0-14
				201	0-14-0
				250	
				202	0-0-14
				204	1-1-0
				205	1-8-0
				206	0-5-0

[No. O-14016/6/84-GP]

का. आ. 2026-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4104 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्णय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उन धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्वहण देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम- कानाम	लिया गया रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6
कानपुर सिटी	कानपुर सिटी	कानपुर सिटी	शेषपुर	478	0-0-4
				489	0-0-1

490 0-9-0  
492 0-13-0  
493 0-14-2  
494 0-5-0  
797 0-0-8  
503 0-5-0  
504 0-12-0  
505 0-12-0  
601 1-1-0  
606 0-1-0  
608 0-3-0  
609 0-17-0  
610 0-14-0  
611 0-4-0  
619 0-3-0  
621 0-11-0  
622 0-12-0  
623 0-1-0  
624 0-14-0  
660 0-17-13  
661 0-4-10  
785 0-5-0  
787 0-6-0  
988 0-7-0  
810 0-9-0

[सं. O-14016/6/84-जी पी]

S.O. 2026.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 4104 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur City	Kanpur City	Kanpur city	Shekhan	478	0-0-4
				489	0-0-4
				490	0-9-0
				492	0-13-0
				493	0-14-2
				494	0-5-0
				797	0-0-5
				503	0-5-0
				504	0-12-0
				505	0-12-0
				601	1-1-0
				606	0-1-0
				608	0-3-0
				609	0-17-0
				610	0-14-0
				611	0-4-0
				619	0-3-0
				621	0-11-8
				622	0-12-0
				623	0-1-0
				624	0-14-0
				660	0-17-13
				661	0-4-10
				785	0-5-0
				787	0-6-0
				988	0-7-0
				810	0-9-0

[No. O-14016/6/84—G.P.]

नई दिल्ली, 1 मई, 1985

का.अ. 2027—अतः केन्द्रीय सरकार ह्मको प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतभर गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत् प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने का प्रयोजन के लिये एन्डोवमेंट अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. बी-58/बी, अलीगंज, लखनऊ-226020 यू.पी. को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची  
हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल बीघा	विस्थापित	विस्थापित
हरदोई	बिलग्राम	कटियारी	श्यामपुर	190	2	5	—
				169/890	—	4	—
				169	—	12	—
				170	—	9	—
				186	—	1	—
				185	—	5	—
				221	2	—	—
				222	1	—	—
				223	—	6	10
				226	—	2	10
				228	1	—	—
				229	1	—	—
				230	—	8	—
				231	—	11	—
				232	—	19	—
				233	—	12	—
				234	—	16	—
				235	—	15	—
				236	—	19	—
				237	—	9	—
				238	—	6	—
				216मि०	3	2	—
				217मि०	—	5	—
				348	1	—	—
				355	1	3	—
				354	—	15	—
				353	—	—	10
				352	1	—	—
				350	2	7	—

[सं. ओ-14016/306/85-जी०पी०]

New Delhi, the 1st May, 1985

S.O. 2027.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Petroleum from Hajira-Bareilly-Jagdishpur in Uttar Pradesh State Pipeline should be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India, Ltd., H.B.J. Pipeline Project B-58/B, Aliganj Lucknow-226020 U.P.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.



## SCHEDULE

## Gas Pipe Line From Hajira—Bareilly-Jagdishpur Project

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	A R E A		
					Bihga	Biswa	Biswansi
1	2	3	4	5	6	7	
Hardoi	Bilgram	Katiyari	Shyam-pur	190	2	5	—
				169/860	—	4	—
				169	—	12	—
				170	—	9	—
				186	—	1	—
				185	—	5	—
				184	1	5	—
				221	2	—	—
				222	1	—	—
				223	—	6	10
				226	—	2	10
				228	1	—	—
				229	1	—	—
				230	—	8	—
				231	—	11	—
				232	—	19	—
				233	—	12	—
				234	—	16	—
				235	—	15	—
				236	—	19	—
				237	—	9	—
				238	—	6	—
				216m.	3	2	—
				217m.	—	5	—
				345	—	—	—
				355	1	3	—
				354	—	15	—
				353	—	—	10
				352	1	—	—
				350	2	7	—

[No. O—14016/306/85-G.P.]

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित: यह भी, कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम-बेरा तहसील-भाण्डेर जिला-ग्वालियर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु०क्र०	खसरा नं०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1.	21 मी०	0.428
2.	22	0.366
3.	18	0.031
4.	3	0.261
5.	11	0.210
6.	12	0.031
7.	10	0.240
8.	9	0.062
9.	8	0.209
10.	62	0.157
11.	121	0.031
12.	122	0.732
13.	128	0.123
14.	127/2	0.208
15.	127/1	0.261
16.	131	0.512
17.	132	0.324
18.	133	0.209
19.	21 मी०	0.002
20.	126	0.002
21.	102	0.031
योग : कुल क्षेत्रफल		4.430

[स० O-14016/307/85-जी०पी०]

का अ० 2028-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजौरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि भारतीय गैस प्राधिकरण की ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्प्रावधान अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिये आशेष सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग एच०बी०जे० पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सांवेर रोड, उज्जैन (म०प्र) 456001 को इस अधिवृत्त की तारीख के 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

S.O. 2028.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

अनुसूची

Village : Ba'nda Tehsil : Bhandar Distt : Gwalior

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	21M	0.428
2.	22	0.366
3.	18	0.031
4.	3	0.261
5.	11	0.210
6.	12	0.031
7.	10	0.240
8.	9	0.062
9.	8	0.209
10.	62	0.157
11.	121	0.031
12.	122	0.732
13.	128	0.123
14.	127/2	0.208
15.	127/1	0.261
16.	131	0.512
17.	132]	0.324
18.	133	0.209
19.	21 M	0.002
20.	126	0.002
21.	192	0.031
TOTAL AREA		4.430

[No. O-14016/307/85-G.P.]

का०आ० 2029—यत् केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजौरा से बरेली से अगदीशपुर तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जाय चाहिये।

और यत् यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाठ्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आणय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बतलें कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच०बी०जे० पाइप लाइन 45, सुभाष नगर, सचिव रोड, उज्जैन (म०प्र०) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिवृष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मृतवाह्य व्यक्तिगत रूप से हो या किसी बिधि व्यवसायी की मार्फत।

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट		
ग्राम- नोबई तहसील भाण्डेर जिला-ग्वालियर राज्य (मध्य प्रदेश)		
अनु क्र०	खसरा न०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर) में
1	2	3
1.	313	0.794
2.	312	0.810
3.	310/2	0.784
4.	320	0.710
5.	319	0.074
6.	321	0.005
7.	322	0.107
8.	323	0.020
9.	296	0.465
10.	291	0.157
11.	293	0.010
12.	292	0.052
13.	290	0.021
14.	289	0.120
15.	297	0.168
16.	284	0.010
17.	283	0.030
18.	285	0.303
19.	364	0.010
20.	363	0.188
21.	361	0.157
22.	373	0.032
23.	372	0.180
24.	374	0.700
25.	375/1	0.020
26.	375/2	0.031
27.	375/3	0.120
28.	378	0.314
29.	388	0.145
30.	387	0.115
31.	389	0.070
32.	432	0.365
33.	431	0.052
34.	430	0.105
35.	429	0.052
36.	419	0.815
37.	418	0.105
38.	420	0.272
39.	416	0.052
40.	96	0.031
41.	95	0.795
42.	282	0.147
43.	288	0.005
44.	310/1	0.136
45.	325	0.005
46.	384	0.021
47.	415	0.031
48.	379	0.010
49.	439	0.052

योग : कुल क्षेत्रफल 9.773

[स० O-14016/308/85-जी०पी०]

S.O. 2029.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by or by legal practitioner.

### SCHEDULE

#### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Nowai Tehsil : Bhandar Distt. : Gwalior

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectar
1.	313	0.794
2.	312	0.810
3.	310/2	0.784
4.	320	0.710
5.	319	0.074
6.	321	0.005
7.	322	0.107
8.	323	0.020
9.	296	0.465
10.	291	0.157
11.	293	0.010
12.	292	0.052
13.	290	0.021
14.	289	0.120
15.	287	0.168
16.	284	0.010
17.	283	0.030
18.	285	0.303
19.	364	0.010
20.	363	0.188
21.	361	0.157
22.	373	0.032
23.	372	0.180
24.	374	0.700
25.	375/1	0.020
26.	375/2	0.031
27.	375/3	0.120
28.	378	0.314
29.	388	0.145
30.	387	0.115
31.	389	0.070
32.	432	0.365
33.	431	0.052
34.	430	0.105
35.	429	0.052
36.	419	0.815
37.	418	0.105

1	2	3
38.	420	0.272
39.	416	0.052
40.	96	0.031
41.	95	0.795
42.	282	0.147
43.	288	0.005
44.	310/1	0.136
45.	325	0.005
46.	384	0.021
47.	415	0.031
48.	379	0.010
49.	439	0.052
TOTAL AREA		9.773

[No. O—14016/308/85-G.P.]

का०आ०२०३० —यह, केन्द्रीय सरकार को यह प्रगत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजौरा से बरेल में जगदलपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारत-यौन प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जान चाहिये।

और यह प्रगत होता है कि ऐसा लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूच में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्णित कि उक्त भूमि में हितवश कोई व्यक्ति उस भूमि के तत्वे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकार, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच० ब० जे पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर, सांवर रोड उज्जैन-456001 (प०प०) को हय अधिसूचना का जारी कर, 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किन विधि व्यवसाय के माफिक।

अनुसूचः

एच०ब००३० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम-मनियर तहसिल-पिछोर जिला-शिवपुर, राज्य-(मध्य प्रदेश)

अनु० क्र०	खसरा न०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	1	0.125
2.	30	0.178
3.	31	0.240
4.	32	0.042
5.	29	0.042
6.	28	0.272
7.	21	0.115
8.	25	0.303
9.	106	0.209
10.	104	0.230
11.	105	0.011

1	2	3
12.	109	0.084
13.	108	0.209
14.	122	0.010
15.	123	0.031
16.	124	0.010
17.	125	0.010
18.	128	0.084
19.	126	0.178
20.	127	0.052
21.	131	0.010
22.	132	0.052
23.	133	0.105
24.	141	0.031
25.	139	0.105
26.	140	0.010
27.	162	0.072
योग--कुल क्षेत्रफल		2.840

[सं० O-14016/309/85-जी०पि०]

S.O. 2030.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBI Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBI GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Maniyar Tehsil : Pichore Distt. : Shivpuri

Sl. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	1	0.125
2.	30	0.178
3.	31	0.240
4.	32	0.042
5.	29	0.042
6.	28	0.272
7.	24	0.115
8.	25	0.303
9.	106	0.209
10.	104	0.230
11.	105	0.031
12.	109	0.084
13.	108	0.209
14.	122	0.010
15.	123	0.031
16.	124	0.010
17.	125	0.010

1	2	3
18.	128	0.084
19.	126	0.178
20.	127	0.052
21.	131	0.010
22.	132	0.052
23.	133	0.105
24.	141	0.031
25.	139	0.105
26.	140	0.010
27.	162	0.072
TOTAL AREA		2.840

[No. O-14016/309/85-G.P.]

का०आ० 2031.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक कि मध्यप्रदेश राज्य में हजारा से बरेली से जगदशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जाना चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावक अनुसूचा में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बताते कि उक्त भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष सक्षम प्राधिकार, नैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच०बी०जी० पाइप लाइन, 45, गुभाण नगर, सांवेर रोड उज्जैन-456001 (स.प.) को इस अधिसूचना के तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेंगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित रूप से कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसके मुताबिक व्यक्तिगत रूप से हो या कि वह विधि व्यवसाय का मार्फत।

अनुसूचा

एच०बी०जी० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम--पिपारा	तहसील--पिछोर	जिला--शिवपुर	राज्य (मध्य प्रदेश)
अनु० क्र०	खसरा नं०	जायान अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)	
1	2	3	
1.	287	0.052	
2.	282	0.022	
3.	283	0.116	
4.	284	0.105	
5.	295	0.084	
6.	297	0.073	
7.	298	0.105	
8.	299	0.021	
9.	300	0.073	
10.	302	0.043	
11.	303	0.136	
12.	309	0.031	
13.	310	0.418	
14.	311	0.041	

1	2	3
15	312	0.010
16	317	0.021
17	320	0.021
18	321	0.010
19	225	0.010
20	227	0.261
21	229	0.200
22	231	0.115
23	224	0.251
24	219	0.004
25	218	0.335
26	217	0.021
27	160	0.021
28	319	0.021
29	113	0.042
30	117	0.105
31	118	0.261
32	119	0.178
33	156	0.042
34	158	0.209
35	155	0.105
36	620	0.261
37	687	0.282
38	688	0.057
39	689	0.073
40	683	0.065
41	677	0.470
42	698	0.157
43	700	0.335
44	701	0.240
45	699	0.209
46	674	0.010
47	678	0.010
48	230	0.042
49	285	0.073
50	286	0.042
51	313	0.031
52	314	0.157
53	316	0.010
54	611	0.042
55	621	0.010
56	676	0.042
57	682	0.021
योग--कुल क्षेत्रफल		9.772

[सं. 0-14016/310/85-ज(कौ०)]

S.O. 2031.--Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barcilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act,

127 GI/85-11

1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village	Pipara	Tehsil	Pichhore	Distt.	Shivpuri
S. No.	Survey No.				Area to be acquired for R.O.U. in Hectar
1.	287				0.052
2.	282				0.022
3.	283				0.116
4.	284				0.105
5.	295				0.084
6.	297				0.073
7.	298				0.105
8.	299				0.021
9.	300				0.073
10.	302				0.043
11.	303				0.136
12.	309				0.031
13.	310				0.418
14.	311				0.041
15.	312				0.010
16.	317				0.021
17.	320				0.021
18.	321				0.010
19.	225				0.010
20.	227				0.261
21.	229				0.200
22.	231				0.115
23.	224				0.251
24.	219				0.004
25.	218				0.335
26.	217				0.021
27.	160				0.021
28.	319				0.021
29.	113				0.042
30.	117				0.105
31.	118				0.261
32.	119				0.178
33.	156				0.042
34.	158				0.209
35.	155				0.105
36.	620				0.261
37.	687				0.282
38.	688				0.057
39.	689				0.073
40.	683				0.065
41.	677				0.470
42.	698				0.157
43.	700				0.335
44.	701				0.240
45.	699				0.209
46.	674				0.010
47.	678				0.010
48.	230				0.042

1	2	3	1	2	3
49. 285		0.073	12. 388		—
50. 286		0.042	13. 894		0.014
51. 313		0.031	14. 896		0.031
52. 314		0.157	15. 895		0.354
53. 316		0.010	16. 832		—
54. 611		0.042	17. 833		0.035
55. 621		0.010	18. 811		0.217
56. 676		0.042	19. 809		0.177
57. 682		0.021	20. 808		—
Total Area		9.772	21. 805		0.311
[No. O-14016/310/85-GP]			22. 805/3249		—
<p>का० भा० 2032:—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।</p> <p>और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।</p> <p>अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।</p> <p>बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच बी जे पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर, साँबर रोड, उज्जैन-456001 (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।</p> <p>और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।</p>			23. 912		0.021
			24. 806		0.032
			25. 911		0.031
			26. 807		0.032
			27. 799		0.597
			28. 798		0.031
			29. 797		0.032
			30. 690		0.404
			31. 691		0.313
			32. 692		0.155
			33. 693		0.199
			34. 695		0.083
			35. 696		0.166
			36. 622		0.025
			37. 623		0.207
			38. 620		0.716
			39. 559		0.020
			30. 618		0.032
			41. 564		0.541
			42. 566		0.032
			43. 569		0.726
			44. 568		—
			45. 571		—
			46. 572		—
			47. 573		—
			48. 570		0.170
			49. 590		0.035
			50. 587		0.022
			51. 588		0.020
			52. 589		0.002
			53. 581		0.330
			54. 596		—
			55. 594		—
			56. 595		—
			57. 597		—
			58. 585		0.166
			59. 586		—
			60. 582		—
			61. 583		—
			62. 584		—
			63. 586/275		0.473
			64. 592		—
			65. 593		—

## अनुसूची

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : पिपरोबाकला तहसील : भाण्डेर जिला : मालियर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु० खसरा नं० उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

1	2	3
1. 1036		0.039
2. 1035		0.005
3. 1034		0.879
4. 1037		—
5. 909		0.178
6. 903		0.005
7. 908		0.031
8. 907		0.015
9. 899		0.052
10. 886		0.132
11. 887		0.197

1	2	3
66.	211	0.085
67.	158	0.132
68.	159	—
69.	161	—
70.	162	—
71.	163	—
72.	164	—
73.	168	0.093
74.	157	0.282
75.	156	0.032
76.	151	0.005
77.	150	0.409
78.	148/2	0.051
79.	149/2	—
80.	910	0.015
योग—कुल क्षेत्रफल		9.359

[सं. O-14016/311/85-जी पी]

S.O. 2032.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBI Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBI GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Piprowakala Tehsil : Bhandar Distt. : Gwalior

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired or R.O.U. in Hecter
1	2	3
1.	1036	0.039
2.	1035	0.005
3.	1034	0.879
4.	1037	—
5.	909	0.178
6.	903	0.005
7.	908	0.031
8.	907	0.015
9.	899	0.052
10.	886	0.132
11.	887	0.197
12.	888	—
13.	894	0.014
14.	896	0.031
15.	895	0.354
16.	832	—
17.	833	0.035
18.	811	0.217

1	2	3
19.	809	0.177
20.	808	—
21.	805	0.311
22.	805/3249	—
23.	912	0.021
24.	806	0.032
25.	911	0.031
26.	807	0.032
27.	799	0.597
28.	798	0.031
29.	797	0.032
30.	690	0.404
31.	691	0.313
32.	692	0.155
33.	693	0.199
34.	695	0.083
35.	696	0.166
36.	622	0.025
37.	623	0.207
38.	620	0.716
39.	559	0.020
40.	618	0.032
41.	564	0.541
42.	566	0.032
43.	569	0.726
44.	568	—
45.	571	—
46.	572	—
47.	573	—
48.	570	0.170
49.	590	0.035
50.	587	0.022
51.	588	0.020
52.	589	0.002
53.	591	0.330
54.	596	—
55.	594	—
56.	595	—
57.	597	—
58.	585	0.166
59.	586	—
60.	582	—
61.	583	—
62.	584	—
63.	586/3275	0.473
64.	592	—
65.	593	—
66.	211	0.055
67.	158	0.132
67(a)	159	—
68.	161	—
69.	162	—
70.	163	—
71.	164	—
72.	168	0.093
73.	157	0.282
74.	156	0.032
75.	151	0.005
76.	150	0.409
77.	148/2	0.051
78.	149/2	—
79.	910	0.015
TOTAL AREA		9.359

[No. O-14016/311/85-GP]

का. प्रा. 2013--यह केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीक होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में कृषि से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये वाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यह यह प्रतीक होता है कि ऐसी लाइनों का बिछाने के प्रयासों के लिये एतद्वाक्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार प्रदान करना आवश्यक है।

अतः मध्य पेट्रोलियम और खनिज वाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का धर्जन) अधिनियम, 1962 (1961 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार प्रदान करने का अपना आग्रह एतद्द्वारा घोषित किया है।

बतते कि उक्त भूमि में हिमबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे वाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष मध्य प्राधिकारी, नैस तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, एन.बी.जे. वाइप लाइन 45, कृष्ण नगर साधर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 का इस अनुसूची की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर लेंगे।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति निनिदिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी बिधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

एच. बी. जे. गैस वाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम	जनसंख्या	तहसील	दस्तावेज	जिला-वर्तिका राज्य
				(मध्य-प्रदेश)
अनुसू. क्रमसं.				उपयोग का अधिकार
				धर्जन का क्षेत्र
				(हेक्टर में)
1	2	3	4	5
1.	346	0.016		
2.	349	0.008		
3.	350/2	0.041		
4.	353	0.332		
5.	357	0.105		
6.	358	0.137		
7.	375	0.065		
8.	377	0.041		
9.	378	0.137		
10.	379	0.041		
11.	380	0.041		
12.	381	0.024		
13.	384	0.024		
14.	385/1	0.113		
15.	385/2	—		
16.	389	0.049		
17.	390	0.137		
18.	391/1	0.267		
19.	391/2	—		
20.	501	0.081		
21.	502	0.081		
22.	522	0.145		
23.	523/1	0.113		
24.	523/3	—		

1	2	3
25	526	0.097
26	528	0.016
27	529	0.097
28	546	0.057
29	547	0.032
30	548	0.041
31	549	0.016
32	550	0.210
33	551	0.008
34	617	0.348
35	618	0.057
36	642	0.221
37	644	0.081
38	645	0.041
39	646	0.145
40	647	0.016
41	674	0.105
42	671	0.061
43	673	0.101
44	675	0.129
45	696	0.237
46	697	0.024
47	701	0.251
48	702/1 मी.	—
49	703	—
50	714	—
51	702/1 मी.	0.004
52	713	0.170
53	714	0.113
54	715	0.202
55	1630	0.065
56	1641	0.081
57	1642	0.227
58	1643	0.105
59	1647	0.041
60	1648	0.040
61	1649	0.097
62	1654	0.041
63	1660	0.162
64	1661/2	0.186
65	1662	0.065
66	1669	0.008
67	1671	0.218
68	1703	0.016
69	1973	0.097
70	1976	0.162
71	1977	0.057
72	1978	0.064
73	1979	0.145
74	1980	0.049
75	1985	0.162
76	1988	0.170
77	2003/2	0.008
78	2005	0.121
79	2006/1	0.105



1	2	3	1	2	3
80	2007/1	0 227	7	375	0 065
81	2010/1	0 121	8.	377	0 041
82	2011	0 145	9	378	0.137
83	2013	0 073	10.	379	0 041
84	520	0.021	11	380	0 041
85	605	0 031	12.	381	0 024
86	641	0 020	13.	384	0 024
87	527	0 005	14.	385/1	0 113
88	530	0 040	15.	385/2	—
89	374	0 010	16	389	0 049
90	1989	0.020	17.	390	0 137
91	1674	0 010	18.	391/1	0 267
92	2050	0 390	19.	391/2	—
93	2046	0 020	20	501	0 081
94	2047	0 050	21.	502	0.081
95	2048	0 020	22	522	0.145
96	1995	0 010	23.	523/6	0 113
योग —कुल क्षेत्रफल		7 892	24	523/2	—
			25.	526	0 097
			26	528	0 016
			27.	529	0 097
			28.	546	0 057
			29.	547	0 032
			30	548	0 041
			31.	549	0 016
			32.	550	0 210
			33.	551	0 008
			34.	617	0 348
			35.	618	0.057
			36.	642	0 221
			37.	644	0 081
			38.	645	0 041
			39	646	0 145
			40	647	0.016
			41	674	0.105
			42.	671	0 061
			43	673	0 101
			44	675	0 179
			45.	696	0 237
			46	697	0 024
			47.	701	0 251
			48.	702 I M	—
			49.	703	—
			50.	714	—
			51.	702/1 M	0 004
			52.	713	0 170
			53.	714	0.113
			54.	715	0 202
			55.	1639	0 065
			56.	1641	0.081
			57.	1642	0 227
			58.	1643	0.105
			59.	1647	0 041
			60.	1648	0 040
			61	1649	0 097
			62.	1654	0 041
			63.	1660	0.162
			64.	1661/2	0 186
			65	1662	0 065
			66.	1669	0 008
			67.	1671	0 218
			68.	1703	0 016
			69	1973	0 097
			70.	1976	0 162
			71.	1977	0 057

[म O-14016/312/85 जी पी ]

S.O. 2033.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein,

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBI Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village : Unnava; Tehsil : Datia; Distt : Datia (M.P.)		
S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O U in hectare
1	2	3
1.	346	0 016
2.	349	0 008
3.	350/2	0 041
4.	353.	0 332
5.	357	0 105
6.	358	0 137

1	2	3
72.	1978	0.064
73.	1979	0.145
74.	1980	0.049
75.	1985	0.162
76.	1988	0.170
77.	2003/2	0.008
78.	2005	0.121
79.	2006/1	0.105
80.	2007/1	0.227
81.	2010/1	0.121
82.	2011	0.145
83.	2013	0.073
84.	520	0.021
85.	605	0.031
86.	641	0.020
87.	527	0.005
88.	530	0.040
89.	374	0.010
90.	1989	0.020
91.	1674	0.010
92.	2050	0.390
93.	2046	0.020
94.	2047	0.050
95.	2048	0.020
96.	1995	0.010
TOTAL AREA		7.892

[No. O-14016/312/85-GP]

का. आ. 2034.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजिरा में बरेली में जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करने आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राणय एतद्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर साबेर रोड, उज्जैन (म. प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

अनुसूची		
एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट		
ग्राम : बाजना तहसील	बिछौर जिला	शिवपुरी राज्य - मध्यप्रदेश
अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग का अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हैक्टर में)
1	146	0.105
2	147	0.345
3	143	0.031
4	54	0.596
5	55	0.251
6	75	0.021
7	91	0.387
8	92	0.272
9	94	0.262
10	96	0.240
11	97	0.015
12	84	8.481
13	104	0.021
14	103	0.638
15	109 भा.	0.554
16	117	0.251
17	119	0.136
18	120	0.052
19	137	0.094
20	136	0.512
21	135	0.125
22	138	0.021
योग: कुल क्षेत्रफल		5.430

[म. O-14016/313/85-जी. पी.]

S.O. 2034.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Bajana; Tehsil : Picchore; Dist : Shivpuri		
S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectar
1.	146	0.105
2.	147	0.345
3.	143	0.031
4.	51	0.596
5.	55	0.251
6.	75	0.021
7.	91	0.387
8.	92	0.272
9.	94	0.262
10.	96	0.240
11.	97	0.015
12.	84	0.481
13.	104	0.021
14.	103	0.658
15.	109	0.554
16.	117	0.251
17.	119	0.136
18.	120	0.052
19.	137	0.094
20.	136	0.512
21.	135	0.125
22.	138	0.021
TOTAL AREA		5.430

[N.O.—14016/313/85 GP]

का. भा. 2035—यह : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हजौरा से बरेली में जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये ;

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन्डोपाइड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अन्य अथ पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है ;

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर, सावेर रोड, उज्जैन-466001 (म. प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी बलि व्यवसायी को माफत ।

## अनुसूची

## एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम पहाड़ा खर्द तहसील पिछोर जिला शिवपुरी राज्य मध्यप्रदेश		
अनुक्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	831	0.143
2.	844	0.470
3	832	0.042
4	841	0.136
5.	842	0.010
6.	843	0.386
7.	839	0.052
8	439/ 890	0.188
9	811	0.031
10	853	0.073
11.	854	0.324
12.	855	0.251
13.	856	0.491
14.	700	0.073
15.	701	0.157
16.	702	0.240
17.	747	0.240
18.	748	0.073
19.	659	0.188
20	660	0.157
21.	666	0.021
22.	667	0.470
23.	668	0.052
24.	677	0.188
25.	679	0.293
26.	680	0.884
27.	840	0.021
28.	676	0.010
योग कुल क्षेत्रफल		4.864

[स. O-14016 / 314 / 85-जी. पी.]

S.O. 2035.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazura-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Pahara Khurd; Tehsil : Pichhore; Distr. : Shivpuri

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired R.O.U. in hector
1.	831	0.143
2.	844	0.470
3.	832	0.042
4.	841	0.136
5.	842	0.010
6.	843	0.386
7.	839	0.052
8.	439/890	0.188
9.	811	0.031
10.	853	0.073
11.	854	0.324
12.	855	0.251
13.	856	0.491
14.	700	0.073
15.	701	0.157
16.	702	0.240
17.	747	0.240
18.	748	0.073
19.	659	0.188
20.	660	0.157
21.	666	0.021
22.	667	0.470
23.	668	0.052
24.	677	0.188
25.	679	0.293
26.	680	0.084
27.	840	0.021
28.	676	0.010
TOTAL AREA		4.864

[No. O-14016/314/85-GP]

का०मा० 2036 --वतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लाक हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा से बरौली में जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों का बिछाने के प्रयोजन के लिये एनद्राबद्ध भूमि में बंशित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उस उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनद्राबद्ध घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एन०बी०जे० पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सावर रोड, उज्जैन-456001 (म०प्र०) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या कियो कियो व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

## एन०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम --घपीरा तहसील --पिछौर जिला --शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुक्रम०	खसरा न०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	1	3.640
2.	114	0.010
3.	5	0.637
4.	8	0.656
5.	9	0.857
6.	105	0.418
7.	104	0.031
8.	84	0.052
9.	80	0.199
10.	83	0.261
11.	91	0.136
12.	90	0.062
13.	98	0.135
14.	97	0.083
15.	81	0.010
16.	96	0.031
17.	128	0.021
18.	101	0.115
19.	173	0.157
20.	124	0.146
21.	127	0.021
22.	126	0.240
23.	125	0.105
24.	138	0.324
25.	137	0.219
26.	135	0.197
27.	134	0.291
28.	143	0.052
29.	7	0.334

योग --कुल क्षेत्रफल 9.623

[म० O-14016/315/85-जी०पी०]

S.O. 2036.--Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Bardly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

HBJ Pipe Line Project

Village: Ghapaura Tehsil: Pichhore Distt: Shivpuri

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in hector
1.	1	3.640
2.	114	0.010
3.	5	0.637
4.	8	0.656
5.	9	0.857
6.	105	0.418
7.	104	0.031
8.	84	0.052
9.	80	0.199
10.	83	0.261
11.	91	0.136
12.	90	0.062
13.	98	0.135
14.	97	0.063
15.	81	0.010
16.	96	0.031
17.	128	0.021
18.	101	0.115
19.	173	0.157
20.	124	0.146
21.	127	0.021
22.	126	0.240
23.	125	0.105
24.	138	0.324
25.	137	0.219
26.	135	0.397
27.	134	0.294
28.	143	0.052
29.	7	0.334
TOTAL AREA		9.623

[No.-O-14016/315/85-GP]

का प्रॉ. 2037—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयो जन के लिये एतद्विषय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उस भूमि में हितवन् कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष मध्यम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच०बी०जे० पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर सावर रोड, उज्जैन-456001 (म०प्र०) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट. यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

127 GI/85-12

## अनुसूची

एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम हजीरा नहमील भागधर जिला: खालियर राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु० क०	क्षेत्रा म०	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	250	0.774
2.	251/1	0.052
3.	249	0.157
4.	156	0.002
5.	254	0.105
6.	255	0.344
7.	256	0.408
8.	257	0.209
9.	242	0.042
10.	244	0.261
11.	241	0.344
12.	268	0.105
13.	188	0.177
14.	186	0.533
15.	191	0.291
16.	177	0.052
17.	176	0.072
18.	175	0.229
19.	174	0.072
20.	151/1	0.177
21.	172	0.147
22.	173	0.020
23.	171	0.324
24.	169	0.030
25.	170	0.209
26.	167	0.020
27.	166	0.314
28.	164	0.177
29.	165	0.053
30.	77	0.052
31.	80	0.314
32.	81	0.910
33.	74	0.020
कुल क्षेत्रफल		6.095

[म. O-14016/316/85-—हॉ० पी०]

S.O. 2037.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M P).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

## SCHEDULE

HBJ Gas Pipe Line Project  
Village: Dejapara Tehsil: Bhandar Distt: Gwalior

S No	Survey No	Area to be Acquired for R.O U in Hecter
1	250	0 774
2	251/1	0 052
3	249	0 157
4	156	0 002
5	254	0 105
6	255	0 344
7	256	0 408
8	257	0 209
9	242	0 042
10	244	0 261
11	241	0 344
12	268	0 105
13	188	0 177
14	186	0 533
15	191	0 291
16	177	0 052
17	176	0 072
18	175	0 229
19	174	0 072
20	151/1	0 177
21	172	0 147
22	173	0 020
23	171	0 324
24	169	0 030
25	170	0 209
26	167	0 020
27	166	0 314
28	164	0 177
29	165	0 052
30	77	0 052
31	80	0 314
32	81	0 010
33	74	0 020
TOTAL AREA		6 095

[No O-14016/316/85-GP]

का आ — 2038 यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्प्राबद्ध भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय

सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बर्तन में कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच बी जे पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर साधर रोड, उज्जैन-456001 (म प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत। यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माध्यम से।

## अनुसूची

एच बी जे गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम तेहरी तहसील पिछार जिला गिबपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु. क्र. खसरा नं. / उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

1	2	3
1	85	0 408
2	87	0 010
3	80	0 240
4	109	0 052
5	79	0 073
6	103	0 209
7	102	0 105
8	105	0 084
9	104	0 146
10	106	0 418
11	123	0 010
12	142	0 021
13	91	0 010
14	141	0 188
15	138	0 094
16	139	0 334
17	110	0 136
18	126	0 125
19	129	0 199
20	497	0 021
21	496	0 262
22	127	0 167
23	125	0 105
24	125	0 397
25	124	0 543
26	111	0 428
27	213	0 052
28	430	0 115
29	416	0 512
30	447	0 240
31	434	0 251
32	441	0 146
33	450	0 167
34	451	0 428
35	452	0 031
36	503	0 282
37	499	0 449
38	498	0 272

1	2	3
39.	504	0.178
40.	500	0.387
41.	522	0.010
42.	493	0.011
43.	194	0.053
44.	536	0.031
45.	495	0.188
46.	492	0.555
47.	611	0.052
48.	610	0.199
49.	613	0.387
50.	617	0.314
51.	615	0.157
52.	616	0.418
53.	682	0.157
54.	701	0.010
55.	702	0.042
56.	703	0.021
57.	698	0.136
58.	691	0.157
59.	694	0.094
60.	684	0.997
61.	685	0.687
62.	706	0.125
63.	707	0.053
64.	109	0.021
65.	712	0.418
66.	693	0.105
67.	692	0.272
68.	683	0.345
69.	445	0.052
योग :- कुल क्षेत्रफल		14.362

[सं. O-1401 / 317/85 जी.पी.]

S.O. 2038.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE		
HBJ GAS PIPE LINE PROJECT		
Village : Tehari Tehsil : Pichhore, Distt : Shivpuri		
S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U in Hectar
1	2	3
1.	85	0.408
2.	87	0.010
3.	80	0.240
4.	108	0.052
5.	79	0.073
6.	103	0.209
7.	102	0.105
8.	105	0.084
9.	104	0.146
10.	106	0.418
11.	123	0.010
12.	142	0.021
13.	91	0.010
14.	141	0.188
15.	138	0.094
16.	139	0.334
17.	140	0.136
18.	126	0.125
19.	129	0.199
20.	497	0.021
21.	496	0.262
22.	127	0.167
23.	125	0.105
24.	128	0.397
25.	125	0.543
26.	111	0.428
27.	213	0.052
28.	430	0.115
29.	446	0.512
30.	447	0.240
31.	434	0.251
32.	444	0.146
33.	450	0.167
34.	451	0.428
35.	452	0.031
36.	503	0.282
37.	499	0.449
38.	498	0.272
39.	504	0.178
40.	500	0.387
41.	522	0.010
42.	493	0.011
43.	494	0.053
44.	536	0.031
45.	495	0.188
46.	492	0.555
47.	611	0.052
48.	610	0.199
49.	613	0.387
50.	617	0.314
51.	615	0.157
52.	616	0.418
53.	682	0.157
54.	701	0.010
55.	702	0.042
56.	703	0.021
57.	698	0.136
58.	691	0.157

1	2	3
59.	694	0.094
60.	684	0.997
61.	685	0.687
62.	706	0.125
63.	707	0.053
64.	109	0.021
65.	712	0.418
66.	693	0.105
67.	692	0.272
68.	683	0.345
69.	445	0.052
TOTAL AREA		14.362

[No. O 1416/317/85GP]

का. आ. 20 39.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में हुजौरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्प्राबन्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वस्तुतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के मोचे पाइप लाइन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच. बी. जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर साबेर रोड, उज्जैन-466001 (म. प्र.) इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्रामः सालोन (भरौली) तहसीलः भाण्डेर जिलाः ग्वालियर राज्य (म. प्र.)		
अ.सू. क्र.	खसरा नं.	उपयोग का अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	2	3
1.	71	0.031
2.	64	0.560
3.	67	0.167
4.	143	0.002
5.	68	0.042
6.	66	0.031
7.	96	0.084
8.	144	0.042
9.	145	0.082
10.	146	0.229
11.	147	0.031

1	2	3
12.	158	0.178
13.	14	0.035
14.	159	0.031
15.	162	0.199
16.	167	0.188
17.	118	0.020
18.	169	0.199
19.	170	0.052
20.	171	0.157
21.	32	0.115
22.	34	0.002
23.	33	0.073
24.	10	0.157
25.	28	0.010
26.	27	0.209
27.	24	0.229
28.	13	0.293
29.	1	0.115
30.	36	0.002
31.	157	0.005
योग कुल क्षेत्रफल		3.550

[सं. O-14016/318/85— जी पी]

S.O. 2039.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided, that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipe Line, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village: Salon (Bharoli) Tehsil: Bhandar Distt. Gwalior		
S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	71	0.031
2.	64	0.560
3.	67	0.167
4.	143	0.002
5.	68	0.042
6.	66	0.031
7.	96	0.084
8.	144	0.042
9.	145	0.082



1	2	3
10.	146	0.229
11.	147	0.031
12.	158	0.178
13.	14	0.035
14.	159	0.031
15.	162	0.199
16.	167	0.188
17.	168	0.020
18.	169	0.199
19.	171	0.052
20.	171	0.157
21.	32	0.115
22.	34	0.002
23.	33	0.073
24.	10	0.157
25.	28	0.010
26.	27	0.209
27.	24	0.229
28.	13	0.293
29.	1	0.115
30.	36	0.002
31.	157	0.005
TOTAL AREA		3.550

No. O-14016/318/85-GP]

का.आ. 1040.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजोरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर साबेर रोड, उज्जैन-456001 (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

## एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : बहैरा	तहसील : पिछोर	जिला : शिवपुरी	राज्य (मध्य प्रदेश)
अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स) में	
1.	16	0.784	
2.	3	0.142	
3.	2	0.052	
4.	1	0.548	
5.	17	0.167	
योग : क्षेत्रफल		1.693	

[मं. O-14016/319/85-जी पी]

S.O. 2040.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ, Gas Pipe Line, 45, Subash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Badera		Tehsil Pichhore Distt. Shivpuri
S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	16	0.784
2.	3	0.142
3.	2	0.052
4.	1	0.548
5.	17	0.167
TOTAL AREA		1.893

[No. 14016/319/85-GP]

का.आ. 2041.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजोरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाइन, 45, सुभाष नगर साबेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम भवन्हार	तहसील: पिछोर जिला, शिवपुरी राज्य (मध्य प्रदेश)
अनु. क्र./ खमरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	5
2.	4
3.	6
4.	10
5.	11
6	12
7.	13
8.	38
9.	37
10.	39
11	40
12.	41
13.	32
14.	33
15.	27
16.	436
17.	386
18.	437
19.	438
20.	440
21.	441
22.	442
23.	443
24.	444
25.	552
26.	553 मी.
योग : कुल क्षेत्रफल	5.026

[सं. 14016/320/85-जीपी]

S.O. 2041.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barielly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ, Gas Pipe Line, 45, Subash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village	Bhanwarhar	Tehsil	Pichhore	Distt.	Shivpuri
S.No	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare			
1.	5				0.031
2.	4				1.097
3.	6				0.219
4.	10				0.136
5.	11				0.010
6.	12				0.178
7.	13				0.188
8.	38				0.094
9.	37				0.157
10.	39				0.031
11.	40				0.188
12.	41				0.115
13.	32				0.031
14.	33				0.251
15.	27				0.585
16.	436				0.136
17.	386				0.021
18.	437				0.031
19.	438				0.084
20.	440				0.063
21.	441				0.010
22.	442				0.513
23.	443				0.105
24.	444				0.125
25.	552				0.418
26.	553 M.				0.209
TOTAL AREA					5.026

[No.-14016/320/85-GP]

का. आ. 2042.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजिरा से बरेली में जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जाना चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जन करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा पदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जन करने का अपना आणय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मग्न प्राधिकरण, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर सावर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाही व्यक्तिगत रूप से हो या किमा विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

एच बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम निमघना	तहसील पिछोर	जिला शिवपुरा	राज्य मध्य प्रदेश
अनुक्र	खसरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)	
1	1	0 042	
2	2	0 136	
3	3	0 240	
4	4	0 261	
5	5	0 115	
6	6	0 105	
7	20	0 094	
योग कुल क्षेत्रफल		0.993	

[स. 4016/321/85-जा.प.]

S.O. 2042.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagd shpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ, Gas Pipe Line, 45, Subash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPELINE PROJECT,

Village : Nimghana Tehsil : Pichhore Distt. : Shivpuri

S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R O U in Hectore
1.	1	0 042
2.	2	0 136
3.	3	0 240
4.	4	0 261
5.	5	0 115
6.	6	0 105
7.	20	0 094
TOTAL AREA		0 993

[No 14016/321/85-GP]

का आ 2043—यह केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य द्वारा से बरेल में जगदीशपुर तक पेट्रोलियम व परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा बिछाई जाना चाहिए।

और यह यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए एन.एन.टी. अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 का उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन.एन.टी. घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में जितना कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आशेष महाम प्राधिकरण, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एवं बी.जे. पाइप लाइन 45, सुभाष नगर, सावर रोड, उज्जैन 456001 (म.प्र.) का इस अधिसूचना के तारिख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आशेष करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भा.कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत।

## अनुसूची

एच बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम मेमरो	तहसील पिछोर	जिला शिवपुरा	राज्य मध्य प्रदेश
अनुक्र	खसरा न	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)	
1	89	0 178	
2	86	0 084	
3	89	0 084	
4	102	0 010	
5	103	0 157	
6	104	0 073	
7	105	0 178	
8	107	0 010	
9	77	0 575	
10	111	0 021	
11	130	0 461	
12	131	0 031	
13	132	0 073	
14	133	0 031	
15	140	0 021	
16	135	0 105	
17	136	0 091	
18	137	0 073	
19	138	0 115	
20	139	0 052	
21	162	0 272	
22	164/1	0 157	
23	164/1	0 094	
24	173	0 031	
25	174/1	0 157	
26	174/1	0 178	
27	23	0 042	
योग कुल क्षेत्रफल		3 157	

[स. 14016/322/85/जे.पी.]

S.O. 2043.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ, Gas Pipe Line, 45, Subash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Semari Issagarh Teshil Picchore Distt. Shivpuri		
S.No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectar
1.	88	0.178
2.	86	0.084
3.	89	0.084
4.	102	0.010
5.	103	0.157
6.	104	0.073
7.	105	0.178
8.	107	0.010
9.	77	0.575
10.	111	0.021
11.	130	0.261
12.	131	0.031
13.	132	0.073
14.	133	0.031
15.	140	0.021
16.	135	0.105
17.	136	0.094
18.	137	0.073
19.	138	0.115
20.	139	0.052
21.	162	0.272
22.	163/1	0.157
23.	163/3	0.094
24.	173	0.031
25.	174/4	0.157
26.	174/1	0.178
27.	23	0.042
TOTAL AREA		3.157

[No.-14016/322/85 GP]

क्र.अ. १०४१-यत केन्द्रिय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में तृतीया से बरेला, जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए गैस पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए एन.एन.एल.अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब रीटर्नियस और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन.एन.एल. घोषित किया है।

वर्णन कि उक्त भूमि में हितवादी कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सज्जम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच बी जे पाइपलाइन, 45, सुभाष नगर सान्वर रोड, उज्जैन 456001 (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकता है।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चित यह भी कथन करेगा कि वहाँ वह यह चाहता है कि उसकी मुवकाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

##### एच.बी.जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम	माहवा कामगोन तहसील	पिछोर जिला	शिवपुरी राज्य . मध्य प्रदेश
अनु क्र	खसरा न	उपयोग	अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3	
1	2046		0.031
2	2053		0.188
3	2057		0.366
4	2058		0.261
5	2059		0.167
6.	2202		1.000
7	2070		0.170
8	2291		0.031
9	2294		0.082
10	2124		0.648
11.	2123		0.209
12	2121		0.230
13.	2175		0.031
14	2176		0.292
15	2147		0.366
16	2150		0.240
17.	2151		0.321
18	2269		0.021
19	2268		0.010
20	2270		0.042
21.	2271		0.261
22	2283		0.021
23	2145		0.355
24	2221		0.116
25.	2223		0.073
26	2225		0.063
27	2227		0.115
28	2228		0.115
29	2219		0.073
30	2261		0.010

1	2	3	1	2	3
31.	2265	0.209	21.	2271	0.261
32.	2277	0.314	22.	2283	0.021
33.	2278	0.105	23.	2148	0.355
34.	2281	0.105	24.	2224	0.146
35.	2296	0.063	25.	2223	0.073
36.	2297	0.031	26.	2225	0.063
37.	2295	0.031	27.	2227	0.115
38.	2054	0.052	28.	2228	0.115
39.	2064	0.021	29.	2229	0.073
40.	2226	0.010	30.	2264	0.010
योग : कुल क्षेत्रफल		7.182	31.	2265	0.209
		[सं. 14016/323/85-जी पी]	32.	2277	0.314
			33.	2278	0.105
			34.	2281	0.105
			35.	2296	0.063
			36.	2297	0.031
			37.	2295	0.031
			38.	2054	0.052
			39.	2064	0.021
			40.	2226	0.010
			TOTAL AREA		7.182

[No. 14016/323/85-GP]

S.O. 2044.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ, Gas Pipe Line, 45, Subash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village Mohaba Darmone Tehsil Pichhore Distt. Shivpuri

S.No. Survey No. Area to be Acquired for R.O.U. in Hecter

1	2	3
1.	2046	0.031
2.	2053	0.188
3.	2057	0.366
4.	2058	0.261
5.	2059	0.167
6.	2292	1.000
7.	2070	0.470
8.	2291	0.031
9.	2294	0.082
10.	2124	0.648
11.	2123	0.209
12.	2121	0.230
13.	2175	0.031
14.	2176	0.292
15.	2147	0.366
16.	2150	0.240
17.	2151	0.324
18.	2269	0.021
19.	2268	0.010
20.	2270	0.042

का.आ. 2045.—यस: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्यप्रदेश राज्य में मूर्जारा से धरेली से जगदीशपुर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि० द्वारा बिछाई जानो चाहिये।

और यस: यह प्रतीत होता है कि ऐसी साधनों को बिछाने के प्रयो-जन के लिये एतद्पाषाण अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सभ्य प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग एच.बी.जी. पाइप लाइन 45, मुभाष नगर सांवेर रोड उज्जैन-456001 (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और जेना आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत. यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

अनुसूची		
एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट		
ग्राम—भवरगढ़ तहसील—पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य—मध्य प्रदेश		
अनु/क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1	5	0.261
2	6	0.909
3	9	0.533
4	10	0.355
5	11	0.334
6	12	0.533
7	21	0.460
8	26	0.679
9	26/48	0.105
10	23	0.052
11	24	0.084
12	1	0.021
योग-- कुल क्षेत्रफल		4.326

[स. 14016/324/85-जी पी]

S.O. 2045.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village—Bhawargarh Tehsil—Pichhore Distt.—Shivpuri

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecter
1.	5	0.261
2.	6	0.909
3.	9	0.533
4.	10	0.355
5.	11	0.334
6.	12	0.533
7.	21	0.460
8.	26	0.679
9.	26/48	0.105
10.	23	0.052
11.	24	0.084
12.	1	0.021
TOTAL AREA		4.326

[No. 14016/324/85-GP]

का.आ. 2046.—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक कि मध्य प्रदेश राज्य में हज़ीरा से बरेली से जगदीशपुरी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग अधिकार अर्जन करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जन करने का अपन, आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइपलाइन 45, सुभाष नगर, सावर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 450001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निर्निश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सूचनाई व्यक्तिगत हो या किसी बिधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

## एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : पगरा तहसील : पिछोर जिला : शिवपुरी राज्य : मध्य प्रदेश

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1.	75	0.092
2	233	0.021
3.	76	0.941
4.	71	0.502
5.	64	0.063
6	63	0.084
7	66	0.021
8	57	0.021
9	62	0.449
10.	185	0.021
11.	186	0.031
12	187	0.021
13.	222	0.031
14	227	0.105
15.	234	0.021
16.	228	0.084
17.	232	0.084
18.	230	0.031
19	231	0.136
20.	242	0.084
21.	239	0.072
22	243	0.021
23	247	0.240
24	246	0.355
25.	248	0.042
26	270	0.063
27.	210	0.177

1	2	3
28	209	0.219
29	208	0.219
30	206	0.261
31	274	0.586
32	273	0.125
33	60	0.031
योग :- क्षेत्रफल		5.254
[No. O-14016/325/85-G.P.]		

S.O. 2046.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum for Hazira—Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipe line should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas, Commissioner, HBJ Gas Pipeline, 45, Subhash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village—Pagara	Tehsil—Pichhore	Distt. Shivpuri
Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R. O. U. in Hecter
1.	75	0.092
2.	233	0.021
3.	76	0.941
4.	71	0.502
5.	64	0.063
6.	63	0.084
7.	66	0.021
8.	57	0.021
9.	62	0.449
10.	185	0.021
11.	186	0.031
12.	187	0.021
13.	222	0.031
14.	227	0.105
15.	234	0.021
16.	228	0.084
17.	232	0.084
18.	230	0.031
19.	231	0.136
20.	242	0.084
21.	239	0.072
22.	243	0.021
23.	247	0.240
24.	246	0.355

1	2	3
25.	248	0.042
26.	270	0.063
27.	210	0.177
28.	209	0.219
29.	208	0.219
30.	206	0.261
31.	274	0.586
32.	273	0.125
33.	60	0.031
TOTAL AREA		5.254
[No. O-14016/325/85-GP]		

का.आ. 2047 :—यह केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि वास्तव में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हरजोरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राकृतिक गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जाना चाहिये।

और यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों का बिछाने के प्रयोजन के लिये एन्ड्रुवावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन्ड्रुवावद्ध घोषित किया है।

बताने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप महम प्राधिकरण, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइपलाइन 45, सुभाष नगर, मांवेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफ़त।

अनुसूची

एच.बी.जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—बिलोदरा तहसील—पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य—मध्य प्रदेश

अनु. क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	145	0.690
योग :- कुल क्षेत्रफल		0.690

[म. O-14016/326/85-जीपी]

S.O. 2047.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira—Bareilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline 45, Subash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### HBJ GAS PIPELINE PROJECT

Village—Ghilodra Tehsil—Pichore Distt.—Shivpuri

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectar
1.	145	0.690
TOTAL AREA		0.690

[No. O-14046/326/85-GP]

का. आ. 2048.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में हजौरा से बरेली से जगदीशपुर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपलब्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

यद्यपि कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सहम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, एच.बी.जे. पाइपलाइन 45, सुभाष नगर, साबेर रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456001 को इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी प्रत्यन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की सार्फत।

#### अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

ग्राम—पहड़ा कला तहसील—पिछोर जिला—शिवपुरी राज्य—मध्य प्रदेश

अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	459	0.532
2.	465	0.125
3.	466	0.209
4.	467	0.261
5.	447	0.157
6.	448	0.011
7.	578	0.156
8.	579	0.324
9.	588	0.355
10.	590	0.146
11.	591	0.125

1	2	3
12.	592	0.064
13.	593	0.199
14.	632	0.387
15.	634	0.627
16.	633	0.063
17.	643	0.166
18.	644	0.240
19.	635/3	0.063
20.	572	0.010
21.	635/4	0.219
22.	642/11	0.282
23.	642/1	0.314
24.	642/2	0.105
25.	642/3	0.073
26.	642/4	0.115
27.	60	0.084
28.	635/5	0.042
29.	642/5	0.021
योग :— कुल क्षेत्रफल		5.475

[सं. O-14016/327/85-जी.पी.]

S.O. 2048.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Hazira-Barilly to Jagdishpur in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, HBJ Gas Pipeline 45, Subash Nagar, Sanwer Road, Ujjain (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

##### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village—Pahara Kala Tehsil—Pichore Distt.—Shivpuri

S.No.	Survey No.	Area to be Aquired for R.O.U. in Hectar
1.	459	0.532
2.	465	0.125
3.	466	0.200
4.	467	0.261
5.	447	0.157
6.	448	0.011
7.	578	0.156
8.	579	0.324
9.	588	0.355
10.	590	0.146
11.	591	0.125



1	2	3
12.	592	0.064
13.	593	0.199
14.	632	0.387
15.	634	0.627
16.	633	0.063
17.	643	0.166
18.	644	0.240
19.	635/3	0.063
20.	572	0.010
21.	635/4	0.219
22.	642/11	0.282
23.	642/1	0.314
24.	642/2	0.105
25.	642/3	0.073
26.	642/4	0.115
27.	60	0.084
28.	635/5	0.042
29.	642/5	0.021
TOTAL AREA		5.475

[No 14016/327/85 G.P.]

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1985

का. आ. 2049.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3740 तारीख 17.11.84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे रही है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की उपधारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

## अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लॉट नं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	भूलेमउ	218/1	0-810-
				219	0-2-0

1	2	3	4	5	6
				221	0-1-0
				443	0-0-15
				220	0-9-0
				224	1-10-0
				372	0-14-0
				229	0-11-5
				389	0-6-0
				230	0-2-10
				241	0-4-15
				239	0-1-0
				243	0-14-0
				240	0-1-0
				357	0-0-10
				365	0-10-10
				367	0-3-5
				396	0-1-0
				381 kha	0-6-0
				363	0-1-0
				366	0-3-5
				371	0-15-10
				381/ka	0-3-10
				834	0-10-0
				838	0-2-0
				839	0-6-0
				380	0-6-0
				387	0-11-10
				388	0-2-0
				390	0-7-0
				391	0-15-10
				444	0-2-0
				447	1-11-0
				448	0-13-10
				449	0-9-0
				840	0-12-0
				842	0-3-15
				845	0-4-0
				843	0-6-0
				844	0-2-10
				386	0-0-10

[सं. O 14016/53/84-जी पी]

New Delhi, the 29th April, 1985

S.O. 2049.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3740 dated 6-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central

Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Hajira	Barrielly	Jogdeshpur	Pipe	Line Project	
Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Required
1	2	3	4	5	6
Unnav	Purva	Purva	Bhulamou	218/1	0-8-10
				219	0-2-0
				221	0-1-0
				443	0-0-15
				220	0-9-0
				224	1-10-0
				372	0-14-0
				229	0-11-5
				389	0-6-0
				230	0-2-10
				241	0-4-15
				239	0-1-0
				243	0-14-0
				240	0-1-0
				357	0-0-10
				365	0-10-10
				367	0-3-5
				396	0-1-0
				381/Kha	0-6-0
				363	0-1-0
				366	0-3-5
				371	0-15-10
				381/Kha	0-3-10
				834	0-10-0
				838	0-2-0
				839	0-6-0
				380	0-6-0
				387	0-11-10
				388	0-2-0
				390	0-7-0
				391	0-15-10
				444	0-2-0
				447	1-11-0
				448	0-13-10
				449	0-9-0
				840	0-12-0
				842	0-3-15
				845	0-4-0
				843	0-6-0
				844	0-2-10
				386	0-0-10

[N.O. 14016/53/84—G.P.]

का आ. 1050—यत्. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. स. 3453 तारीख 3-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यत् सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

#### अनुसूची

#### हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	पारगना	ग्राम का नाम	प्लॉट नं.	विमा. नं. रकबा
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	बेहटा	797	1-0-10
				795	0-6-10
				798	0-9-17
				796	0-7-16
				808	0-13-0
				804	0-2-5
				829	0-12-7
				830	0-15-12
				835/1	0-19-5
				836	0-9-15
				837	0-4-16
				839	0-7-13
				840	0-2-0
				841	0-1-10
				986	0-7-5
				988	0-7-0
				991/4, 5	0-13-5
				1029	0-3-0
				1024	0-3-10
				1028	0-16-10
				1027	0-3-8
				1026	0-0-10
				1025	0-10-15
				806	0-0-10
				788	0-0-5
				827	0-0-5
				992	0-1-16

[स. O-14016/50/81—जी. पी.]

S.O. 2050.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3453 dated 3-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared

its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और आगे यतः केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तन शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निर्णय लेती है, कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

#### हाजिरा बरेली अणवीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

SCHEDULE					
Hajira	Barrielly	Jogdeshpur	Pipe line	Project	
Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No	Area Required
1	2	3	4	5	6
Unnav	Unnav	Hadha	Behta	797	1-0-10
				795	0-6-10
				798	0-9-17
				796	0-7-16
				808	0-13-0
				804	0-2-5
				829	0-12-7
				830	0-15-12
				835/1	0-19-5
				836	0-9-15
				837	0-4-16
				839	0-7-13
				840	0-2-0
				841	0-1-10
				986	0-7-5
				988	0-7-0
				991/4, 5	0-13-5
				1029	0-3-0
				1024	0-3-10
				1028	0-16-10
				1027	0-3-8
				1026	0-0-10
				1025	0-10-15
				806	0-0-10
				788	0-0-5
				827	0-0-5
				992	0-1-16

[No. O-14016/56/84-GP]

का. प्रा. 2051.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पदार्थलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) (अधिनियम 1962) (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का अधिसूचना का प्रा. म. 3898 तारीख 24-11-84 द्वारा केंद्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था,

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लॉट	नियोज्य रकबा
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	उन्नाव	हड्डा	हटौली	185	1-16-13
				192	0-18-0
				193	0-7-18
				194	0-2-0
				195	0-3-12
				196	1-2-16
				199	0-3-0
				201	0-5-0
				218	0-4-0
				219	0-2-15
				222	0-1-6
				223	0-10-10
				224	0-5-2
				225	0-0-5
				288	0-0-12
				300	0-14-10
				301	0-6-0
				300	0-15-0
				311	0-9-18
				317	1-2-3
				318	0-1-5
				320	0-1-12
				321	0-2-5
				322	0-10-15
				323	0-1-0
				336	0-0-5
				337	0-6-18
				338	0-10-10
				339	1-3-14
				343	0-7-1
				1047	0-0-18
				1053	0-7-16

1	2	3	4	5	6	7
				1054	0-9-0	
				1058	0-1-5	
				1059	0-9-12	
				1063	1-3-14	
				1064	0-0-12	
				1068	0-0-2	
				1073	0-0-18	
				1075	0-17-14	
				1077	0-1-4	
				1078	0-7-16	
				1083	2-1-18	
				1090	0-7-4	
				1144	0-6-0	
				1145	1-19-0	
				1158	0-5-17	
				1160	0-0-10	
				1162	0-6-0	
				1163	0-10-16	
				1164	2-1-0	
				1173	0-11-0	
				1161	2-5-11	
				1176	0-8-8	
				1179	1-2-5	
				1184	0-0-12	
				1185	2-4-5	
				1188	0-5-8	
				1146	1-0-14	
				344	0-0-5	
				1044	0-0-10	
				1079	0-0-10	
				1178	0-0-5	

[सं O—14016/236/84—जे.पी.]

S.O. 2051.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3898 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to the notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

SCHEDULE					
Hajira	Bareilly	Jagdish	Pipe	line	Project
Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Unnao	Unnao	Harapa	Itauli	185	1-16-13
				192	0-18-0
				193	0-7-18
				194	0-2-0
				195	0-3-12
				196	1-2-16
				199	0-3-0
				201	0-5-0
				218	0-4-0
				219	0-2-15
				222	0-1-6
				223	0-10-10
				224	0-5-2
				225	0-0-5
				288	0-0-12
				300	0-14-10
				301	0-6-0
				300	0-15-0
				311	0-9-18
				317	1-2-3
				318	0-1-5
				320	0-1-12
				321	0-2-5
				322	0-10-15
				323	0-1-0
				336	0-0-5
				337	0-6-18
				338	0-10-10
				339	1-3-14
				343	0-7-4
				1047	0-0-10
				1053	0-7-16
				1054	0-9-0
				1058	0-1-5
				1059	0-9-12
				1063	1-3-14
				1064	0-0-12
				1068	0-0-2
				1073	0-0-18
				1075	0-17-14
				1077	0-1-4
				1078	0-7-16
				1083	2-1-18
				1090	0-7-4
				1144	0-6-0
				1145	1-19-0
				1158	0-5-17
				1160	0-0-10
				1162	0-6-0
				1163	0-10-16
				1164	2-1-0
				1173	0-11-0
				1161	2-5-11
				1176	0-8-8
				1179	1-2-5
				1184	0-0-12
				1185	2-4-5
				1188	0-5-8
				1146	1-0-14
				344	0-0-5
				1044	0-0-10
				1079	0-0-10
				1178	0-0-5

[No. O-14016/236/84-GP]

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

का. भा. 2052 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3710, तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राप्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इन अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इन अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियां में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निश्चय देती है कि उक्त अधिकार केन्द्रिय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. से सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, बांधपा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम पिटोल खुरद तहसील—झाबुआ जिला—झारखण्ड राज्य (मध्य-प्रदेश)

क्र. सं. खसरा नं. उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेरों में)

1.	13	0-016
2.	14	0-026
3.	16	0-194
4.	15	0-040
5.	17	0-344
6.	18	0-065
7.	19	0-053
8.	23	0-021
9.	24	0-045
10.	25	0-186
11.	26	0-016
12.	30	0-219
13.	27	0-105
14.	31	0-291
15.	32	0-154
16.	89	0-016
17.	90	0-081
18.	92/2	0-142
19.	91	0-251
20.	97	0-324

कुल क्षेत्रफल :— 2-569

[नं. O-14016/172/84-बी.पी.]

New Delhi, the 26th April, 1985

S.O. 2052.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3710 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Name of Village—Pitol Khurd Tehsil—Zabua Distt.—Zabua

S.No. Survey No. Area to be Acq.

for R. O. U in

Hectares

1.	13	0.016
2.	14	0.026
3.	16	0.194
4.	15	0.040
5.	17	0.344
6.	18	0.065
7.	19	0.053
8.	23	0.021
9.	24	0.045
10.	25	0.186
11.	26	0.016
12.	30	0.219
13.	27	0.105
14.	31	0.291
15.	32	0.154
16.	89	0.016
17.	90	0.081
18.	92/2	0.142
19.	91	0.251
20.	97	0.324

TOTAL AREA

.569

[No. O-14016/172/84-GP]

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1985

का. भा. 2053 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3809 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राप्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

#### हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	प्लॉट सं०	लिया गया रकबा
कानपुर	अकबरपुर	अकबरपुर	असंख्य	90	0-1-4
बेहात	पुर	पुर		91	0-10-10
				89	0-6-0
				88	0-9-0
				87	0-14-0
				86	0-5-10
				82	2-2-0
				83	0-7-0
				71	0-1-0
				78	6-14-0
				187	2-11-0
				190	1-6-0
				212	0-0-13
				213	0-1-7
				241	0-19-10
				231	0-2-10
				232	1-10-0
				230	1-12-10
				296	0-5-0
				223	0-0-17
				224	0-9-2
				297	3-16-0
				299	1-19-0
				392	0-0-13

[सं. O-14016/194/84-जी.पी.]

New Delhi, the 29th April, 1985

S.O. 2053.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3802 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

#### Hasira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Required
Kanpur	Akbarpur	Akbarpur	Asanda	90	0-1-4
Dehat				91	0-10-10
				89	0-6-0
				88	0-9-0
				87	0-14-0
				86	0-5-10
				82	2-2-0
				83	0-7-0
				71	0-1-0
				78	6-14-0
				187	2-11-0
				190	1-6-0
				212	0-0-13
				213	0-1-7
				241	0-19-10
				231	0-2-10
				232	1-10-0
				230	1-12-10
				296	0-5-0
				223	0-0-17
				224	0-9-2
				297	3-16-0
				299	1-19-0
				392	0-0-13

[No. O-14016/194/84-GP]

का० प्रा० 2054 :-- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० प्रा० सं० 3803 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

##### हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं०	लिया गया क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
कानपुर	अकबर-पुर	अकबर-पुर	मुबारक-पुर	1046	2- -
देहात			लाटा		
				1042	- - 5
				1041	मि.- 2-
				1040	1-12-
				1038	- 5-
				1039	- 2 5
				1032	- - 5
				1030	- 5-
				1029	- 2-
				1028	- 17-

[सं. O- 14016/195/84-जीपी]

S.O. 2054.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3803 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### Hajira—Barielly—Jagdishpur Pipe Line Project

Dist.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur	Akbar-	Akbar-	Muwarak	1046	2- -
Dehat	pur	pur	pur Laa	1042	- - -
				1041	M. 2-
				1040	1-1-2
				1038	- 5-
				1039	-2-5
				1032	- -5
				1030	-5-
				1029	-2-
				1028	-17-

[No. O-14016/195/84-GP]

का. भा. 2055: --यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मन्त्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3804 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

##### हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
कानपुर	अकबर-पुर	अकबर-पुर	करबक	933	1- 5- 0
देहात	पुर	पुर			
				937	0- 0- 4
				948	1- 0- 0
				949	0- 14- 0
				950	1- 5- 0
				780	0- 4- 5
				781	0- 6- 0
				782	0- 17- 15

[सं. O- 14016/196/84-जीपी]

S.O. 2055.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3804 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### Hajira Barielly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Kanpur	Akbarpur	Akbarpur	Karbak	933	1-5-0
Dohat				937	0-0-4
				948	1-0-0
				949	0-14-0
				950	1-5-0
				780	0-4-5
				781	0-6-0
				782	0-17-15

[No. O-14016/196/84—GP]

बई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

का. सा 2055:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) का धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कां. प्रां. सं. 3712 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का धपना प्रामाण्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और धाते, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और धाते उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सहायता प्राप्त से मुक्त रूप में, बोधना के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. ओ. गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट

घाम बाबड़ी तहसील पेटनाबद विभागा बाबुघा राज्य (मध्य-प्रदेश)

अनु. क्र.	खसरा नं०	उपयोग का क्षेत्र (हैक्टर में)
1	2	3
1.	840	0-150
2.	841	0-344
3.	843	0-016
4.	844	0-042
5.	847/1	0-219
	846/1	
6.	847/2	0-150
	846/2	
7.	845	0-049
8.	855	0-275
9.	856	0-243
10.	848	0-008
11.	884	0-358
12.	886	0-281
13.	927	0-101
14.	928	0-024
15.	882/3	0-332
16.	882/2	0-010
17.	981	0-004
18.	982	0-283
19.	885	0-020
20.	934	0-085
	935	
21.	936	0-037
22.	938	0-405
23.	945	0-004
24.	947	0-332
25.	948	0-032
26.	953	0-020
27.	954	0-126
28.	939/2	0-016
29.	887	0-008
30.	949	0-340
31.	459/2	0-004
32.	915	0-194
33.	947	0-008
34.	321	0-040
35.	592	0-178
36.	900	0-080
37.	593	0-154
	595	0-032
38.	507	0-016
39.	506	0-008
40.	510	0-073
41.	513	0-032
42.	512	0-170
43.	508	0-024



1	2	3	1	2	3
44	451	0-243	6.	846/1	
45.	476	0-210		847/2	0.150
46.	588	0-040		846/2	
47	883	0-040	7.	845	0.049
48.	477	0-008	8.	855	0.275
49	475	0-210	9.	856	0.243
50	460	0-486	10.	848	0.008
51.	464	0-028	11.	884	0.356
52.	457	0-032	12.	886	0.291
53	474	0-016	13.	927	0.101
54.	461	0-028	14.	928	0.024
55.	505	0-028	15.	882/3	0.332
56	462/2	0-028	16.	882/2	0.010
57.	421	0-012	17.	931	0.004
58	420	0-186	18.	932	0.283
59.	405/1	0-275	19.	885	0.020
60	400	0-040	20.	934	0.085
61.	397	0-016		935	
62.	401	0-316	21.	936	0.037
63.	398	0-291	22.	938	0.405
योग कुल क्षेत्रफल . ---		7-808	23.	945	0.004
			24.	947	0.332
			25.	948	0.032
			26.	953	0.020
			27.	954	0.126
			28.	939/2	0.016
			29.	557	0.008
			30.	949	0.340
			31.	459/2	0.004
			32.	615	0.194
			33.	647	0.008
			34.	321	0.040
			35.	592	0.178
			36.	600	0.030
			37.	593	0.154
				595	0.032
			38.	507	0.016
			39.	506	0.008
				510	0.073
			40.	513	0.032
			41.	512	0.170
			42.	508	0.024
			43.	451	0.243
			44.	476	0.210
			45.	588	0.040
			46.	883	0.040
			47.	477	0.008
			48.	475	0.210
			49.	460	0.486
			50.	464	0.028
			51.	457	0.032
			52.	474	0.016
			53.	461	0.028
			54.	505	0.028
			55.	462/2	0.028
			56.	421	0.012
			57.	420	0.186
			58.	405/1	0.275
			59.	400	0.040
			60.	397	0.016
			61.	401	0.316
			62.	398	0.291
			Total Area		7.808

[स. O-14016/200/84-जीपी]

New Delhi, the 26th April, 1985

S.O. 2056.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3712 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

## HBJ GAJ PIPE LINE PROJECT

Village : Bawadi Tehsil : Petlwabad Distt : Zabua

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
--------	------------	---

1	2	3
1.	840	0.150
2.	841	0.344
3.	843	0.016
4.	844	0.032
5.	847/1	0.219

[No. O-14016/200/84-GP]

का. प्रा. 2057.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 3714 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख निहित होगी।

#### अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम का नाम—गोलरकला तहसील—मानुभा जिला—माजुभा राज्य—(मध्य-प्रदेश)

अनु- क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	15	0-364
2.	14	0-121
3.	13	0-024
4.	10	0-081
5.	4	0-040
6.	55	0-162
7.	11	0-302
8.	54	0-324
9.	59	0-065
10.	72	0-283
11.	74 1	0-709
12.	83	0-364
13.	84	0-162
14.	86	0-162
15.	88	0-040
16.	91	0-097
17.	94	0-024
18.	99	0-121
19.	100	0-526
20.	104	0-283
21.	103	0-202
22.	101	0-008
23.	102	0-024
कुल क्षेत्रफल		4.488

S.O. 2057.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3714 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to the notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Golarkalan Tehsil : Zabua Distt. : Zabua

S. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture
1.	15	0.364
2.	14	0.121
3.	13	0.024
4.	10	0.081
5.	4	0.040
6.	55	0.162
7.	11	0.302
8.	54	0.324
9.	59	0.065
10.	72	0.283
11.	74/1	0.709
12.	83	0.364
13.	84	0.162
14.	86	0.162
15.	88	0.040
16.	91	0.097
17.	94	0.024
18.	99	0.121
19.	100	0.526
20.	104	0.283
21.	103	0.202
22.	101	0.008
23.	102	0.024

Total Area

4.488

का. भा. 2058.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3718 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राश्य घोषित कर दिया था।

और यतः वक्ष्य प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम-सोयला	तहसील-पेटलावद	जिला-झाबुआ	राज्य (मध्य-प्रदेश)
अनुक्रम-मांक	खसरा नं.	उपयोग का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)	अधिकार अर्जन
1	2	3	
1.	24	0-089	
2.	26	0-138	
	25	0-142	
	27	0-299	
	32	0-016	
3.	33	0-267	
	46	0-324	
4.	208	0-036	
5.	35	0-016	
	39	0-421	
6.	36	0-202	
7.	37	0-105	
8.	40	0-024	
	42	0-210	
9.	41	0-413	
10.	43	0-162	
	48	0-049	
11.	44	0-299	
12.	34	0-020	
	45	0-008	
	47	0-032	
	38	0-008	
	207	0-020	
योग:—कुल क्षेत्रफल		3-300	

[सं. O-14016/207/84-जीपी]

S.O. 2058.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3718 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962)), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### HBJ Gas Pipe Line Project

Village : Soyala	Tehsil : Petlawad	Distt. : Zabua
S. Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hecture	
No.		
1. 24		0.089
2. 26		0.138
25		0.142
27		0.299
32		0.016
3. 33		0.267
46		0.324
4. 208		0.036
5. 35		0.016
39		0.421
6. 36		0.202
7. 37		0.105
8. 40		0.024
42		0.210
9. 41		0.413
10. 43		0.162
48		0.049
11. 44		0.299
12. 34		0.020
45		0.008
47		0.032
38		0.008
207		0.020
Total Area		3.300

[No. O-14016/207/84-GP]

का. भा. 2059.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3770 तारीख 17/11/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न भूमियों में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आश्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी न उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और कारण उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में कोयला के प्रकाशन को इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम सागादिया तहसील पेटलावाद जिला—सागुआ राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु क्रम. 1 खसरा नं. 1 उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

1	2	3
1.	702	0-016
2.	275	0-413
3.	303	0-032
4.	305	0-372
5.	306	0-121
6.	320/2	0-129
7.	326	0-291
	345	0-388
	346	0-057
8.	334	0-170
9.	336	0-194
	329	0-251
	340	0-599
10.	344	0-283
11.	454	0-202
12.	467	0-190
13.	474/3	0-186
14.	474/7	0-202
15.	474/5	0-008
16.	475	0-283
17.	335	0-016
18.	452	0-008
19.	156	0-053
20.	273	0-008
21.	274	0-113
22.	278	0-162
23.	304	0-028
24.	276	0-041
25.	319	0-105

1	2	3
26.	321	0-040
27.	322	0-081
28.	281	0-049
29.	328	0-057
30.	455	0-316
31.	465	0-210
32.	468	0-081
31.	469	0-073
34.	471	0-575
35.	474/1	0-170
36.	476	0-053
37.	453	0-010
योग कुल क्षेत्रफल :—		6-636

[सं० O-14016/209/84 गैसी]

S.O. 2059.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3770 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Sagadia Tehsil : Petlawad Distt. Zabua

S. Survey No. Area to be Acquired for R.O.U. in Hecture

1	2	3
1.	702	0.016
2.	275	0.413
3.	303	0.032
4.	305	0.372
5.	306	0.121
6.	320/2	0.129
7.	326	0.291
	345	0.388
	346	0.057

1	2	3
8. 334		0.170
9. 336		0.194
329		0.251
340		0.599
10. 344		0.283
11. 454		0.202
12. 467		0.190
13. 474/3		0.186
14. 474/7		0.202
15. 474/5		0.008
16. 475		0.283
17. 335		0.016
18. 452		0.008
19. 156		0.053
20. 273		0.008
21. 274		0.113
22. 278		0.162
23. 304		0.028
24. 276		0.041
25. 319		0.105
26. 321		0.040
27. 322		0.081
28. 281		0.049
29. 328		0.057
30. 455		0.316
31. 465		0.210
32. 468		0.081
33. 469		0.073
34. 471		0.575
35. 474/1		0.170
36. 476		0.053
37. 453		0.010
Total Area		6.636

[No. O-14016/209/84-GP]

मई किलमी, 29 अप्रैल, 1985

का.आ. 2060—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3711 तारीख 17/11/84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों का उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विश्वास करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद् द्वारा अर्जित किया जाना है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से उक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची		
एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट		
ग्राम खेड़ी तहसील साबुआ जिला साबुआ राज्य (मध्य प्रदेश)		
अनु क्र	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1	2	3
1.	355	0-065
2.	354	0-040
3.	58	0-364
4.	77	0-202
5.	78	0-526
6.	80	0-065
7.	81	0-024
8.	82	0-081
9.	83	0-121
10.	94	0-024
11.	84	0-048
12.	145	0-073
13.	144	0-510
14.	138	0-243
15.	139	0-024
16.	140	0-010
17.	132 सी.	0-567
18.	126/2	0-324
19.	119	0-024
20.	120	0-267
21.	122/2	0-421
22.	122/1	0-024
23.	123/1	0-162
24.	123/2	0-170
26.	110	0-186
योग कुल क्षेत्रफल :—		4-565

[सं. O-14016/251/84-जीपी]

New Delhi, the 29th April, 1985

S.O. 2060.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3711 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village : Khedi Tehsil : Zabua Distt. : Zabua

S. Survey No. NO.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hecture
1. 355	0.065
2. 354	0.040
3. 58	0.364
4. 77	0.202
5. 78	0.526
6. 80	0.065
7. 81	0.024
8. 82	0.081
9. 83	0.121
10. 94	0.024
11. 84	0.048
12. 145	0.073
13. 144	0.510
14. 138	6.243
15. 135	0.024
16. 140	0.010
17. 132M	0.567
18. 126/2	0.324
19. 119	0.024
20. 120	0.267
21. 122/2	0.421
22. 122/1	0.024
23. 123/1	0.162
24. 123/2	0.170
25. 110	0.186
Total Area	4.565

[No. O-14016/251/84-GP]

नई दिल्ली, 1 मई, 1985

का० घा० 2061—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० घा० 3926 तारीख 24-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों वा बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था,

और यत् सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और आगे, यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिसूचना से सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है,

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना से सम्बन्धित अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है,

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार ने निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में वायु का प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट

ग्राम महुडी पाइदा तहसील पेटलावाद जिला—भाबुआ, राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु. क्र.	खसरा न.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	7	0.028
2.	9	0.628
3.	18	0.405
4.	8	0.129
5.	19	0.061
6.	59	1.202
7.	63	0.247
8.	60	0.008
योग कुल क्षेत्रफल		2.708

[स. O-14016/264/84- जीपी]

New Delhi, the 1st May, 1985

S.O. 2061.—Whereas by notification by the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3926 dated 24-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances,

## SCHEDULE

## HBJ GAS PIPE LINE PROJECT

Village Mahudi Pada Tehsil : Petlawad Distt. : Zabua

S. Survey No. No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1. 7	0.028
2. 9	0.628
3. 18	0.405
4. 8	0.129
5. 19	0.061
6. 59	1.202
7. 63	0.247
8. 60	0.008
Total	2.708

[No. O-14016/264/84-GP]

कां०श० 2062-यन. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) के धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कां०श० सं० 4052 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जन करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित कहती है कि इस अधिसूचना से सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जन किया जाता है,

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सर्वा बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

##### हाजिरा-बरेल-जगदशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	गाटा सं०	निर्दिष्ट भूमि का रकबा	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	पुरवा	पुरवा	टोकर	3	0-1-10	
			कला	4	0-1-0	
				5	0-17-0	
				7	1-0-0	
				8	0-15-0	
				24	1-16-0	
				24	0-5-0	
				29	0-0-10	
				33	0-1-0	
				34	0-9-0	
				35	0-10-0	
				35	0-10-0	
				35	0-10-0	
				35	0-5-0	
				54	0-6-0	
				54	0-1-0	
				56	0-1-0	
				58	0-11-0	
				60	0-0-10	
				215	0-12-0	
				217	0-1-0	
				218	0-18-0	
				219	0-0-2	
				261	0-15-0	
				262	0-18-0	

[स.०-14016/290/84-ज.प.]

S.O. 2062.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4052 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962)), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

Mazra— Bareilly— Jagdishpur Gas Pipeline

District	Tahsil	Pargana	Village	Plot No.	Acquired Area in B.B.B.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Purva	Purva	Tikar	3	0-1-10	
			Kalan	4	0-1-0	
				5	0-17-0	
				7	1-0-0	
				8	0-15-0	
				24	1-16-0	
				24	0-5-0	
				29	0-0-10	
				33	0-1-0	
				34	0-9-0	
				35	0-10-0	
				35	0-10-0	
				35	0-10-0	
				35	0-5-0	
				54	0-6-0	
				54	0-1-0	
				56	0-1-0	
				58	0-11-0	
				60	0-0-10	
				215	0-12-0	
				217	0-1-0	
				218	0-18-0	
				219	0-0-2	
				261	0-15-0	
				262	0-18-0	
				265	0-0-10	
				266	0-0-10	
				247	0-0-5	
				2	0-0-2	
				267	0-16-0	
				268	0-3-0	
				279	0-5-0	
				287	0-5-0	
				288	0-2-0	
				289	0-2-0	
				291	0-5-0	
				356	0-2-0	
				358	1-17-0	
				360	0-6-0	
				361	0-3-0	
				362	0-5-0	
				363	0-6-0	
				364	0-1-0	
				365	0-5-15	
				367	0-3-0	
				404	0-16-0	
				405	0-12-0	
				407	0-9-0	
				408	0-5-0	
				600	0-4-0	
				601	0-11-0	
				603	0-3-0	

1	2	3	4	5	6	7
Unnao	Purva	Purva	Tikar	604	0-7-0	
				606	0-11-0	
				607	0-0-10	
				609	0-15-10	
				610	0-0-10	
				612	0-17-0	
				613	1-1-0	
				614	0-3-0	
				1	0-0-10	
				55	0-0-15	
				602	0-2-15	

[No. O-14016/290/84-GP]

का.भा. 2063—यत. पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.भा.सं. 4056 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय व्यक्त कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

हाजिरा बरेली अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम	लिया गया रकबा	धिवरण	
1	2	3	4	5	6	7
उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	मैसई चतुर	8	0-7-0	
				9	0-8-8	
				10	0-2-8	
				12	0-13-0	
				20	0-3-10	
				21	0-15-0	
				24	0-8-0	
				26	0-6-8	
				27	0-8-10	
				28	0-6-0	
				30	0-4-4	
				31	0-6-12	
				32	0-1-16	



1	2	3	4	5	6
उन्नाव	उन्नाव	हड़हा	भैसई चतुर	35	0-0-4
				36	0-10-0
				37	0-5-2
				56	1-11-0
				67	0-0-6
				84	0-8-0
				85	0-2-4
				89	0-12-12
				92	1-4-12
				93	0-5-0
				96	0-7-4
				106	2-3-8
				38	0-0-5
				113	1-3-8
				116	0-13-6
				117	0-0-5
				128	0-11-15
				205	0-15-0
				206	0-13-0
				291	0-12-0
				25	0-9-0
				107	0-5-10
				108	0-0-10
				109	0-1-10

[स. O-14016/294/84-जी०पी०]

S.O. 2063.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4056 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And Further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

Hajira-Bareilly to Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Unnav	Unnav	Harha	Bhaisay Chatar	8	0-7-0
				9	0-8-8
				10	0-2-8

1	2	3	4	5	6
Unnav	Unnav	Harha	Bhaisay Chatur	12	0-13-0
				20	0-3-10
				21	0-15-0
				24	0-8-9
				26	0-6-18
				27	0-8-10
				28	0-6-0
				30	0-4-4
				31	0-6-12
				32	0-1-16
				35	0-0-4
				36	0-10-0
				37	0-5-2
				56	1-11-0
				67	0-0-6
				84	0-8-0
				85	0-2-4
				89	0-12-12
				92	1-4-12
				93	0-5-0
				106	2-3-8
				113	1-3-8
				116	0-13-6
				117	0-0-5
				128	0-11-15
				205	0-15-0
				206	0-13-0
				291	0-12-0
				25	0-9-0
				107	0-5-10
				108	0-0-10
				109	0-1-10

[No. O-14016/294/84-GP]

का. आ. 2064.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कां० आ० सं० 4057 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची					
हजिरा-बरेली जगदीशपुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट					
जिला	तहसील	परगना	ग्राम	निवा गवा	रकबा
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	पुर्वा	भौरावा	महाराज खेडा	28/1	0-0-10
				28/2	0-0-10
				33	0-0-5
				34	1-0-0
				35	0-3-5
				31	0-0-5
				32	0-9-0
				46/1	0-15-0
				46/2	0-5-0
				51	0-1-10
				49	0-1-15
				47/1	0-1-10
				47/2	0-1-5
				18	0-3-17
				222	0-4-16
				233	0-14-0
				236	0-10-16
				239	0-2-8
				235	0-1-0
				241	0-16-6
				240	0-2-0
				212	0-4-0
				307	0-13-0
				589	0-1-0
				588	0-1-0
				590/1	0-10-0
				590/2	0-3-0
				587	0-18-0
				593/1	0-10-0
				592	0-1-0
				595	0-9-0
				598	0-7-4
				597	0-0-18
				599	0-3-0
				563	0-4-4
				564/1	0-1-0
				564/2	0-3-0
				578	0-9-16
				565	0-2-0
				573	2-1-16
				538	0-13-0
				540	0-12-0
				541	0-14-3
				542	0-1-0
				543	0-3-3
				517/15	0-2-10
				517/16	0-3-0
				517/17	0-8-0
				516/1	0-1-0
				515/1	0-12-0

1	2	3	4	5	6
उन्नाव	पुर्वा	भौरावा	महाराज खेडा	511/10	0-2-8
				511/11	0-2-4
				511/13	0-8-0
				511/12	0-4-0
				511/17	0-1-0
				511	1-13-12
				583	0-0-10
				583	0-2-16
				579	0-1-16
				539	0-4-0
				45	0-0-15
				243	0-1-0
				584	0-1-10
				600	0-3-0

[स O 14016/295/84 जा.प.प.]

S.O. 2064 —Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4057 dated 11-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline,

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline,

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

## SCHEDULE

Hijra Bareilly-Jagdishpur Pipeline Project					
Distt	Tahsil	Pargana	Village	Plot No	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Unnao	Purva	Mauranvan	Maharaj Kheda	28/1	0-0-10
				28/2	0-0-10
				33	0-0-5
				34	1-0-0
				35	0-3-5
				31	0-0-5
				32	0-9-0
				46/1	0-15-0
				46/2	0-5-0
				51	0-1-10
				49	0-1-16
				47/1	0-1-10
				47/2	0-1-5
				48	0-3-17

1	2	3	4	5	6
Unnao	Purva	Mauran-	Maharani	222	0-4-16
		van	Kheda	233	0-14-0
				236	0-10-16
				239	0-2-8
				235	0-1-0
				241	0-16-6
				240	0-2-0
				242	0-4-0
				307	0-13-0
				589	0-1-0
				588	0-1-0
				590/1	0-10-0
				590/2	0-3-0
				587	0-18-0
				593/1	0-10-0
				592	0-1-0
				595	0-9-0
				598	0-7-4
				597	0-0-18
				599	0-3-0
				563	0-4-4
				564/1	0-1-0
				564/2	0-3-0
				578	0-8-16
				565	0-2-0
				573	2-1-16
				538	0-13-0
				540	0-12-0
				541	0-14-8
				542	0-1-0
				543	0-3-3
				517/15	0-2-10
				517/16	0-3-0
				517/17	0-8-0
				516/1	0-1-0
				515/1	0-12-0
				511/10	0-2-8
				511/11	0-2-4
				511/13	0-8-0
				511/12	0-4-0
				511/17	0-1-0
				511	1-13-12
				583	0-0-10
				583	0-2-16
				579	0-1-16
				539	0-4-0
				45	0-0-15
				243	0-1-0
				584	0-1-10
				600	0-3-0

[N.J. O-14016/295/84-GP]

का. भा. 2065—यत. पेट्रोलियम और खनिज पदार्थों का उपयोग (भूमि से उपयोग के अधिकार का अर्ज) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. म. 4059 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाश्चात्यों को विछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाश्चात्यों को विछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है। कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हों क बचाव भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से वाष्पण के प्रकाशन को इस तारीख को निश्चित होगा।

## अनुसूची

हाजिरा-बरेली-अगदीणपुर पाश्चात्य प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	भूत का नाम	वि.स. सं.	रकबा
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	पूरवा	पूरवा	कंव गांव सानी	8	0-2-10
				26	0-7-0
				27	0-1-0
				28	0-2-0
				29	0-11-0
				30	0-0-10
				31	0-1-0
				32	0-7-0
				33	0-2-0
				34	1-0-0
				35	0-18-0
				39	0-5-0
				41	0-7-0
				42	0-14-0
				44	0-2-10
				109	0-0-5
				110	1-8-0
				111	0-2-0
				120	0-8-0
				121	0-4-0
				133	0-2-0
				135	0-4-0
				136	0-1-0
				137	0-7-0
				139	0-4-0
				140	0-9-0
				141	0-5-0
				149	0-3-0
				154	1-12-0
				156	0-15-0
				169	0-10-0
				170	0-10-0
				191	0-0-15
				193	0-0-10
				194	1-0-10
				179	0-18-1
				180	0-4-0

[सं. O-14016/297/84-जी. पी.]

S.O. 2065.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4059 dated 1-12-84 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### Hajira Bareilly Jagdishpur Pipe Line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Unnao	Purva	Purva	Unchgaon	8	0-2-10
			Sani	26	0-7-0
				27	0-1-0
				28	0-2-0
				29	0-11-0
				30	0-0-10
				31	0-1-0
				32	0-7-0
				33/3	0-2-0
				34	1-0-0
				35	0-18-0
				39/2	0-5-0
				41	0-7-0
				42	0-14-0
				44	0-2-10
				109	0-0-5
				110	1-8-0
				111	0-2-0
				120	0-8-0
				121	0-4-0
				133	0-2-0
				135	0-4-0
				136	0-1-0
				137/1	0-7-0
				139	0-4-0
				140	0-9-0
				141	0-5-0
				149Kha	0-3-0
				154	1-12-0
				156	0-15-0
				169	0-10-0
				170	0-0-10
				191	0-0-15
				193	0-0-10
				194Ka	1-4-0
				179	0-18-1
				180	0-4-0

[No. O-14016/297/84-GP]

का. पा. 2066.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. पा. म. 4408 तारीख 3-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों का बिछाने के लिए अर्जित करने का अन्तर्गत प्राणाय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और अग्रे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. से सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हजीरा से बरेली से जयसीवापुर तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य	गुजरात	जिला	पंच महल	तालुका	काकोल
गांव	सर्वे. न.	हे.	आर.	म.	
द्वेराल	190पी		1	98	50
	508		0	32	00
	507पी		0	03	00
	505/1		0	17	00
	506		0	04	00
	502/2		0	01	00
	499/पी		0	28	00
	499 पी		0	34	50
	488/14		0	20	50
	488/1		0	09	00
	488/2		0	03	00
	488/3		0	01	00
	487		0	23	00
	191		0	23	00

[म. O-14016/373/84-जी पी]

S.O. 2066.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 4408 dated 3-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user

in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquiesced for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

### SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Kalol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Eral	190/P	1	98	50
	508	0	32	00
	507/P	0	03	00
	505/1	0	17	00
	506	0	04	00
	502/2	0	01	00
	499/P	0	28	00
	499/P	0	34	50
	488/14	0	20	50
	488/1	0	09	00
	488/2	0*	03	00
	488/3	0	01	00
	487	0	23	00
	191	0	23	00

[No. O-14016/373/84-GP]

का. आ. 2067.—यत् पेट्रोलियम और गैस पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना कां० आ. सं. 4578 तारीख 22-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत् सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यत् केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. से सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

### अनुसूची

हाजिरा ---बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्रामा का नाम	गांवा सं०	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
उन्नाव	पुरवा	मोरावां	मन्वाना	210	0-1-5
				211	0-0-13
				214	0-5-0
				213	0-5-0
				228	0-0-14
				226	0-3-0
				227	0-5-0
				230	0-0-3
				232	0-2-10
				239	0-1-15
				240	0-0-15
				241	0-0-5
				242	0-0-1
				233	0-8-0
				234	0-0-2
				236	0-1-5
				237	0-5-0
				238	0-1-10
				267	0-10-0
				268	0-10-17
				269	0-1-10
				271	0-0-10
				273	0-10-10
				274	0-0-2
				275	0-5-0
				277	0-0-3
				278	0-4-10
				279	0-0-10
				280	0-6-0
				281	0-1-0
				478	0-7-5
				479	0-6-0
				480	0-1-0
				491	0-0-10
				493	0-0-2
				498	2-14-0
				499	1-2-0
				536	0-0-3
				537	0-0-3
				538	0-2-0
				2870	
				535	1-16-0
				533	0-2-10
				584	0-1-0
				531	0-18-0
				530	0-0-15
				686	0-3-0
				685	0-9-0
				687	0-6-12

1	2	3	4	5	6
				683	0-11-8
				684	0-1-10
				689	0-0-5
				690	0-18-0
				682	0-1-10
				691	0-1-0
				853	0-17-5
				854	0-10-16
				855	0-7-15
				857	0-7-10
				856	0-2-10
				861	0-9-10
				1010	0-5-0
				1009	0-0-2
				1002	1-0-10
				1003	0-3-15
				1001	0-0-5
				1000	1-0-5
				864	0-0-5
				995	0-0-2
				997	0-8-5
				998	0-1-0
				999	0-6-0
				989	0-15-0
				988	0-2-0
				987	0-5-0
				985	2-8-0
				982	0-1-15
				971	0-6-5
				972	0-4-10
				975	0-2-0
				1163	2-1-8
				1172	0-7-15
				1171	0-3-5
				1174	1-1-0
				1176	0-9-5
				1177	0-0-15
				1178	0-9-0
				1309	0-1-0
				1312	1-5-5
				1307	0-3-5
				1310	0-4-15
				1306	0-1-5
				1350	0-1-5
				1353	0-3-13
				1354	0-2-10
				1355	0-8-5
				1356	0-12-5
				1357	0-1-0
				1293	0-3-0
				1287	0-7-13
				1288	1-9-5
				1289	0-4-0
				1257	0-3-10
				1259	0-8-0
				1264	0-14-0

1	2	3	4	5	6
				1265	0-0-5
				1266	0-0-4
				1267	0-14-5
				1263	0-8-10

[सं० O-1413/413/84-जी पी]

S.O. 2067.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 4518 dated 22-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

Hajira—Bareilly—Jagdishpur Pipe Line Project					
Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Unnao	Purva	Mauravan	Sandana	210	0-1-5
				211	0-0-13
				214	0-5-0
				213	0-5-0
				228	0-0-14
				226	0-3-0
				227	0-5-0
				230	0-0-3
				232	0-2-10
				239	0-1-15
				240	0-0-15
				241	0-0-5
				242	0-0-1
				233	0-8-0
				234	0-0-2
				236	0-1-5
				237	0-5-0
				238	0-1-10
				267	0-10-0
				268	0-10-17
				269	0-1-10
				271	0-0-10
				273	0-10-10
				274	0-0-2
				275	0-5-0

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
				277	0-0-3					1306	0-1-5
				278	0-4-10					1350	0-1-5
				279	0-0-10					1353	0-3-12
				280	0-6-0					1354	0-2-10
				281	0-1-0					1355	0-8-5
				478	0-7-5					1356	0-12-5
				479	0-6-0					1357	0-1-0
				480	0-1-0					1293	0-3-0
				491	0-0-10					1287	0-7-15
				493	0-0-2					1288	1-9-5
				498	2-14-0					1289	0-4-0
				499	1-2-0					1257	0-3-10
				536	0-0-3					1259	0-8-0
				537	0-0-3					1264	0-14-0
				538	0-2-0					1265	0-0-5
										1266	0-0-4
				2870						1267	0-14-5
				535	1-16-0					1263	0-8-10
				533	0-2-10						
				584	0-1-0						
				531	0-18-0						
				530	0-0-15						
				686	0-3-0						
				685	0-9-0						
				687	0-6-12						
				683	0-11-8						
				684	0-1-10						
				689	0-0-5						
				690	0-18-0						
				682	0-1-10						
				691	0-1-0						
				853	0-17-5						
				854	0-10-16						
				855	0-7-15						
				857	0-7-10						
				856	0-2-10						
				861	0-9-10						
				1010	0-5-0						
				1009	0-0-2						
				1002	1-0-10						
				1003	0-3-15						
				1001	0-0-5						
				1000	1-0-5						
				864	0-0-5						
				995	0-0-2						
				997	0-8-5						
				998	0-1-0						
				999	0-6-0						
				989	0-15-0						
				988	0-2-0						
				987	0-5-0						
				985	2-8-0						
				982	0-1-5						
				971	0-6-5						
				972	0-4-10						
				975	0-2-0						
				1163	2-1-8						
				1172	0-7-15						
				1171	0-3-5						
				1174	0-1-0						
				1176	0-9-5						
				1177	0-0-15						
				1178	0-9-0						
				1309	0-1-0						
				1312	1-5-5						
				1307	0-3-5						
				1310	0-4-15						

[No. O-14016/413/84-GP]

का. प्रा. 2068-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 4535 तारीख 10-2-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों के बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का निश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय रैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

हजीरा से बरेली से जमवीयपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए  
राज्य-गुजरात जिना-यंजमहल तालुका-कालोल

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर आर	सेन्टीयर
टीन्वी	16	0	26 00
	14	0	33 00
	9	0	30 00
	12	0	24 00
	10	0	21 00
	11	0	21 00
	6	0	12 00

[सं. O-14016/437/84-जीपी]

S.O. 2068.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 4535 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hec-tare	Acre	Centiare
Timbi	16	0	26	00
	14	0	33	00
	9	0	30	00
	12	0	24	00
	10	0	21	00
	11	0	21	00
	6	0	12	00

[No. O—14016/437/84—GP]

का. मा. 2068:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का मा. सं. 4554 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची  
हजिरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।  
राज्य-गुजरात जिला-पंचमहाल तालुका-हालोल

गांव	ब्लॉक न.	हेक्टर और	सेन्टीयर	
1	2	3	4	5
तरखडा	298	0	42	00
	296	0	01	00
	281/ए	0	16	53
	280	0	27	14
	279	0	21	93
	278	0	19	14
	276	0	44	00
	973	0	22	10
	1	0	27	46
	12	0	27	62
	11	0	03	66
	कार्ट ट्रैक	0	05	00
	50	0	16	72
	107	0	04	84
	कार्ट ट्रैक	0	02	25
	51	0	00	58
	106	0	14	96
	104	0	10	90
	105	0	12	96
	102	0	15	22
	115	0	00	05
	116	0	12	44
	101	0	12	44
	117	0	60	84
	158	0	01	70
	159	0	03	69
	160	0	11	20
	513	0	21	08
	514	0	10	18
	कामस	0	04	50
	511	0	11	73
	510	0	10	56
	509	0	28	29
	508	0	06	40
	507	0	01	10
	502	0	30	36
	501	0	14	30
	503	0	14	20
	499	0	36	64
	498	0	11	98
	610	0	17	80
	612	0	02	75
	611	0	15	84
	646/ए	0	09	15
	646/बी	0	09	78
	647	0	08	26
	644	0	53	90
	643	0	18	06
	650	0	15	57
	652	0	37	80



1	2	3	4	5
	682	0	31	28
	681	0	31	90
	679	0	17	94
	680	0	00	50
	678	0	97	54
	651	0	22	08

[सं. O-14016/457/84-जीपी]

S.O. 2069.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S. O. 4554 dated 10-12-84 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

## SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Block No.	Hec- tare	Are	Centi- are
1	2	3	4	5
Tarkhanda	298	0	42	00
	296	0	01	00
	281/A	0	16	53
	280	0	27	14
	279	0	21	93
	278	0	19	14
	276	0	44	00
	973	0	22	10
	1	0	27	46
	12	0	27	62
	11	0	03	66
	Cart track	0	05	00
	50	0	16	72
	107	0	04	84
	Cart track	0	02	25
	51	0	00	58
	106	0	14	96
	104	0	10	90
	105	0	12	96
	102	0	15	22
	115	0	00	05
	116	0	12	44

1	2	3	4	5
	101	0	12	44
	117	0	60	84
	158	0	01	70
	159	0	03	69
	160	0	11	20
	513	0	21	08
	514	0	10	18
	Kans	0	04	50
	511	0	11	73
	510	0	10	56
	507	0	28	29
	508	0	06	40
	507	0	01	10
	502	0	30	36
	509	0	14	30
	503	0	14	20
	499	0	36	64
	498	0	11	98
	610	0	17	80
	612	0	02	75
	611	0	15	84
	646/A	0	09	15
	646/B	0	09	78
	647	0	08	26
	644	0	53	90
	643	0	18	06
	650	0	15	57
	652	0	37	80
	682	0	31	28
	681	0	31	90
	679	0	17	94
	680	0	00	50
	678	0	97	54
	651	0	22	08

[No. O-14016/457/84-GP]

का. प्रा. 2070.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.प्रा.सं. 4556 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्टें वे दी हैं।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है की इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के अर्थ में अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. से सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

श्रृङ्खला से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य-गुजरात जिला-पंचमहाल तालुका-हालोल

गांव	सर्वे न.	हेक्टेयर	भार	सन्टीयर
1	2	3	4	5
विंटीज	कार्ट ट्रैक	0	02	00
	602	0	05	00
	390	0	22	20
	कार्ट ट्रैक	0	01	28
	608/2	0	17	00
	407	0	11	00
	610	0	03	00
	611	0	22	00
	507	0	45	00
	506	0	20	00
	505	0	19	00
	कार्ट ट्रैक	0	03	50
	350/3	0	21	00
	346/2	0	00	16
	346/1	0	00	16
	349/4	0	14	00
	349/3	0	08	00
	349/2	0	05	00
	349/1	0	01	00
	347/2	0	05	00
	347/1	0	18	00
	329/3	0	02	00
	329/2	0	16	00
	331/2	0	01	00
	331/1	0	07	00
	331/3	0	00	08
	330	0	24	00
	326	0	45	00
	327	0	01	00
	322/2	0	10	00
	322/3	0	01	00
	323/1	0	26	00
	314/2	0	05	00
	314/1	0	11	00
	315/2	0	06	16
	312	0	07	00
	308/पी	0	11	00
	310/1	0	19	00
	309	0	19	16
	308/पी	0	04	00
	302	0	27	16
	295/3	0	01	00
	295/2	0	14	00
	241/2	0	05	00
	241/1	0	11	00

1	2	3	4	5
	242	0	21	00
	243/1	0	21	00
	243/2	0	04	00
	272	0	12	00
	271	0	47	00
	273	0	29	00
	268/1	0	05	00
	265	0	24	00
	कोटार	0	28	00

[No O-14016/459/84-जे पी

S.O. 2070.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4556 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 5 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

Pipeline from Hajira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Vintoj	Cart track	0	02	00
	602	0	05	00
	390	0	22	20
	Cart track	0	01	28
	608/2	0	17	00
	407	0	11	00
	610	0	03	00
	611	0	22	00
	507	0	45	00
	506	0	20	00
	505	0	19	00
	Cart track	0	03	50
	350/3	0	21	00
	346/2	0	00	16
	346/1	0	00	16
	349/4	0	14	00
	349/3	0	08	00

349/2	0	05	00
349/1	0	01	00
347/2	0	05	00
347/1	0	18	00
329/3	0	02	00
329/2	0	16	00
331/2	0	01	00
331/1	0	07	00
331/3	0	00	08
330	0	24	00
326	0	45	00
327	0	01	00
322/2	0	10	00
322/3	0	01	00
323/1	0	26	00
314/2	0	05	00
314/1	0	11	00
315/2	0	06	16
312	0	07	00
308/P	0	11	00
310/1	0	19	00
309	0	19	16
308/P	0	04	00
302	0	27	16
295/3	0	01	00
295/2	0	14	00
241/2	0	05	00
241/1	0	11	00
242	0	21	00
243/1	0	21	00
243/2	0	04	00
272	0	12	00
271	0	47	00
273	0	29	00
266/1	0	05	00
265	0	24	00
Kotari	0	28	00

[No. O-14016/459/84-GP]

का. आ. म. 2071:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4568 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जन करने का अपना प्राप्य घोषित कर दिया था।

और यतः मध्यम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तात्पर्य को निहित होगा।

अनुसूची				
हजारी से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।				
राज्य-गुजरात जिला- पंचमहल तालुका- लीमखेड़ा				
गांव	मर्वे नं.	हेक्टेयर	आरि.	सेन्टीयर
कधीनिया	36	0	00	34
	37/2	0	38	45
	39/1	0	09	10
	39/4	0	21	24
	38	0	40	47
	35	0	06	80
	34/1	0	24	28
	34/2	0	23	27
	33/3	0	01	01
	33/2	0	39	46
	33/1	0	26	30
	33/5	0	11	40
	33/6	0	11	40
	33/7	0	12	60
	30/1	0	16	19
	15	0	00	32
	14	0	32	37
	13/1	0	30	35
	13/2	0	33	38
	3	0	12	15
	4/3	0	32	37
	4/2	0	24	29
	5/1	0	24	29
	30	0	41	48
कोटर		0	09	10
	5/2	0	13	50
	5/3	0	13	50
	119/1	0	60	00
	83	0	62	10
	83/7	0	26	40
	83/8	0	40	70
काटे ट्रेक		0	05	00

[स. O-14016/471/84-जी पी]

S.O. 2071.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4568 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

## SCHEDULE

Pipeline from Hajira Bareilly Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Limkheda

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Katholiya	36	0	00	34
	37/2	0	38	45
	39/1	0	09	10
	39/4	0	21	24
	38	0	40	47
	35	0	06	80
	34/1	0	24	28
	34/2	0	23	27
	33/3	0	01	01
	33/2	0	39	46
	33/1	0	26	30
	33/5	0	11	40
	33/6	0	11	40
	33/7	0	12	60
	30/1	0	16	19
	15	0	00	32
	14	0	32	37
	13/1	0	30	35
	13/2	0	33	38
	3	0	12	15
	4/3	0	32	37
	4/2	0	24	29
	5/1	0	24	29
	30	0	41	48
	Kotar	0	09	10
	5/2	0	13	50
	5/3	0	13	50
	119/1	0	60	00
	83	0	62	10
	83/7	0	26	40
	83/8	0	40	70
	Cart track	0	05	00

[No. O—14016/471/84—GP]

का. आ. 2073—यतः 'पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 4571 तारीख 10-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिये  
राज्य :—गुजरात जिला :—पंचमहल तालुका :—दाहोद

गांव	सर्वे नं.	हेक्टेयर	घार	सेन्टीयर
नानी खराज	6	0	09	00
	7	0	08	00
कोटर		0	09	00
	9	0	44	00
	78	0	34	00
	74	0	45	00
	75	0	03	00
	81	0	03	00
	73	0	22	00
	67	0	28	00
	82	0	03	00

[सं. O—14016/474/84—जी पी]

S.O. 2072.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4571 dated 10-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

## SCHEDULE

Pipeline from Hazira—Bareilly—Jagdishpur

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Dahod

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Nani Kharaj	6	0	09	00
	7	0	08	00
Kotar		0	09	00
	9	0	44	00
	78	0	34	00
	74	0	45	00
	75	0	03	00
	81	0	03	00
	73	0	22	00
	67	0	28	00
	82	0	03	00

[No. O—14016/474/84—GP]

## कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1985

## MINISTRY OF AGRICULTURE &amp; RURAL

DEVELOPMENT

(Department of Agriculture &amp; Cooperation)

New Delhi, the 22nd April, 1985

का.मा. 2073—केन्द्रीय सरकार, 30 जुलाई, 1982 तक यथा संशोधित पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 की उपधारा (1) (एच) के उपबन्धों के अंतर्गत एतद्वारा डा. कैलाश सखला को नत्काल से प्राणी अधिकारों तक भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का सदस्य नामांकन करती है।

[सं 14-6/85-एल डी i]

के जी कृष्णमूर्ति, उप सचिव

S.O. 2073.—Under provisions of Sub-Section (1) (h) of Section 5 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1950 as amended upto 30th July, 1982, the Central Government hereby nominate Dr. Kailash Sankhala as Member of the Animal Welfare Board of India with immediate effect and until further orders.

[No. 14-6/85-LD.I]

K G. KRISHNAMOORTHY, Dy Secy.

(संस्कृत विभाग)

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1985

(पुरातत्व)

का.मा. 2074—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपायय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्मारक महत्व का है —

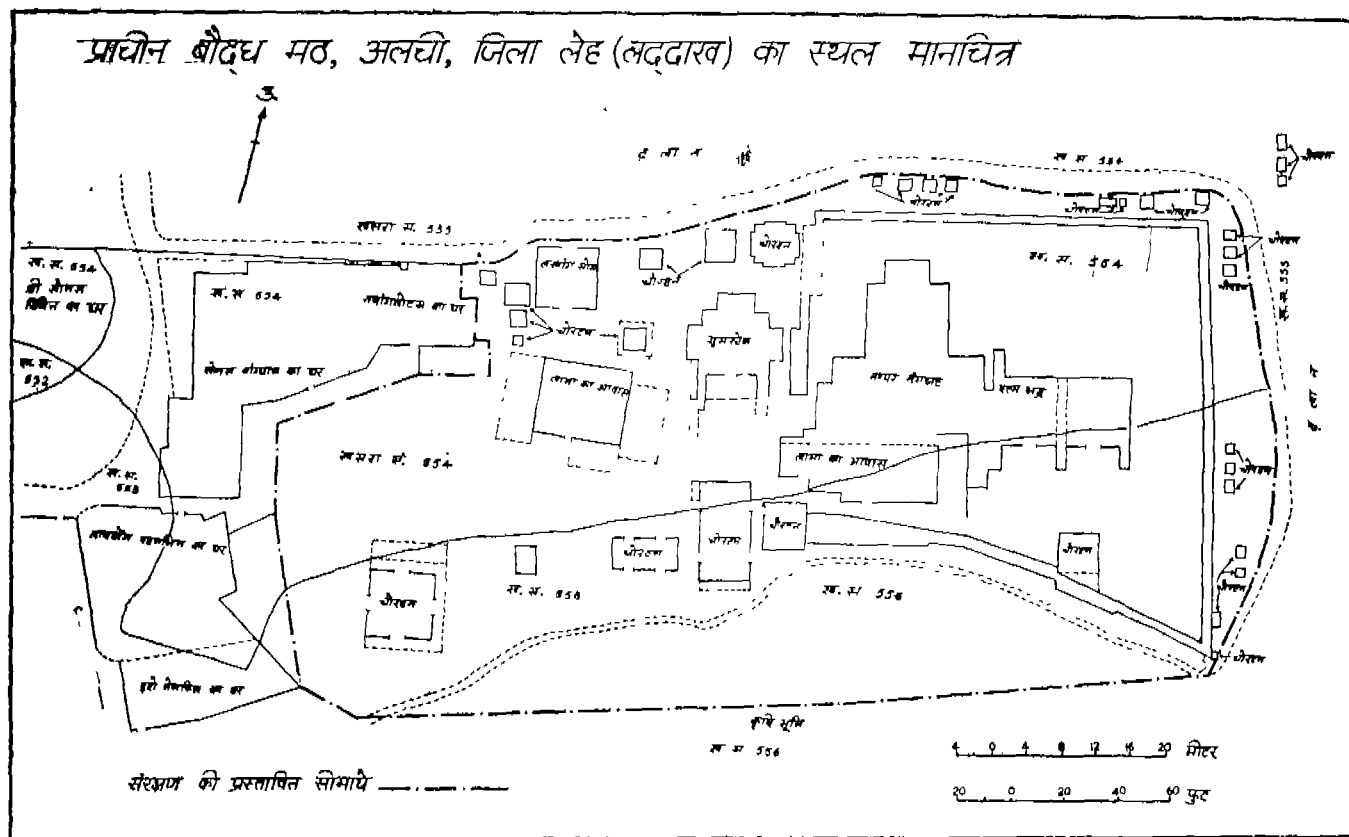
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग ii, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 6 फरवरी, 1982 में प्रकाशित संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना स. का. मा. 450 तारीख 21 जनवरी, 1982 को अधिकांश करने हुए, उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में जारी किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त स्मारक में द्विपक्षीय किसी व्यक्त से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी।

## अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	स्मारक का नाम	संरक्षक अधीन सम्मिलित किया जाने वाला राजस्व प्लॉट संख्या
1	2	3	4	5	6
जम्मू कश्मीर	लद्दाख	लेह	ग्रामीण	नीचे दिए गए रेखांक में वर्णित सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 554 और 556 के भागों में समाविष्ट बौद्ध विहार	नीचे दिए गए रेखांक में वर्णित सर्वेक्षण प्लॉट सं. 554 और 556 के भाग
क्षेत्र	सीमा	स्वामित्व	टिप्पणियाँ		
7	8	9	10		
0 4095 हेक्टर	पूर्व: सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 555 दक्षिण: सर्वेक्षण प्लॉट संख्या 556 का शेष भाग उत्तर: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 534 और 535 पश्चिम: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 554 और 556 के शेष भाग	प्राइवेट	धार्मिक उपयोग में है।		

[सं० 2/38/78-एम०]



एम. एस. नमराजराव (सं. 2 38 78-एम.)

**DEPARTMENT OF CULTURE**  
(Archaeological Survey of India)  
New Delhi, the 27th April, 1985  
(ARCHAEOLOGY)

S.O. 2074.—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

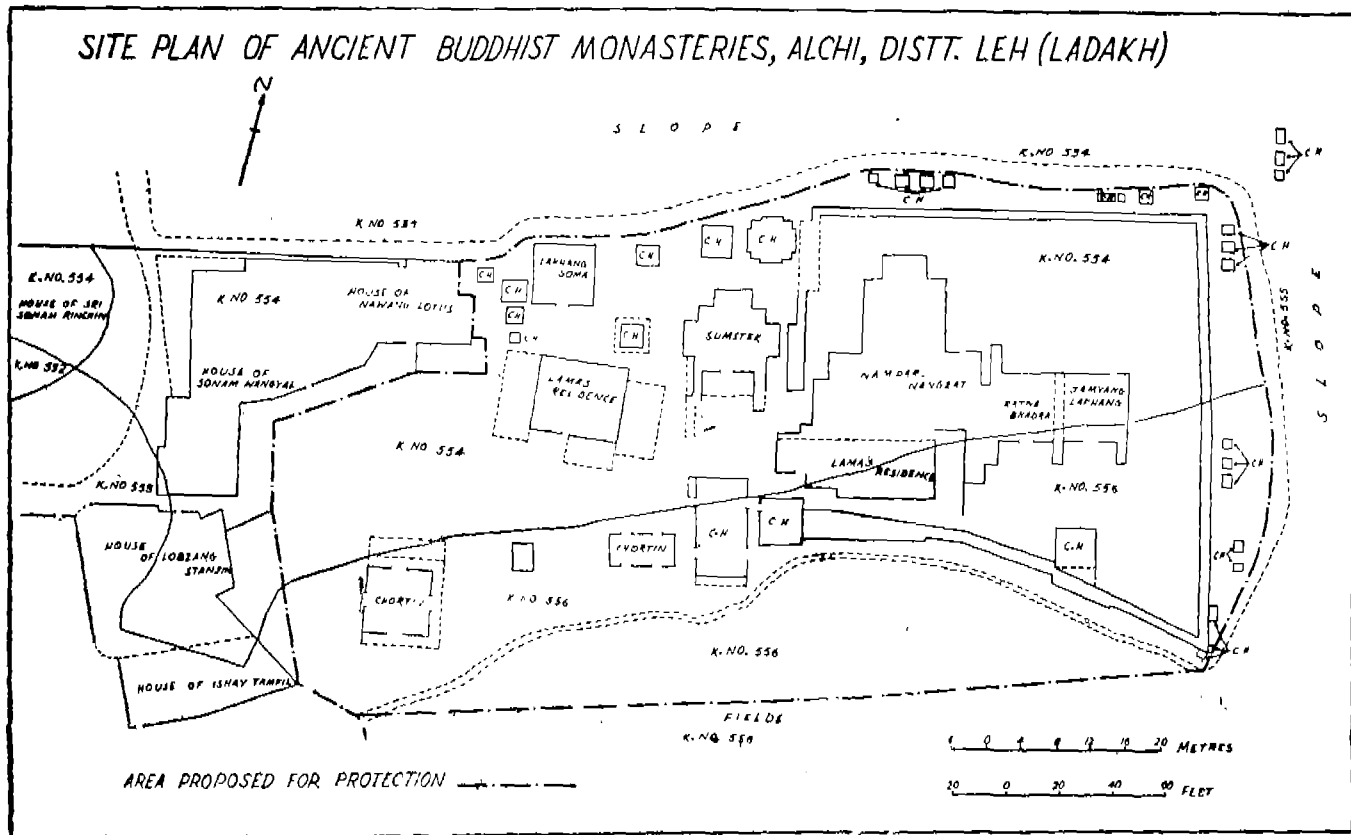
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958)

and in supersession of the notification of Department of Culture (Archaeological Survey of India) No. S. O. 450 dated the 21st January, 1982 Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 6th February, 1982, the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance.

Any objection which may be received within a period of two months from the date of issue of this notification in the official Gazette from any person interested in the said ancient monument will be considered by the Central Government.

**SCHEDULE**

State	Distt.	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jammu & Kashmir	Ladakh	Leh	Alchi	Buddhist Monasteries comprised in parts of survey plot Nos. 554 and 556 as shown in the site plan reproduced below.	Part of survey plot Nos. 554 and 556 as shown in the site plan reproduced below.	0.4095 Hectares	East.—Survey Plot No. 555  South.—Remaining portion of survey plot No. 556 North.—Survey Plot Nos. 534 and 535. West.—Remaining portions of survey plot Nos. 554 and 556.	Private	in religious use



[No. 2/38/78--M]

का. भा. 2075--केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उदाहरण अनुसूची में विविष्ट संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (ii) तारीख 7 मई, 1983 में प्रकाशित संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं. का. भा. 2057 तारीख 22 अप्रैल, 1983 को अधिकांश करते हुए, उक्त संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, दो मास की सूचना देती है।

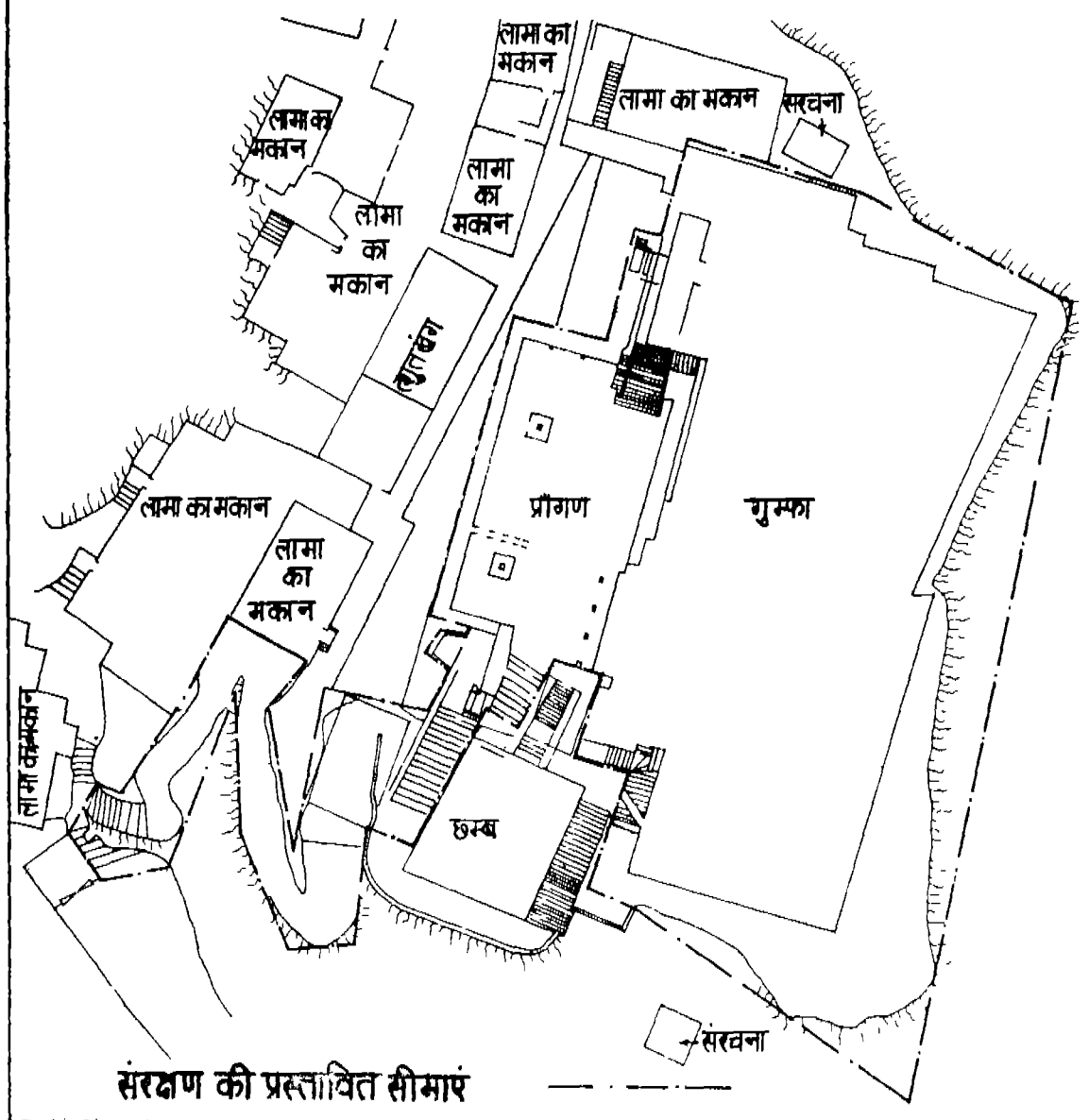
केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार विनिविष्ट दो मास की अवधि के भीतर उक्त संस्मारक में हिनबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी

## अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किया जाने वाला राजस्व प्लॉट संख्यांक
1	2	3	4	5	6
जम्मू-कश्मीर	लद्दाख	लेह	थिक्से	नीचे दिए गए रेखांक में दर्शाए गए सर्वेक्षण प्लॉट सं. 2040 के भाग में समाविष्ट भू-भाग के साथ प्राचीन गुफा	नीचे दिए गए स्थल रेखांक में दर्शाए गए सर्वेक्षण प्लॉट सं. 2040 का भाग
क्षेत्र	सीमा		स्वामित्व	टिप्पणियाँ	
7	8		9	10	
0.3172 हेक्टेयर	उत्तर: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 2040 का शेष भाग पूर्व: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 2040 का शेष भाग दक्षिण: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 2040 का शेष भाग पश्चिम: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 2040 का शेष भाग		प्राइवेट स्वामित्ववादी	गुफा धार्मिक उपयोग में	

# थिकसे, जिला-लेह (लद्दाख) में स्थित प्राचीन गुम्फा का स्थल मानचित्र

0 6 12 18 24 30 मीटर  
0 20 40 60 80 100 फुट



[च. 2/16/89-एम ]

S.O. 2075.—Whereas the Central Government is of the opinion that the monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) and in supersession of the notification of the Department of Culture (Archaeological Survey of India) No. S. O. 2057 dated the 22nd April, 1982, published in the Gazette of

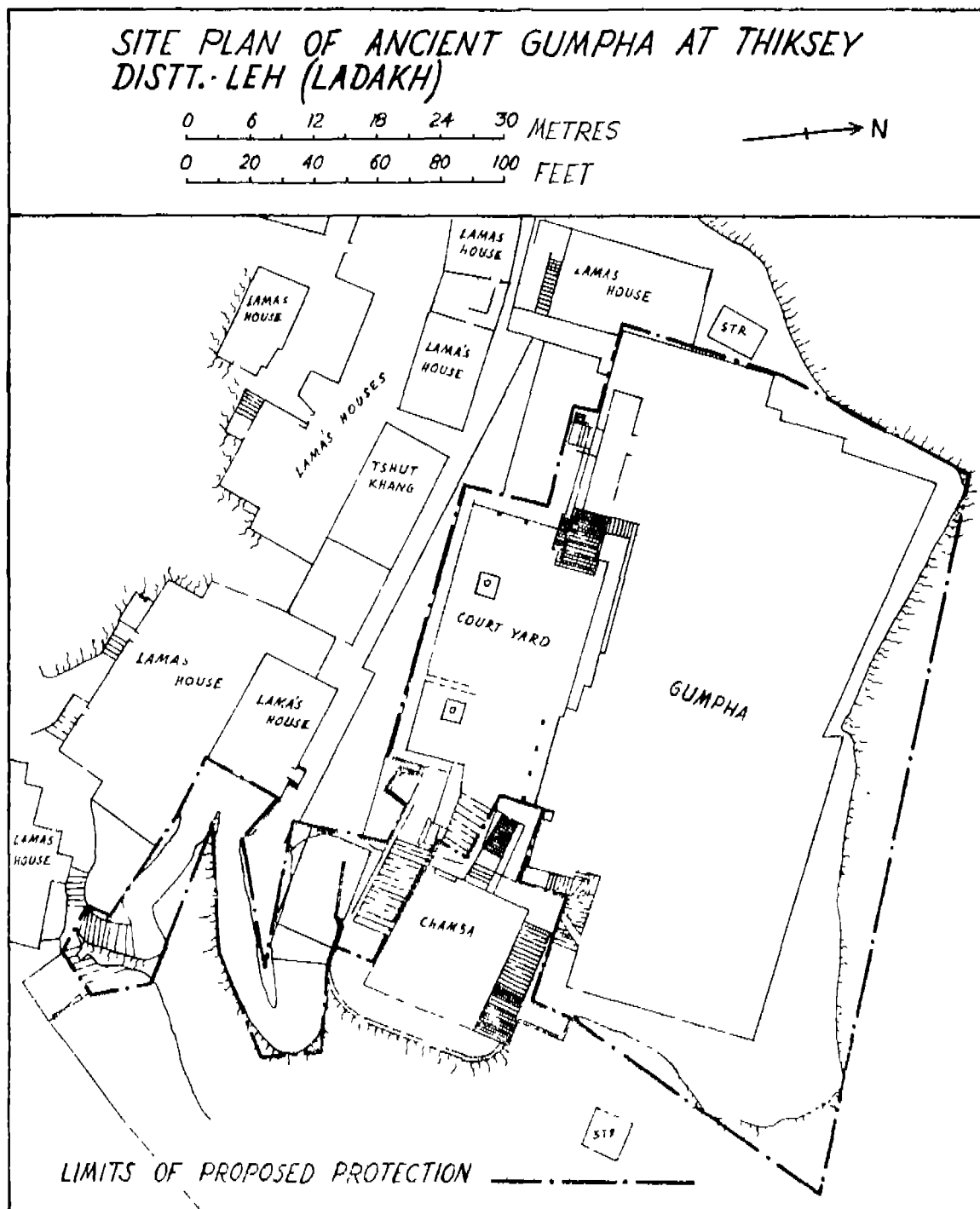
India, Part II, Section 3 (ii) dated the 7th May 1983, the Central Government hereby gives two months' notice of its intention to declare the said monument to be of national importance from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection which may be received from any person interested in the said monument within a period of two months so specified will be considered by the Central Government.



## SCHEDULE

State	Distt.	Tehsil	Locality	Name of Monument	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jammu & Kashmir	Ladakh	Leh	Thiksey	Ancient Gumpah along with part of land comprised in part of survey plot No. 2040 as shown in the site plan reproduced below.	Part of survey plot No. 2040 as shown in the site plan reproduced below.	0.3172 Hectares	North.—Remaining portion of survey plot No. 2040.  East.—Remaining portion of survey plot No. 2040 South.—Remaining portion of survey plot No. 2040. West.—Remaining portion of survey plot No. 2040.	Privately owned	Gumpah religious use



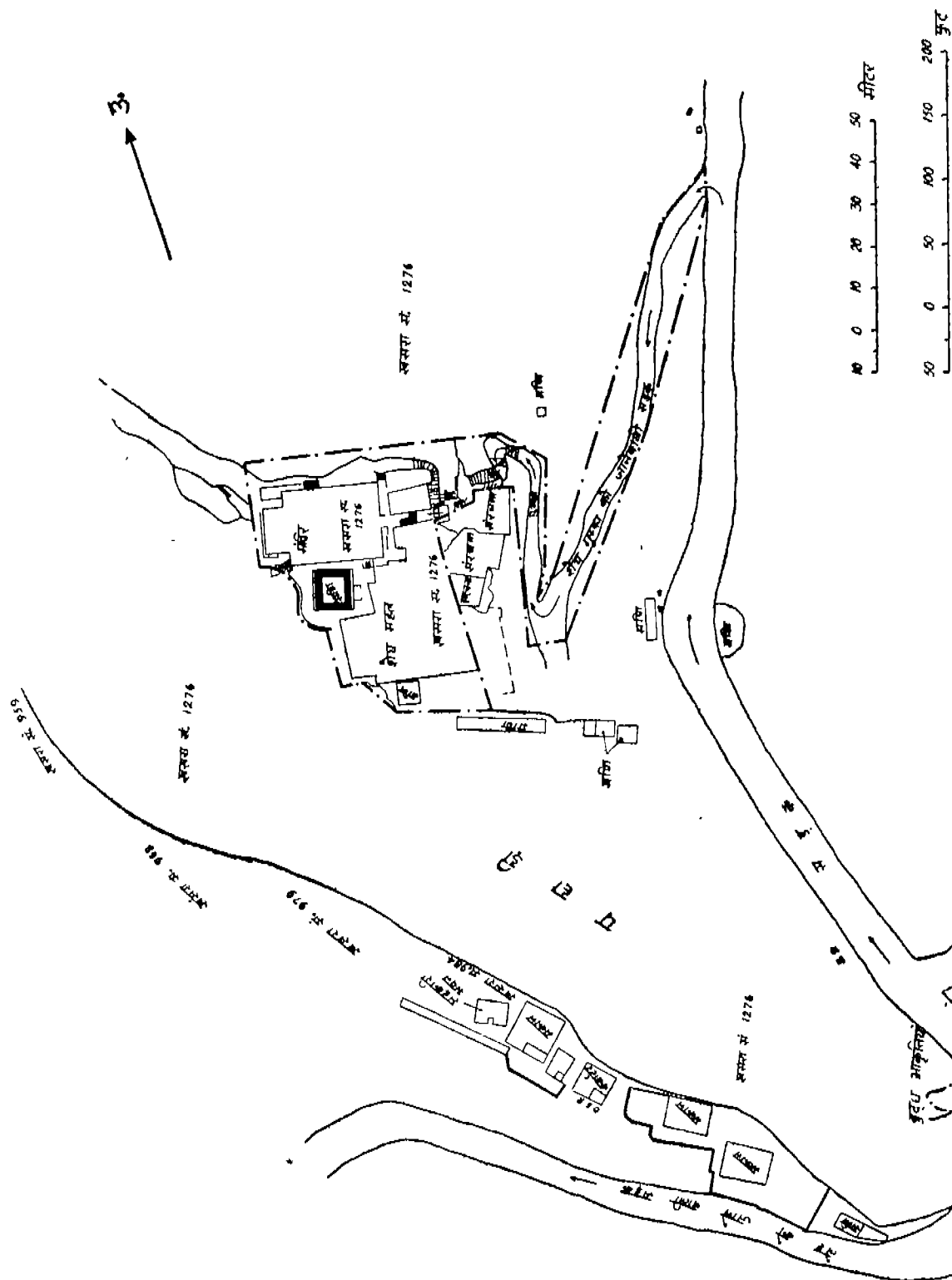
का. भा. 2076 —केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपावृद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 (ii) तारीख 6 फरवरी, 1982 में प्रकाशित संस्कृत विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना स. का. भा. 421 तारीख 21 जनवरी, 1982 को अधिकास्त करते हुए, उक्त संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, दो मास की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार विनिर्दिष्ट वंश नाम की अवधि के भीतर उक्त संस्मारक में हिनबद्ध तिरों वंशों में प्राचिनता आशय पर विचार करेगी

#### अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किये जाने वाला राजस्व प्लॉट संख्यांक
1	2	3	4	5	6
जम्मू-काश्मीर	लेह	लेह	शेष	नीचे दिए गए स्थल रेखांक में दर्शित सर्वेक्षण प्लॉट सं. 1276 के भाग में समाविष्ट मंगल क्षेत्र सहित प्राचीन महल, जिसके अंतर्गत पूजा स्थल भी हैं।	नीचे दिए गए स्थल रेखांक में दर्शित सर्वेक्षण प्लॉट सं. 1276 का भाग
क्षेत्र		सीमा		स्वामित्व	टिप्पणी
7		8		9	10
0.4013 हेक्टेयर		उत्तर: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 1276 का शेष भाग पूर्व: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 1276 का शेष भाग और मुख्य सड़क दक्षिण: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 1276 का शेष भाग पश्चिम: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 1276 का शेष भाग		प्राइवेट	पूजन स्थल, धार्मिक उपयोग में है।



संरक्षण की प्रस्तावित सीमाएं

S.O.2076.—Whereas the Central Government is of opinion that the monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) and in supersession of the notification of the Department of Culture (Archeological Survey of India), No. S. O. 421, dated the 21st January, 1982 published in the Gazette of

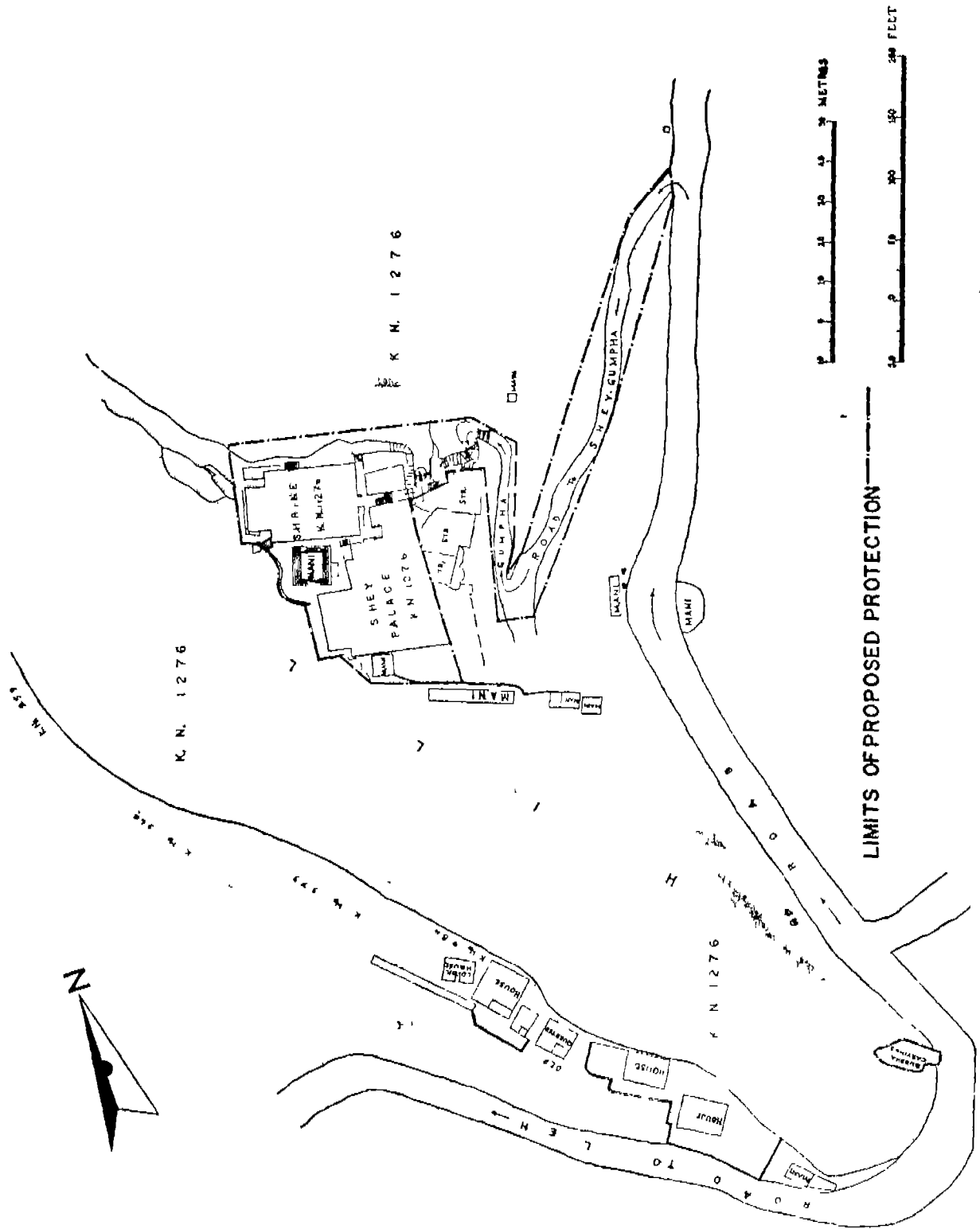
India, Part II, Section 3(ii), dated the 6th February, 1982 the Central Government hereby gives two months' notice of its intention to declare the said monument to be of national importance from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection which may be received from any person interested in the said monument within a period of two months so specified will be considered by the Central Government.

#### SCHEDULE

State	Distt.	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jammu & Kashmir	Leh	Leh	Shey	Ancient Palace including shrine together with adjacent area comprised in part of survey plot No. 1276 as shown in site plan reproduced below.	Part of survey plot No. 1276 as shown in site plan reproduced below.	0.4013 Hectares.	North.—Remaining portion of survey plot No. 1276.  East.—Remaining portion of survey plot No. 1276 and Main road. South.—Remaining portion of survey plot No. 1276. West.—Remaining portion of survey plot No. 1276	Private	Shrine in religious use.

# SITE PLAN OF ANCIENT PALACE AT SHEY DIST. LEH, LADAKH



का. प्र. 2077--केन्द्रीय सरकार ने, भारत के राजपत्र, भाग 2-खंड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 492-493 पर प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं. का. प्र. 455 तारीख 21 जनवरी, 1982 द्वारा उक्त अधिसूचना में उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक के राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के आने आणव की दो माम की सूचना दी थी और प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्विक स्थल और धरोहर अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 के उपधारा (1) की अधिनियम द्वारा उक्त अधिसूचना की एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक के पास एक सहज दृश्य स्थान पर चिपका दी थी।

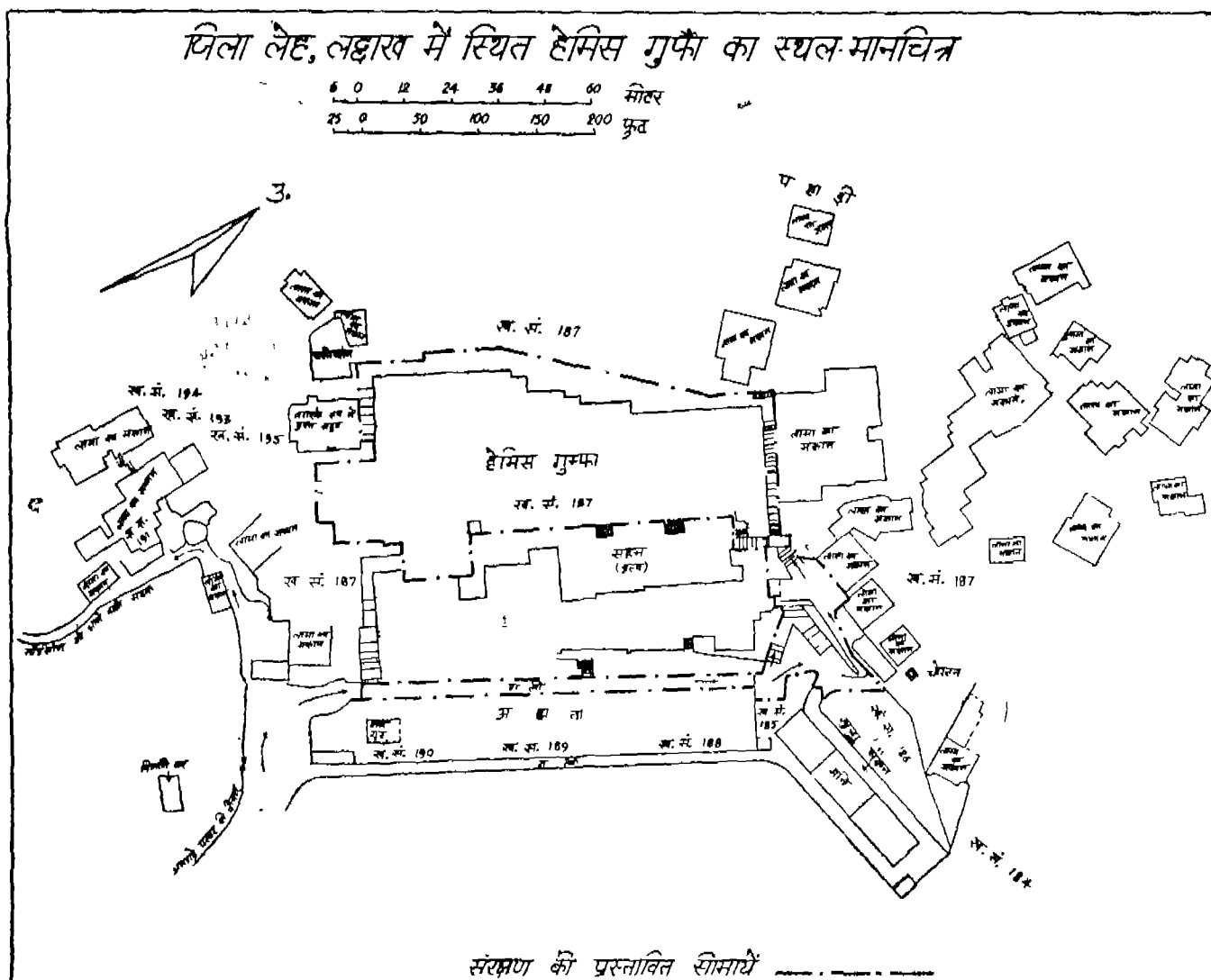
और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता की 11 फरवरी, 1982 को उपलब्ध करा दी गई थी।

और जनता से प्राप्त धार्यों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, इसमें उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त प्राचीन स्मारक की राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है।

#### अनुसूची

राज्य	जिला	महल	अवस्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण के प्रयोग सम्बन्धित किए जाने वाले सर्वेक्षण प्लॉट सं.
1	2	3	4	5	6
जम्मू-काश्मीर	लेह	लेह	हेमिस	हेमिस गुफा और तीर्थ किए गए स्थल रेखांक में दर्शित सर्वेक्षण प्लॉट सं. 187 के भाग में समाविष्ट शाल्वस्थ भूमि	नीचे दिए गए स्थल रेखांक में दर्शित सर्वेक्षण प्लॉट सं. 187 का भाग
क्षेत्र	मीमांसा	स्वामिन्	टिप्पणी		
7	8	9	10		
532 रेक्टर	उत्तर सर्वेक्षण प्लॉट सं. 187 का शेष भाग पूर्व : सर्वेक्षण प्लॉट सं. 187 और सर्वेक्षण प्लॉट सं. 185 और 186 का शेष भाग दक्षिण : सर्वेक्षण प्लॉट सं. 187 का शेष भाग सर्वेक्षण प्लॉट सं. 188, 189 और 190 पश्चिम : सर्वेक्षण प्लॉट सं. 187 का शेष भाग	हेमिस गुफा	वैश्विक उपयोग में		





का. प्र. 2078--केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इसमें उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट संस्मारक महत्व का है;

अतः इस केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 3 (ii) तारीख 19 जून, 1982 में प्रकाशित महानि विज्ञान (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना स. का.प्र. 2247 तारीख 19 जून, 1982 को अधिकांश करने हुए, उक्त संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, दो मास की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार विनिर्दिष्ट दो मास की अवधि के भीतर उक्त संस्मारक में हितार्थ कि या अन्य के लाभ के लिए कार्य करेगी।

#### अनुसूची

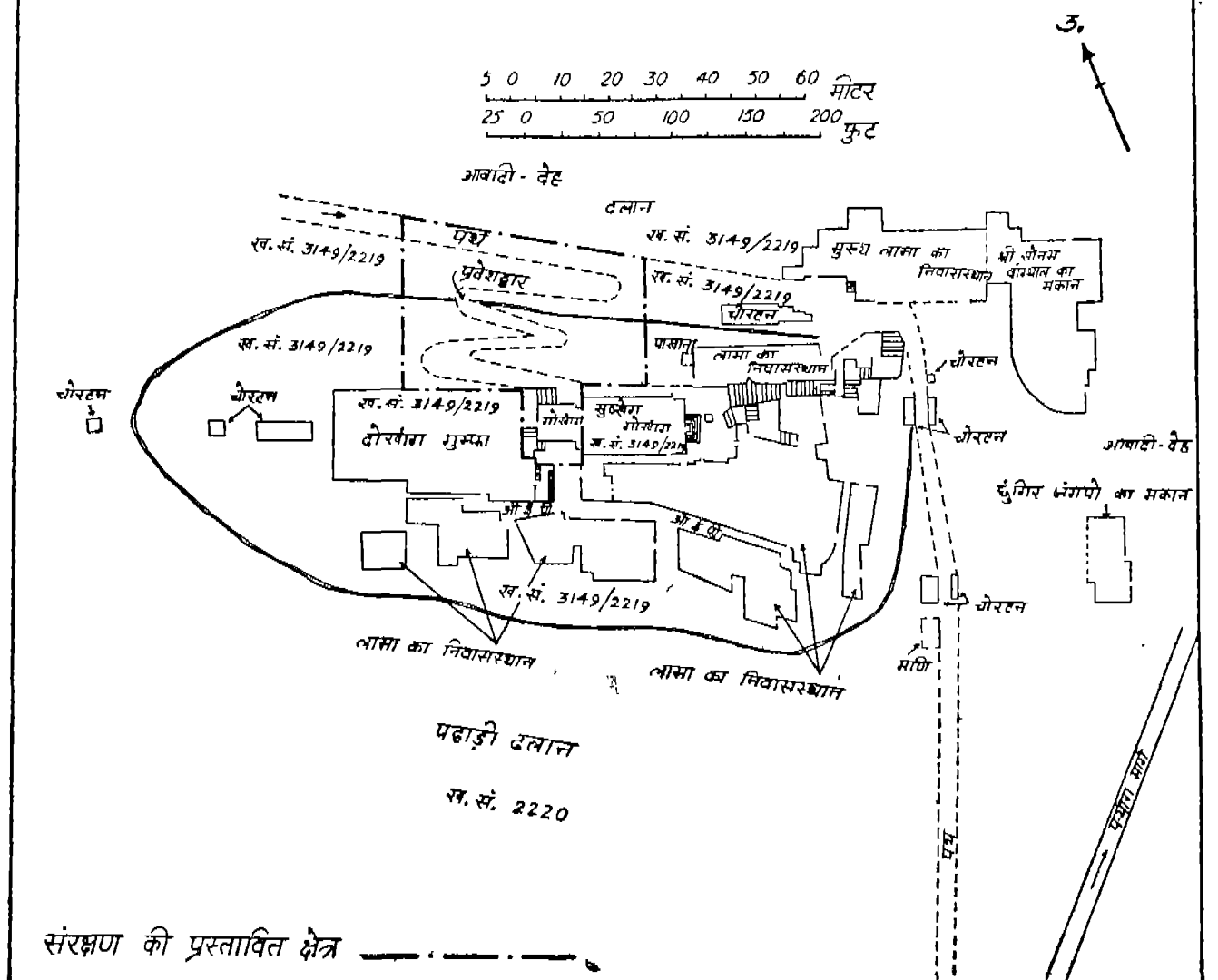
राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	संरक्षण के अर्थात् सम्मिलित हिए जाने वाला राजस्व प्लॉट संख्यांक
1	2	3	4	5	6
जम्मू-काश्मीर	सेह (लद्दाख)	सेह (लद्दाख)	पश्चात्	नीचे दिए गए स्थल रेखांक में दर्शा सर्वेक्षण प्लॉट नं. 3149 2219 के भाग में समाविष्ट मनम क्षेत्र महानि विज्ञान	नीचे दिए गए स्थल रेखांक में दर्शा सर्वेक्षण प्लॉट नं. 3149/2219 का भाग
शेष		सोमा		सामान्य	टिप्पणियाँ
	7		8	9	10
11 हेक्टेयर			उत्तर: सर्वेक्षण प्लॉट नं. 3149/2219 का शेष भाग पूर्व: सर्वेक्षण प्लॉट नं. 3149/2219 का शेष भाग दक्षिण: सर्वेक्षण प्लॉट नं. 3149/2219 का शेष भाग पश्चिम: सर्वेक्षण प्लॉट नं. 3149/2219 का शेष भाग	ग्राहबेट	धार्मिक उपयोग में

[सं 2/28/80-एम]

एन० एस० नारायणराय, सचिव सचिव पदेन



बौद्ध गुम्फा, फयांग, तहसील-लेह, जिला-लेह (लद्दाख) का स्थल मानचित्र



(स. २/२८/८०-एम.)

S.O. 2078.—Whereas the Central Government is of the opinion that the monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) and in supersession of the notification of the Department of Culture (Archaeological Survey of India) No. S.O. 2247 dated the 9th June, 1982 published in the Gazette of India,

Part II, Section 3(ii) dated the 19th June, 1982, the Central Government hereby gives two months notice of its intention to declare the said monument to be of national importance from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection which may be received from any person interested in the said monument within a period of two months so specified will be considered by the Central Government.



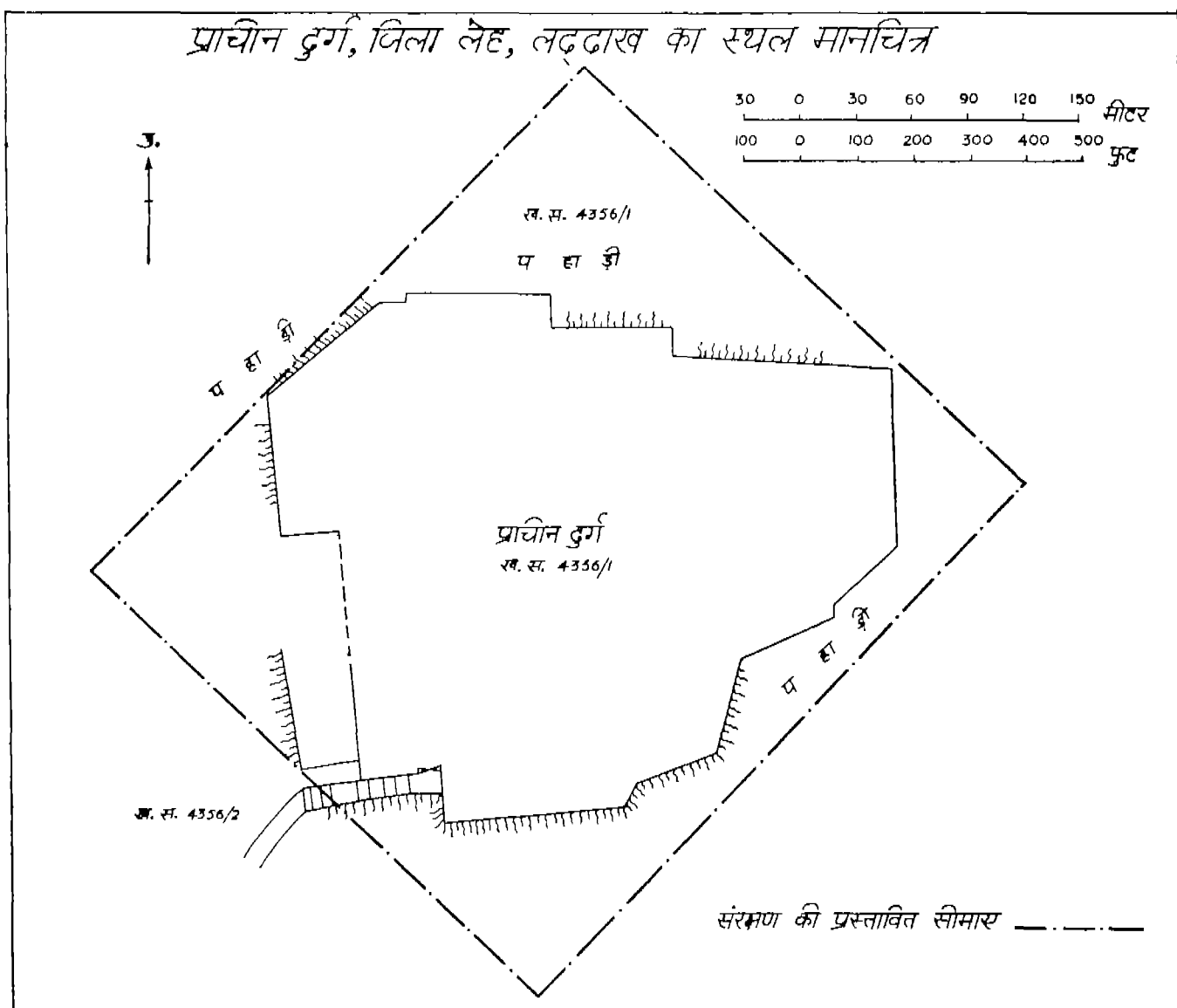
का. आ. 2079-—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसे उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्तिक राष्ट्रीय महत्त्व का है,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र भाग, II खंड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 6 फरवरी, 1932 में प्रकाशित संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की अधिसूचना सं. का. आ. 451, तारीख 21 जनवरी, 1982 को अधीकृत करते हुए, उक्त स्मारक को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने के अपने आशय को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो मास की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार, इस प्रकार विनिर्दिष्ट दो मास की अवधि के भीतर उक्त स्मारक में द्रिजबड किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	स्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले राज्य प्लॉट की सं.
1	2	3	4	5	6
जम्मू काश्मीर	लेह	लेह	लेह	सर्वेक्षण प्लॉट सं. 4356/1 में समाविष्ट मलयन क्षेत्र सहित पुराना गड	सर्वेक्षण प्लॉट सं. 4356/1
क्षेत्र	सीमा		स्वामित्व		टिप्पणियाँ
7	8		9		10
0.07 हेक्टेयर	उत्तर : पहाड़ी का अमर्बेक्षित क्षेत्र पूर्व : पहाड़ी का अमर्बेक्षित क्षेत्र दक्षिण : पहाड़ी का अमर्बेक्षित क्षेत्र और सर्वेक्षण प्लॉट सं. 4356/2 का भाग पश्चिम : पहाड़ी का अमर्बेक्षित क्षेत्र और सर्वेक्षण प्लॉट सं. 4356/2 का भाग		प्राइवेट		आवामिक उपयोग में नहीं है।



S.O. 2079.—Whereas the Central Government is of the opinion that the monument specified in the Schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) and in supersession of the notification of the Department of Culture (Archaeological Survey of India), No. S.O. 451, dated the 21st January, 1982 published in the Gazette of

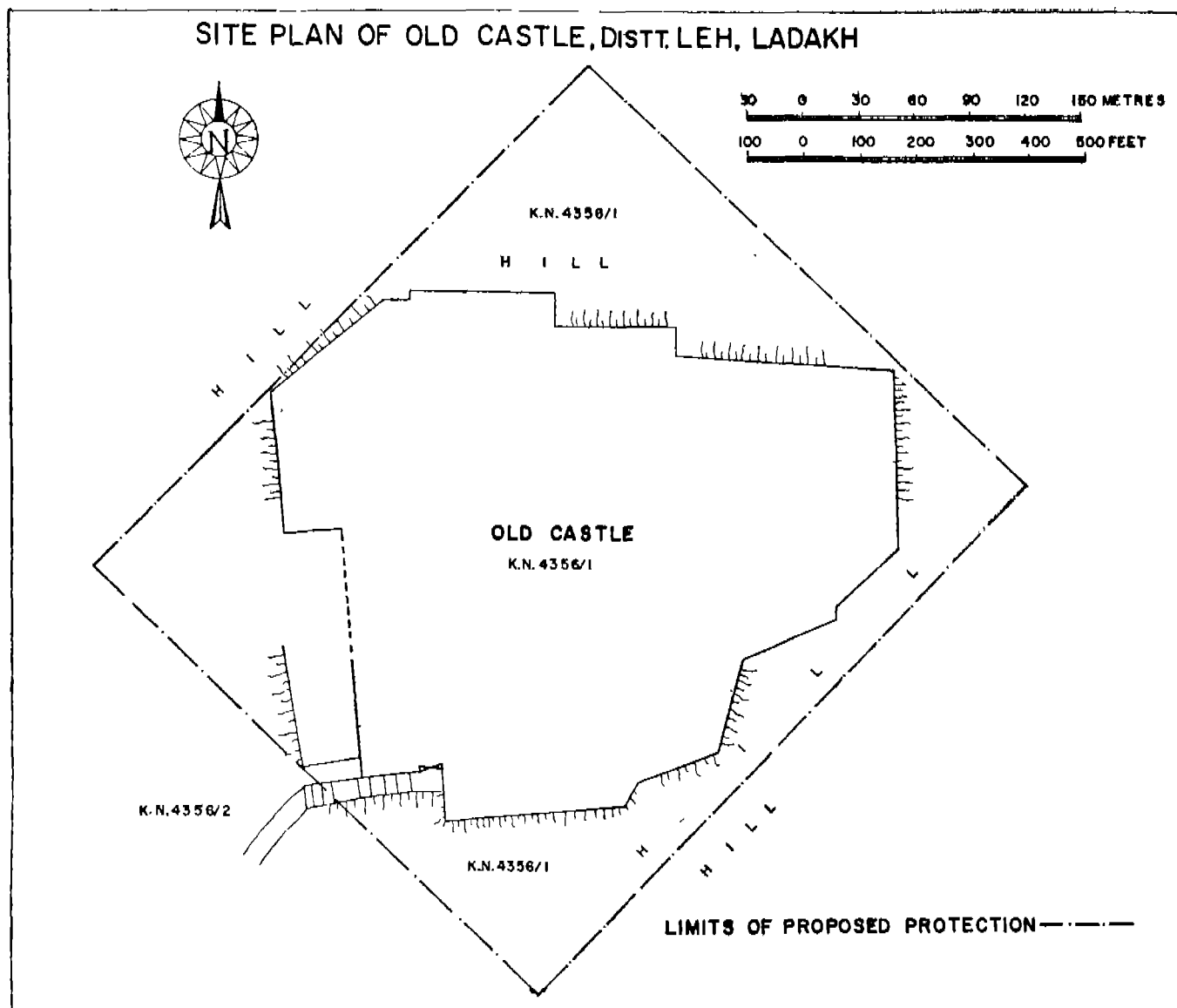
India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 6th February, 1982, the Central Government hereby gives two months' notice of its intention to declare the said monument to be of national importance from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection which may be received from any person interested in the said monument within a period of two months so specified will be considered by the Central Government.

#### SCHEDULE

State	Distt.	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jammu & Kashmir	Leh	Leh	Leh	Old Castle along with adjoining area comprised in survey plot No. 4356/1	Survey plot No. 4356/1	0.07 Hectares	North.—Unsurveyed area of hill, East.—Unsurveyed area of hill. South.—Unsurveyed area of hill and a portion of survey plot No. 4356/2. West—unsurveyed area of hill and a portion of survey plot No. 4356/1.	Private	Not in residential use.

#### SITE PLAN OF OLD CASTLE, DISTT. LEH, LADAKH



का. आ. 2080:—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संरक्षित संस्मारक के निकट या पार्श्वस्थ क्षेत्रों को खनन संक्रिया और निर्माण के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध कर दिया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्विक स्थल और अवशेष नियम, 1959 के नियम 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 2222 तारीख 18-6-1957 का अतिक्रमण करते हुए, उक्त क्षेत्रों को प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है;

जिम राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, उसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर उक्त क्षेत्रों में हिनबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आक्षेप पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

## अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	संस्मारक का नाम	प्रतिषिद्ध घोषित किए जाने वाले क्षेत्र के ब्योरे	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	रायगड	बनवेम	घारापुरी	(i) ऐलीफेंटा गुफाएं और (ii) ऐलीफेंटा द्वीप से प्राचीन ईंटों से बना स्तूप।	संस्मारकों के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर का ऐलीफेंटा द्वीप का संपूर्ण क्षेत्र और द्वीप के चारों ओर एक किलोमीटर की परिधि तक का तटीय क्षेत्र।	

टिप्पण:—अधिसूचना सं. का. नि. आ. 2222 तारीख 18-6-1957, भारत राजपत्र, भाग II खंड 2, तारीख 6-7-1957 में प्रकाशित हुई थी।

[सं. 8/1/84-एम.]

S.O. 2080.—Whereas the Central Government is of opinion that the areas near or adjoining the protected monuments in the Schedule attached hereto be prohibited for purposes of mining operation and construction;

Ministry of Education and Scientific Research No. SRO 2222, dated 18-6-1957, hereby gives notice of its intention to declare the said areas as prohibited areas;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 31 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, the Central Government, in super-session of the notification of the Government of India in the

Any objection made by any person interested in the said areas within one month after the date on which the Gazette in which this notification is published is made available to the public will be considered by the Central Government.

## SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of Monuments	Details of the areas to be declared prohibited	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
Maharashtra	Raigad	Panwal	Gharapuri	(i) Elephanta Caves and (ii) Ancient Brick Stupa at Elephanta Island.	Entire area of the Elephanta Island surrounding the protected area of the monuments and coastal area upto the radius of 1 km. all around the Island,	

NOTE :—Notification No. S.R.O. 2222, dated 18-6-1957 was published in Part I, Section 2 of the Gazette of India dated 6-7-1957.

[No. 8/1/84M]

का आ 4021 -- केन्द्रिय सरकार का राय है कि इसमें उपाबन्ध अनुसूच में विनिर्दिष्ट प्राचीन सम्मानक राष्ट्रीय महत्व का है,

अन केन्द्रिय सरकार प्राचीन सम्मानक तथा पुरातत्त्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1959 (1958 का 24) के धारा 1 का उपधारा (1) द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करने हुए और शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि (पुरातत्त्व) विभाग के अधिसूचना सं 05 4-6(1)41-एफ और एल, तारीख 30 अप्रैल 1941 का अधिकांश करने हुए उक्त प्राचीन सम्मानक को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तारीख से राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आदेश की दो मास की सूचना देन है

केन्द्रिय सरकार इस प्रकार विनिर्दिष्ट दो मास के अवधि के भीतर उक्त प्राचीन सम्मानक को से हटाकर किस भी व्यक्ति के प्रत्येक किस आदेश पर बंधार करेगा ।

#### अनुसूच

राज्य	जिला	तहसील	अवस्थान	सम्मानक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व प्लॉट संख्याएँ	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	नासिक	नासिक	त्रिाशक	त्रियंबकेश्वर मंदिर और उससे लगे गायत्र और शिव मंदिर और सर्वेक्षण प्लॉट सं 10 11 12, 13 और सर्वेक्षण प्लॉट सं 9 1327 और 1339 का भाग, जो सूच दिए गए स्थान रेखांक में दिखाए गए हैं ।	सर्वेक्षण प्लॉट सं 10, 11 12, 13 और सर्वेक्षण प्लॉट सं 9 1327 और 1339 का भाग, जो सूच दिए गए स्थान रेखांक में दिखाए गए हैं ।	7306 हेक्टर

#### संमाण

#### स्वामित्व

#### टिप्पणियाँ

8

9

10

उत्तर सर्वेक्षण प्लॉट सं 6 7 8 और सर्वेक्षण प्लॉट सं 9 का शेष भाग ।

सरकार मिलाय सर्वेक्षण प्लॉट सं 1327 के जो प्रोपर्टी स्वामित्व के अधीन है ।

पूजा का जान है ।

पूर्व सर्वेक्षण प्लॉट सं 1339, 1327 और सार्वजनिक गली का शेष भाग ।

दक्षिण सोदावरी नदी ।

पश्चिम-सर्वेक्षण प्लॉट सं 1, सार्वजनिक भूमि और सोदावरी नदी ।



S.O. 2081.—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient monuments specified in the Schedule annexed hereto are of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), and in supersession of the notification of the Department of Education, Health and Lands (Archaeology), No. F. 4-6 (2)41 F. & L, dated 30th April, 1941, the Central Govern-

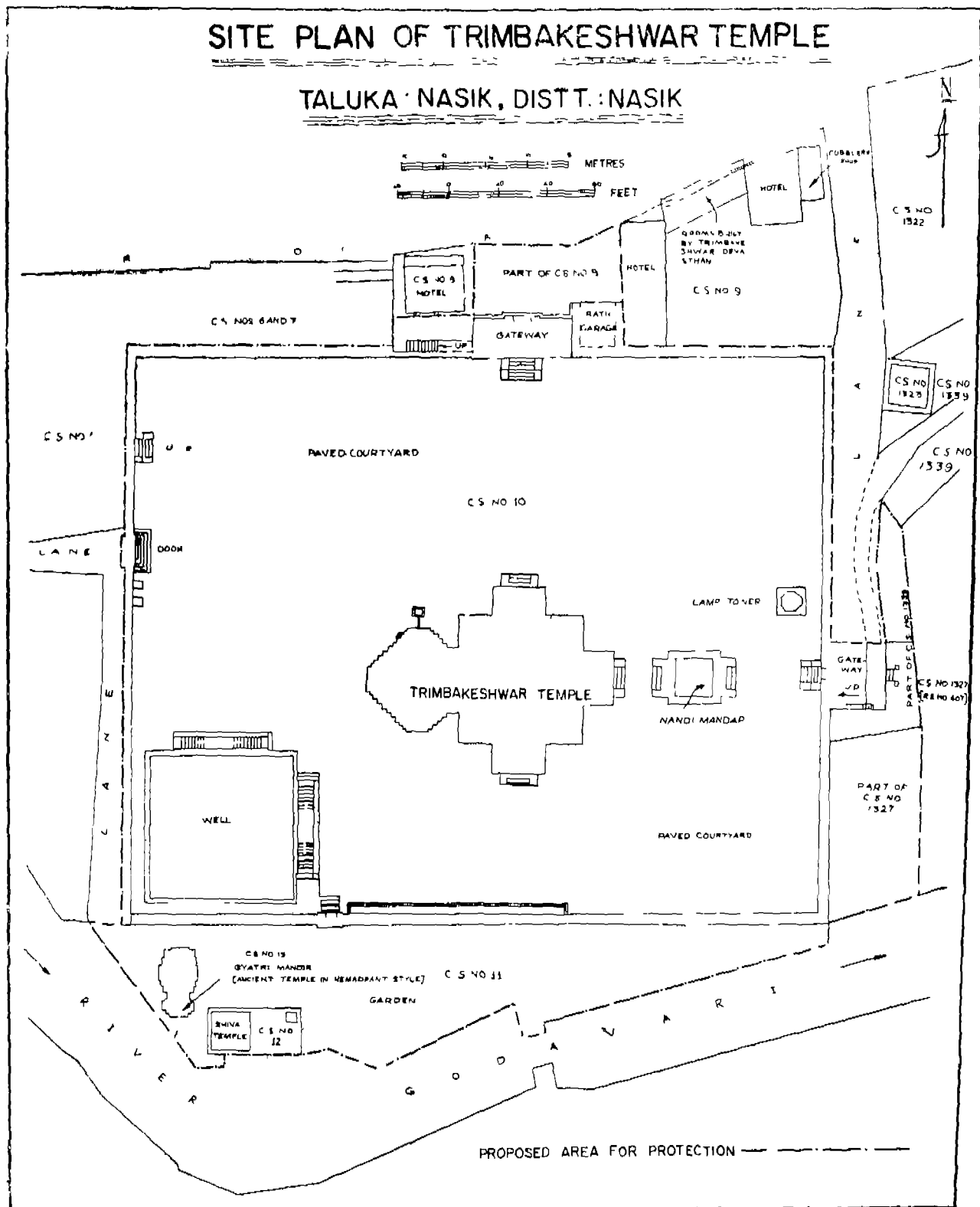
ment gives two months' notice of its intention to declare the said ancient monuments to be of national importance from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection which may be received from any person interested in the said ancient monuments within a period of two months so specified, will be considered by the Central Government.

#### SCHEDULE

State	Distt.	Tehsil	Locality	Name of monuments	Revenue plot numbers to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maharashtra	Nasik	Nasik	Tryambak	Tryambakeshwar	Survey plot Nos. 10, 11, 12, 13, and part of survey plot numbers 9, 1327, and 1339 as shown in the site plan plot numbers 10, 11, 12, 13 and parts of survey Plot numbers 9, 1327, and 1339 as shown in the site plan—reproduced below.	.7306 Hectares	North.—Survey plot Numbers 6,7,8, and remaining portion of survey plot numbers 9 and 1327 East.—Remaining portion of survey plot numbers 1339, 1327 and public lane South.—River Godavari. West.—Survey plot number 1, public land and river Godavari.	Govt. except plot No. 1327 which is under Pvt. ownership	Under Worship





[No. 2/30/73-M]

M.S. NAGARAJA RAO, Director General

&amp;

Ex-Officio Jt. Secy.

## निर्माण और आवास मंत्रालय

## MODIFICATION

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1984

का.आ. 2082—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन जिन्हें केन्द्रीय सरकार दिल्ली के लिए बृहत् योजना क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61वाँ) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 24-12-83 के नोटिस नम्बर एफ-3(50)/78-एमपी द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11 ए की उप-धारा (3) में अश्विनी अपरिमित मुसाव हम नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि में आमंत्रित किए गए थे।

और यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त संशोधनों के बारे में आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली की बृहत् योजना और क्षेत्रीय विकास योजना से संशोधन करने का निर्णय किया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार निम्न उपबन्धों की शर्त पर उक्त अधिनियम की धारा 11 ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु भारत के राजपत्र में इस अधिनियम के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की बृहत् योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

## संशोधन

जान.सो.14 के लिए दिल्ली बृहत् योजना तथा क्षेत्रीय विकास योजना में "मनोरंजनात्मक प्रयोग (जिला पार्क)" के लिए उद्दिष्ट 0.404 हेक्टेयर (1 एकड़) माप के तथा पूर्व की ओर राष्ट्रीय उपमार्ग (91:44 मीटर ओर/डबल्यू), दक्षिण की ओर मेगाजोहन रोड/मनोरंजनात्मक क्षेत्र तथा उत्तर व पश्चिम में मनोरंजनात्मक क्षेत्र से घिरे प्लॉट सं.1 मेगाजोहन रोड के भू-उपयोग को "सार्वजनिक तथा अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं" (मास्यनिक उपयोग) में बदला जाता है जैसा कि

बशर्ते कि विशेष मामले के रूप में स्वीकृत भू-उपयोग शक्ति में अन्य मामलों के लिए उद्धारण न बने विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जो यमुना नदी के सामने मनोरंजनात्मक जोना में पड़ते हों।

[स. के-13011/16/80-डी. डी. II ए]

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 31st December, 1984

S.O. 2082.—Whereas certain modification, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 3(50)/78-MP dated 24-12-1983 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by Sub-section (3) of section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice;

And whereas no objection and suggestion have been received with regard to the said modification;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government subject to provision below hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi and Zonal Development Plan with effect from the date of publication of this modification in Gazette of India, namely;

"The land use of plot No. 1, Magazine Road, earmarked for "Recreational Use (District Park)" in Delhi Master Plan and Z.D.P. for Zone C-14 measuring 0.404 Hect. (1 acre) and bounded by National Bypass (91.44 metres. R/W) towards East, Magazine Road/Recreational area towards South and Recreational area towards North and West is changed to "Public and Semi-Public facilities."

Provided that this change of land use which has been agreed to as a special case will not form precedent for other cases in future especially for areas falling in recreational zones fronting the river Yamuna.

[No. K-13011/16/80-DDIA]

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1985

का.आ. 2083 —यतः केन्द्रीय सरकार का दिल्ली बृहत् योजना क्षेत्रीय विकास योजना में नौवे उल्लिखित क्षेत्रों में कृषिय संशोधन करने का प्रस्ताव है तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिनांक 16-10-1982 के नोटिस नम्बर एफ-20 (17) /81-एमपी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उपधारा (3) में दया अश्विनी नोटिस की तारीख से 30 दिन के भीतर आक्षेप/सुझावों का आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था—

और यतः उक्त संशोधनों के सम्बन्ध में आक्षेप और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने बृहत् योजना और क्षेत्रीय विकास योजना का संशोधन करने का निर्णय लिया है।

अब यतः उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु, केन्द्रीय सरकार एवम् द्वारा दिल्ली की उक्त बृहत् योजना और क्षेत्रीय विकास योजना में भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

## संशोधन

(1) क्षेत्रीय एफ-7 में पड़ने वाले लगभग 0.81 हेक्टे. (2.00 एकड़) क्षेत्र जिसके उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में 'सामाजिक एवम् सांस्कृतिक संस्थान' दक्षिण-पश्चिम की ओर 18.3 मी. (60 फुट) मार्गाधिकार की सड़क और आवासीय क्षेत्र (मुख्यदेव विहार) तथा दक्षिण-पूर्व में 18.3 मी. (60 फुट) मार्गाधिकार की सड़क है, का भूमि उपयोग सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान से बदलकर आवासीय (समूह-आवास) किया जाता है।

(ii) क्षेत्रीय एफ-7 में पड़ने वाले लगभग 0.17 हेक्टे. (0.42 एकड़) क्षेत्र, जिसके उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में 'सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान' दक्षिण-पूर्व में 'मनोरंजनात्मक' उपयोग की भूमि है, का भूमि उपयोग से 'संवरण' से बदलकर आवासीय (समूह आवास) किया जाता है।

(iii) क्षेत्र एफ-7 में पड़ने वाले लगभग 7.01 हेक्टे. (17.33-एकड़) क्षेत्र जिसके उत्तर पूर्व में मनोरंजनात्मक उपयोग क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम में 18.3 मी. (60 फुट) मार्गाधिकार की सड़क और आवासीय क्षेत्र (मुख्यदेव विहार), दक्षिण-पश्चिम में शैक्षणिक उपयोग केन्द्रिय सड़क अनुसन्धान संस्थान और दक्षिण-पूर्व में मनोरंजनात्मक उपयोग का क्षेत्र है, का भूमि उपयोग मनोरंजनात्मक से बदलकर आवासीय (समूह आवास) किया जाता है।

[स.के.-13011/8/81-ज.डी. II-ए]

कृष्ण कुमार सक्सेना, प्रधान सचिव

New Delhi, the 22nd April, 1985

तालिका

S.O. 2083.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the areas mentioned here under, were published with Notice No. F. 20(17)/81-MP dated 16-10-1982 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice.

And whereas, the Central Government after considering the objections and suggestions with regard to the said modifications have decided to modify the Master Plan and Zonal Development Plan;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi and Zonal Development Plan with effect from the date of publication of this modification in Gazette of India, namely :—

## MODIFICATIONS :

- (i) "The land use of an area measuring about 0.81 hect. (2.00 acres) falling in zone F-7 and bounded by the 'Social Cultural Institutions' towards its north-west and north-east 18.3 mts. (60 ft.) right-of-way road and residential area (Sukhdev Vihar) towards its South-West and 18.3 mts (60 ft.) right of way road on its South-East is changed from 'Social & Cultural Institutions' to 'Residential' (Group Housing)."
- (ii) The land use of an area measuring about 0.17 hect. (0.42 acre), falling in zone F-7, and bounded by Social & Cultural Institutions towards its North-West and North-East and recreational land use towards its South-East is changed from 'Circulation' to 'Residential' (Group Housing).
- (iii) The land use of an area measuring about 7.01 hect. (17.33 acres) falling in zone F-7 and bounded by recreational use towards its North-East, 18.3 mts. (60 ft.) road right-of-way and residential area (Sukhdev Vihar) towards its North-West, educational (Central Road Research Institute) towards its South-West and recreational area, towards its South-East is changed from 'Recreational' land use to 'residential' (Group Housing).

[No. K-13011/8/81-DDIIA]

K. K. SAXENA, Under Secy.

(वर्क डिविजन)

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1985

का०आ० 2084—लोक परिसर (अनधिकृत रखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार निम्न तालिका के कालम 1 में उल्लिखित अधिकारी को, सरकार राजस्वित अधिकारी होने के नाते, सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है जो उक्त तालिका के कालम 2 के तालिका की दृष्टि में निर्धारित लोक परिसर के सम्बन्ध में स्थानीय सीमा के भीतर अपने क्षेत्राधिकार में शक्तियों का उपयोग करेगा और उक्त अधिनियम में या उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को दिये गये कर्तव्यों को निभायेगा और शक्तियों का उपयोग करेगा।

अधिकारी का पदनाम	लोक परिसर की श्रेणियाँ और क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा।
1	2
कार्यपालक इंजीनियर "जी" मण्डल केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग, नई दिल्ली।	निम्न अनुलग्नक में यथा उल्लिखित में सामान्यपूल कार्यालय बास तथा रिहूयशी बास जिनका अनुरक्षण कार्यपालक इंजीनियर "जी" मण्डल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नई दिल्ली के पास है को छाड़कर लोक परिसर
	अनुलग्नक

कार्यपालक इंजीनियर "जी" मण्डल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दिल्ली के क्षेत्राधिकार के भीतर अनुरक्षणार्थ निम्नलिखित क्षेत्र कालोनिया आती है।

1. सरोजिनी नगर सभी सरकारी रिहायशी बास, बाबू मार्केट, समाज सदन, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय।
2. नौरोजी नगर 628 सामान्यपूल क्वार्टर।
3. चाणक्यपुरी नेहरू पार्क के सामने, सत्यमार्ग के चौराहे तक विनयमार्ग का क्षेत्र और डी-I तथा डी-II सरकारी क्वार्टर और सत्यमार्ग, नई दिल्ली के बाईं ओर क्लब, तथा चाणक्यपुरी पूछताछ कार्यालय।
4. नेताजी नगर सभी टाइप का रिहूयशी बास, समाज सदन क्षेत्रीय लेखन सामग्री डिपो और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय।
5. आर.के.पुरम सेक्टर XIII उच्च अधिकारियों के लिए 138 टाईप-5 तथा 115 टाईप-5 क्वार्टर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्टॉक क्वार्टर और ऊपरी जल की टर्को।
6. मोतीबाग मोती बाग, (घरण-I) तथा वेस्ट मोती बाग आई० बी०, कालोनी, पानी की दो बड़ी टर्कियाँ, के०स०स्वा० योजना औषधालय, और समाज सदन क्षेत्र।
7. गुरु तानक पुरा सामान्यपूल क्वार्टर, पूछताछ कार्यालय, सेक्टर-12 के 1 से 16 तक डी-II क्वार्टर।

[फाइल सं० 20014/44/82-वि० 3/ई० डब्ल्यू-2]

आर० एल० परवीप, संयुक्त सचिव

(Works Division)

New Delhi, the 1st April, 1985

S. O. 2084:—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in the column 1 of the Table below, being gazetted officer of Government, to be estate officer who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act

within the Local Limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table:

TABLE

Designation of officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction.
1	2
Executive Engineer, 'G' Division, Central Public Works Department, New Delhi.	The public premises excluding general pool office and residential accommodation, in the areas as mentioned in the Annexure below, the maintenance of which is under the jurisdiction of the Executive Engineer, 'G' Division, Central Public Works Department, New Delhi.

## ANNEXURE

The following areas/colonies came under the jurisdiction of Executive Engineer, 'G' Division, Central Public Works Department, New Delhi for maintenance :

1. Sarojini Nagar : All the Government residential accommodation Babu Market, Samaj Sadan, Central Government Health Scheme Dispensary.
2. Nauroji Nagar : 628 General pool quarters.
3. Chankyapuri : In front of Nehru Park, the area of Vinay Marg upto the crossing of Satya Marg and the D-I and D-II Government quarters and club on the right side of Satya Marg, New Delhi and Chankyapuri enquiry office.
4. Netaji Nagar : All type of residential accommodation, Samaj Sadan, Regional Stationary Depot and Central Government Health Scheme Dispensary.
5. R. K. Puram, Sector-XIII; 138 type-V and 115 type-VI quarters for high ranking officers, staff quarters of Central Public Works Department and a high water tank.
6. Moti Bagh : Moti Bagh (Phase-I), North-West Moti Bagh, Information Bureau Colony, two big water tanks, Central Government Health Scheme Dispensary and Samaj Sadan area.
7. Guru Nanak Pura : Central pool quarters, enquiry office, the D-II quarters Nos. from 1 to 16 in Sector-XII.

[F. No. 20014/44/82-W.3/EW.2]

R. L. PARDEEP, Jt. Secy.

मई दिल्ली, 7 मई, 1985

का.आ. 2085.—राष्ट्रपति मूल नियम के नियम 45 के अनुसरण में सरकारी निवास स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी निवास स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी निवास स्थान आबंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियम, 1963 में अनुपूरक नियम 317-ख-8 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि अधिकारी अधिकारी पूल में भी उस टाइप में निवास स्थान के आबंटन के लिए हकदार होगा जिस टाइप के लिए वह हकदार है।”

टिप्पणी :— मूल नियम भारत सरकार के निर्माण और आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय (निर्माण और आवास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1330 तारीख 6 मई, 1963 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

नियम, 1980 में (सितम्बर, 1979 तक संशोधित) पुन मूद्रित किए गए थे। उसके पश्चात्, उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है :—

(I) अधिसूचना सं. 17013(1)/81 नीति II तारीख 14.4.82 का. आ. सं. 1607 तारीख 24.4.82

(II) सं. 12035(6)/75 नीति 11 (जिल्द II) तारीख 22-11-82 का. आ. सं. 4202 तारीख 18.12.1982

(III) सं. 12035 (1)/82 नीति II तारीख 1.2.83 मा.का.नि. 159 तारीख 19-2-83

[का.सं. 12034(1)/84 नीति I]

वी.एस. रामन, संपदा उपनिदेशक (नीति)

New Delhi, the 7th May, 1985.

## NOTIFICATION

S.O. 2085.—In pursuance of the provisions of rule 45 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Allotment of Government Residences (General pool in Delhi) Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Allotment of Government Residences (General pool in Delhi) Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Allotment of Government Residences (General Pool in Delhi) Rules, 1963, in supplementary Rules 317-B-8, after sub-rule (3), the following proviso shall be added namely :—

“Provided the officers shall also be entitled to allotment of accommodation in the entitled type from Tenure Officers' Pool.”

Note :—Principal rules were published under the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing and Rehabilitation (Department of Works & Housing) vide S.O. No. 1330 dated the 6th May 1963.

The rules were re-printed in 1980 (corrected upto September, 1979).

Subsequently amended by :—

(i) Notification No. 17013(1)/81-Pol. II dated 14-4-82 S.O. No. 1607 dated 24-4-82.

(ii) No. 12035(6)/75-Pol. II (Vol. II) dated 22-11-82 S.O. No. 4202 dated 18-12-1982.

(iii) No. 12035(1)/82-Pol. II dated 1-2-83 GSR 159 dated 19-2-1983.

[File No. 12024(1)/84-Pol. II]

Y.S. RAMAN, Dy. Director of Estates (Policy)

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय**

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 1985

शुद्धि पत्र

का. अ. 1086.—भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना स. का. अ. 2950 दिनांक 24-11-1984 को जो भारत सरकार के राजपत्र के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, साथ संलग्न अनुसूची में, मद संख्या तीन में, प्रत्येक ट्रेलर के स्वीकृत भार की सीमा के स्थान पर इस कार्य के लिए निम्नलिखित सीमा निश्चित की जाती है :—

सामान का एकल लोड	7.60
पीछे का एकल लोड	20.30
कुल लदा भार	27.90

[फाइल नं. टी. डब्ल्यू/टी.जी.एम. (63)/84]

प्रादीप सिंह, उप सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT**

(Transport Wing)

New Delhi, the 27th April, 1985

**CORRIGENDUM**

S.O. 2086.—In the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) Notification No. S.O. 2950 dated 24-11-1984 published in the Gazette of India Part II Section 3, sub-section (ii), in the Schedule appended thereto, in place of limits specified against item No. 3 relating to recommended load of each trailer, following shall be substituted :—

Front axle load—7.60 t

Rear tandem axle load—20.30 t

Gross laden weight—27.90 t

[File No. TW/TGM(63)/84]

PRADEEP SINGH, Dy. Secy.

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1985

का. अ. 2087.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (सब के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अन्वय में, पत्र सूचना कार्यालय के शाखा कार्यालय, कानपुर का जिसके कर्मचारी वृत्त ने हिन्दी का कार्य-संघक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

[संख्या ई 11011/35/83-हिन्दी]

इन्दु भूषण कर्ण, जबर सचिव

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**

New Delhi, the 19th April, 1985

S.O. 2087.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the Branch Office, Kanpur of Press Information Bureau, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. E. 11011/35/83-Hindi]

I. B. KARAN, Under Secy.

**श्रम मंत्रालय**

नई दिल्ली, 25 अप्रैल 1985

का. अ. 2088.—औद्योगिक विवाद प्रावित्यम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार धर्मबांद कोलियरी नैमज भारत कोकिंग कोल लि. के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अन्वय में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, न. 2, धनबाद के पनाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-4-85 को प्राप्त हुआ था।

**MINISTRY OF LABOUR**

New Delhi, the 25th April, 1985

S.O. 2088.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dharmaband Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th April, 1985.

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO 2) AT DHANBAD****PRESENT :**

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer

Reference No. 82 of 1984

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

**PARTIES :**

Employers in relation to the management of Dharmaband Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

**APPEARANCES :**

On behalf of the employers—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal

Dated Dhanbad, the 15th April, 1985

**AWARD**

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. 1-24012(28)/84-D.IV(B) dated, the 31st October, 1984.

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of Dharmaband Colliery of M/s. BCCIL in dismissing Sri Bisunpat Singh is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

The case of the management is that the concerned workman Shri Bisunpat Singh who was working as Switch Board Attendant absented from duty for more than 10 days since 10-9-80 and as such he was chargesheeted for misconduct under Clause 29(16) of the Standing Orders of the management. In spite of several notices issued to the concerned workman none of them were personally served on the concerned workman. The management came to the conclusion that the concerned workman was avoiding service of the notices of the enquiry proceeding and as such the enquiry proceeded against him ex parte. The enquiry Officer found the concerned workman guilty of the charge and thereafter the concerned workman was dismissed from service by the Agent vide his letter dated 3/6-5-1982. The management or the Enquiry Officer were never informed of the whereabouts of the concerned workman.

The case of the concerned workman is that he was originally appointed as Switchboard attendance in the year 1967 by the erstwhile management and that the said management had stopped the work of the concerned workman along with others for their trade union activities. An industrial dispute was raised by Bihar Colliery Kamgar Union challenging the termination of their services which was ultimately referred in Ref. 23/70. The Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad made an Award in the said reference in favour of the concerned workman and others directing the management to reinstate them with full back wages. In 1980 the concerned workman was reinstated at Dharmaband Colliery in pursuance of the Award in Reference No. 23 of 1970. The case of the concerned workman further is that after his reinstatement, he started demanding back wages as per the Award and started championing the grievances of the workmen. The management did not like the union activities of the concerned workman and as such a false chargesheet dated 5-5-80 was issued against him in order to harass but the concerned workman was absolved of the said charges. The management was always in the look out to dispense with the services of the concerned workman and when he was detained by the police under N. S. Act and absented from duties, the management issued chargesheeted against him and after holding an ex parte enquiry proceeding dismissed him from service. The management has never served any notice to the concerned workman in respect of the enquiry proceeding and he was not aware of the said enquiry proceeding. The concerned workman was released from detention on 1-11-81 and thereafter he reported for duty on 14-12-81. The management assured him to look into the matter and handed over the order of dismissal dated 3/6-5-82 instead of allowing him to resume his duties. At the time when the concerned workman was detained under N.S. Act, the Secretary of Bihar Colliery Kamgar Union had sent a letter dated 25-9-80 to the Manager, Dharmaband Colliery informing the management that the concerned workman was arrested by the police and as such he could not attend his duties from 10-9-80 and that leave may be granted to him and that he would join his duties after his release from Jail. It is submitted on behalf of the concerned workman that the said letter was received by the Head Clerk of Dharmaband Colliery and that verbally also the management was informed through some of the workmen about the detention of the concerned workman under N.S. Act. The concerned workman and the union had requested the management to reinstate him and when he was not taken in employment, an industrial dispute was raised and on failure of the conciliation proceeding before the ALC(C), Dhanbad the present reference was made.

The management had raised a preliminary point before the Tribunal that in view of the fact that legality and propriety of the domestic enquiry was being challenged by the workmen, a preliminary enquiry may be made whether the domestic enquiry against the concerned workman was fair and proper and in case the domestic enquiry was not found to be fair and proper, the management may be given opportunity to lead evidence to justify the action taken by the management. The said prayer of the management was allowed and it was held on the aid preliminary point that the ex parte domestic enquiry against the concerned workman was not fair and proper and the management was allowed to adduce evidence before the Tribunal to establish the charges against the concerned workman.

This award therefore deals with the merit of the case with reference to the evidence adduced by the parties before this Tribunal.

The only point to be determined in this case is whether the management has been able to justify the dismissal of the concerned workman.

The management has examined three witnesses in support of its case whereas the workmen have examined four witnesses in support of the case of the concerned workman. Besides that both the parties have produced documents which have been marked exhibits in this case.

The simple point to be decided in this case is whether the concerned workman had absented for more than 10 days with-

out permission and without satisfactory cause so as to find him guilty of misconduct as contemplated under clause 29(16) of the Standing Orders Ext. M-21 of the management.

There is no denial of the fact that the concerned workman had not absented from duty from 10-9-80. The management has produced attendance registers in Form E which is marked Ext. M-20 in this case which will show that the concerned workman absented from duty from 10-9-80. The concerned workman WW-1 Bisunpat Singh has stated that he had previously been arrested in connection with the case of murder of one N. Poddar of Sudamdih Washery and that while he was in jail in connection with that case he was served with N.S. Act detention order. The concerned workman has exhibited detention order Ext. W-5 dated 27-12-80. This detention order shows that Shri Balram Singh son of Bijli Singh was detained under N.S. Act, from first of November, 1980 to 31-10-1981. Ext. W-6 is a certificate from the Superintendent of Dhanbad Jail dated 19-3-83 which shows that Balram Singh son of Bijli Singh of village Secunderpur, P. S. Arbal, Dist. Gaya present address Loco Bazar, Patherdih, District Dhanbad who was in custody in connection with another case was detained under N.S. Act from 1-11-80 and was released on 1-11-81 after the expiry of the period of this detention and that the said Balram Singh was released in respect of other case afterwards. It is clear therefore from Ext. W-5 and W-6 that Balram Singh son of Bijli Singh of village Secunderapur, P.S. Arbal, District Gaya residing at Loco Bazar Patherdih, District Dhanbad had been detained under N.S. Act from 1-11-1980 to 31-10-81 and that he was also in custody in other criminal case even prior to the said detention. The case of the workmen is that the concerned workman is named Bisunpat Singh alias Balram Singh and that the concerned workman who was popularly known as Balram Singh in the colliery was detained under N.S. Act. The case of the management on the other hand, is that Balram Singh was a different person than the concerned workman. We have therefore to find out whether the concerned workman Bisunpat Singh was also known as Balram Singh.

The concerned workman WW-1 has himself stated that there is no entry of his name as Balram Singh in any of the Register of the management. Ext. M-22 is the photo copy of the Form B Register in which the concerned workman has been shown as Bisunpat Singh son of Bijli Singh of village Secunderpur, P.S. Arbal, District Gaya and is also signed by the concerned workman Bisunpat Singh. This entry in Form B Register shows that the concerned workman had declared his name as Bisunpat Singh and had not given his alias name as Balram Singh in the said register. As I have already stated above that the concerned workman has admitted that in none of the registers of the management his name has been stated as Balram Singh and as such the entries in Ext. M-22 do not completely negative the assertion of the concerned workman that he was also known as Balram Singh.

MW-1 who was the enquiry officer in this case has stated that the concerned workman was not known as Balram Singh. MW-2 has stated that he does not know if the concerned workman is known as Balram Singh in the colliery. MW-3 has stated that there is no person of the name of Balram Singh working in Dharmaband Colliery. Admittedly, the concerned workman was entered in the register of the management as Bisunpat Singh and not as Balram Singh and as such the statement of MW-3 does not eliminate the possibility of Bisunpat Singh having an alias name Balram Singh. The oral evidence of the concerned workman WW-1 Bisunpat Singh is that he is also known as Balram Singh. It was suggested to him in the cross-examination that he was not Bisunpat Singh and that he was known only as Balram Singh to which the concerned workman had replied that it is not a fact that he was not Bisunpat Singh and that he was known only as Balram Singh. This suggestion put to the concerned workman on behalf of the management has almost admitted the case of the concerned workman. By this suggestion it is admitted that the concerned workman was known as Balram Singh only. Admittedly the concerned workman is named as Bisunpat Singh and this is not denied by the management in

his W.S. The suggestion that the concerned workman was known only as Balram Singh therefore shows that the concerned workman Bisunpat Singh was also known as Baham Singh. WW-2 is working as Lamp Issue Clerk in Dharmaband Colliery. He has stated that the concerned workman Bisunpat Singh is also known as Balram Singh. WW-2 is Mukhiya of Deoghara Gram Panchayet and had issued a certificate under his signature Ext. W-4. The said certificate Ext. W-4 issued by WW-2 shows that Bisunpat Singh alias Balram Singh son of Bijli Singh of Village Secunderpur, Debai, P.S. Arbal, Dist. Gaya presently residing at Loco Bazar Pathchidh, District Dhanbad is known to him and that the concerned workman was in custody from 1-11-80 to November, 1981 in Dhanbad Jail. He has also attested the photograph pasted on Ext.W-4 that the said photograph is of Bisunpat Singh alias Balram Singh. WW-3 was working along with the concerned workman since the erstwhile management. He has stated that the concerned workman Bisunpat Singh was also known as Balram Singh. WW-4 a co-worker of the concerned workman has also stated that the concerned workman Bisunpat Singh was also known as Balram Singh. Thus the oral evidence on behalf of the workman shows that Bisunpat Singh was also known as Balram Singh in the colliery. But the most important document in this case in proof of the assertion of the concerned workman is Ext.W-7 which is a certified copy of FIR lodged by Shri D. N. Singh, Assistant Manager, Khas Dharmaband Colliery. The said FIR was lodged on 28-4-69. It will appear from the said FIR that Bisunpat Singh alias Baham Singh was also an accused along with others in that case again whom the Assistant Manager had lodged an information before the Police. The concerned workman Bisunpat Singh is described as Balram Singh by the Asstt. Manager in the year 1969 long before the present case and there appears to be no reason to disbelieve the said FIR. An affidavit Ext.W-8 dated 23-3-85 has also been filed by M. Inamuddin, Pleader Dhanbad Court which shows that Shri Inamuddin identified the concerned workman Shri Bisunpat Singh alias Balram Singh and that he has also attested the photograph of the concerned workman pasted on Ext.W-8. Another important factor in this connection is that Bisunpat Singh has been shown as son of Bijli Singh of village Secunderpur Debai P. S. Arbal, Distt: Gaya in Form B Register of the management. The Detention order Ext.W-8 has described Balram Singh as son of Bijli Singh. Ext.W-6 describes Balram Singh as son of Bijli Singh of village Secunderpur Debai, P. S. Arbal Dist. Gaya. Thus these exhibits coupled with the oral evidence adduced on behalf of the concerned workman clearly establish that the concerned workman Bisunpat Singh had his alias name Balram Singh and that the concerned workman had been taken in custody under N.S. Act and criminal case since before 1-11-80.

The case of the workmen is that he was taken in custody in connection with a murder case and during that detention he was also detained under N.S. Act Act, from 1-10-80 and remained in custody under N.S. Act till 31.10-81. As the concerned workman was detained in custody it was not possible for him to attend to his work in the colliery. Ext. W-1 is a letter by the Secretary of Bihar Colliery Kamgar Union dated 25-9-80 by which the Manager of Dharmaband colliery was informed of the arrest of the concerned workman by the police from 10-9-80 due to which he was unable to attend his duties and that the Secretary of the Union had prayed for granting leave to the concerned workman and that the concerned workman would join his duties after release from jail. It is stated on behalf of the workmen that this letter was filed in the office of the management. MW-1 has exhibited this W-1 and has stated that this letter was received by the Head Clerk of the colliery and the same bears the signature of the Head Clerk on Ext.W-1. WW-1 has stated that when he was produced before the Dy. Commissioner in the National Security Act case he had informed his union Secretary about the detention and requested him to inform the management about his detention under N.S. Act. WW-2 has stated that he had informed the Personal officer of the management that the concerned workman had been arrested and was in jail. WW-3 has stated that Ext.W-1 was given to him by Shri D. Mukherjee Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union and that he had handed over Ext.W-1 to the Head Clerk. WW-4 has also stated that he informed the Welfare Officer and Engineer regarding the arrest of the

concerned workman. It is thus clear that Ext.W-1 was handed over to the Head Clerk of the Dharmaband Colliery and that the management was informed of the detention of the concerned workman in the custody. It is true that the application for leave has to be made by the workman himself. But the question is whether the concerned workman has been able to show that he had absented on some reasonable ground. Ext.W-1 shows that the management was informed of the detention of the concerned workman and as such the concerned workman could not attend his duties in the colliery. MW-2 who is working as colliery engineer of Dharmaband has stated that the Head Clerk of Dharmaband Colliery looks after all the work of the colliery and that he had not enquired from the Head Clerk whether the Head Clerk had received any letter from the concerned workman regarding his leave. He has further stated that he did not know if the Head Clerk had received a letter on 25-9-80 which was sent on behalf of the concerned workman. If the engineer had dared to enquire from the Head Clerk he might have been informed about the detention of the concerned workman as an intimation had been sent to the office regarding the detention of the concerned workman in the jail.

The evidence discussed above will show that the concerned workman had continuously absented from 10-9-80 for more than 10 days and the management was competent to charge-sheet the concerned workman for misconduct as the concerned workman had not taken any permission for leave. In the present case the concerned workman had not absented of his own accord. He was taken in custody first in connection with the murder of a person in a criminal case and thereafter he was detained under N.S. Act as such it was not possible for him to apply for leave. It will appear that the union Secretary had sent an information before the management regarding the detention of the concerned workman from 10-9-80 and had also requested the management to grant him leave. In my opinion the concerned workman has been able to give satisfactory cause for absents for more than 10 days without permission and in the circumstances of the case it was too harsh on the part of the management to dismiss him from service on the allegation that he was absents continuously for more than 10 days without permission when the concerned workman had absolutely no control of his own in respect of his detention in the custody under National Security Act and in connection with a criminal case. Now the entire matter has come to light and on the facts disclosed I do not think that the management was justified in dismissing the concerned workman on account of his long absence without permission in the circumstances of the case.

In view of the consideration of the entire facts, evidence and circumstances of the case I hold that the action of the management of Dharmaband Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. in dismissing Shri Bisunpat Singh is not justified. The concerned workman, therefore, is entitled to be reinstated to his job. As he was in custody in jail and had reported for duty on 14-12-81 the concerned workman will not be entitled to the wages from 10-9-80 to 13-12-81 and will be entitled with all back wages and other benefits to which he may be entitled from 14-12-81. However, the period of the detention of the concerned workman from 10-9-80 to 13-12-81 will be treated on duty for the purpose of continuity of his services.

This is my Award.

I. N. SINHA Presiding Officer.  
[No. L-24012(28)/84-D.IV(B)]  
R. K. GUPTA, Desk Officer

नई दिल्ली 25 अप्रैल 1985

का प्र. 2089—आयोगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) के धारा 17 के अनुसरण में कन्द्रीय सरकार यूनिवर्सल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधक ने सम्बद्ध नियोक्ता और उनके कर्मचारी के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में कन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर ने पत्रों का प्रकाशित करत है जो कन्द्रीय सरकार का 12-4-85 का प्राप्ति हुआ था।

New Delhi, the 25th April, 1985

S.O. 2089—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Kanpur, is shown in the annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Union Bank of India and their workmen which was received by the Central Government on the 12th April, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM LABOUR COURT, KANPUR

I.D. No. 24 of 1983

In the matter of dispute between

Shri Algoo Ram Sub Staff, C/o The General Secretary  
Union Bank Employees Union, Union Bank of India  
Hazrat Ganj, Lucknow

AND

The Asstt General Manager Union Bank of India  
Zonal Office, Hotel Clark Awadh, Hazrat Ganj  
Lucknow

AWARD

The Central Government Ministry of Labour, vide order No. L-12/12/58/82-D II(A) dt 12th October, 1982 has referred the following dispute for adjudication

"Whether the action of the management of Union Bank of India in relation to their Mardah Branch in not paying 1/3rd of scale wages to Shri Algoo Ram Part time Sweeper as well as not regularising him in that post is justified? If not to what relief the workman is entitled?"

It is common ground that the workman Shri Algoo Ram was appointed as part time sweeper in Mardah Branch of the Union Bank of India but according to the workman he is working since June 1972 when the branch of the bank was opened initially. Whereas according to the management the workman was appointed w.e.f. 1st October 1979. The workman has alleged that he was working for more than 6 hours per week and as per bipartite settlement he is entitled for 1/3 of the scale wages but according to the management he was paid Rs. 50 per month. As according to the terms of appointment he was required to work 5 3/4 hours per week only. The obvious purpose was that it should not exceed 6 hours as in that case the management would be required to pay 1/3rd of the scale wages in view of the above said settlement. The branch manager had informed the workman that in all other days except Sunday he will work for one hour i.e. from 9 a.m. to 10 a.m. and on Saturday from 9 a.m. to 9.45 a.m. The Union of the workman made demand for 1/3rd of scale of wages in June 1981 and thereafter Zonal Office Varanasi recommended payment

of 1/3rd of scale of wages to the workmen. The appointment letter was so worded that the applicant may not gain one third of the scale of wages, that the management with a view to deprive the workman from one third scale of wages issued an appointment order that from Saturday the workman should work for only 45 minutes and not for one hour. That the action of the management is a clear indication of unfair labour practice and the appointment order limiting the working hours of the workman to 5 3/4 hours per week on that account is illegal.

The management has filed three papers with list dated 9th May, 84. The first letter of the branch manager shows that even in September 78 Algoo Ram was working as part time sweeper in the branch and his weekly hours of work was about 12 hours. As regards the date of the working hours the branch manager mentioned that the same was not traceable as he was not issued any appointment letter either by the branch or by Head Office. In another of the branch manager Mardah Branch dated 23rd September, 78 it is mentioned that actual date of start of work is not known. He is working for the last four years. Thus the approximate period since when the workman could be deemed working comes to 74. Regarding working hours per week in this letter also it is mentioned that he is working 12 hours in a week. The management has also filed the appointment letter dt 18 Oct, 79 which shows that the workman was appointed w.e.f. 1st October 1979, meaning thereby that 17 days ahead of the issuance of the order which shows that he was appointed w.e.f. 1st Oct 79 and was working in the bank from before. As regards the date it is mentioned that as regards his duties, it is mentioned that the same would be cleaning and sweeping the office, furnitures and fixtures storing and supplying the drinking water and other work incidental to cleaning of the office premises. It doesn't seem to reason that besides sweeping the office floor and dusting table chairs and other fixtures, the workman was required to store water and supplying it to the persons working in the bank and also the persons who are coming to the bank and all this was required to be done within one hour i.e. from 9 a.m. to 10 a.m. and on Saturday even in shorter period of 45 minutes. The management has also filed the photo copy of the letter of the Development Manager with copy to the branch manager Mardah branch, Regional Manager, Zonal Manager and Suptt Zonal Office in which the workman was recommended higher wages. In his letter he mentioned as follows

If we take into consideration the staff position and sitting arrangement in the branch Shri Algoo Ram is devoting much time than stipulated for cleaning and sweeping office furnitures and fixtures and supplying drinking water etc. We therefore recommend the use of Mr. Algoo Ram for increasing monthly remuneration payable to him as part time on 1/3rd basis.

A similar letter was written from the branch manager to Head office on 29-8-81.

In support of its contention the management examined two witnesses on affidavit MW 1 Shri M. I. Verma expressed his ignorance if the workman was working in the branch since June 72 or from before 1979. He further denied any knowledge about the letter written by the branch manager of Mardah branch recommending the case of Shri Algoo Ram that he was working for more than 12 hours in a week and from 1972. On the other hand the workman has examined two witnesses on affidavit one himself WW 2 and other Sri Praveen Rastogi WW 1 an employee of the bank. Shri Rastogi has deposed that he himself has joined the Mardah branch in November 75 and stayed there till April 83. He has further admitted that it is correct that the carpet area of the Mardah branch is 819 sq. ft. To a cross question of the management he replied that he did not know that the carpet area of the branch is more than 1000 Sq. Ft. 1/3rd scale of wages would not be applicable. The workman himself came into the witness box. In the end he said that it would be wrong to say that he was working only for 5 3/4 hours in a week in the bank rather he was working for more than hours stipulated in the



appointment letter. In his affidavit Sri Algoo Ram has clearly stated that he was working in the bank management from June 72 when the branch was opened there at Mardah District Ghazipur and that approximately he was working more than 2 hours daily. He has further stated that from June 72 he was paid Rs. 75 per month and nor he was getting Rs. 125 per month. The workman has filed letter to the branch manager Ghazipur dt. 13-9-79 where in particulars about part time sweeper is mentioned. Another letter dt. 30-8-79 in the enclosure, it is mentioned that Sri Algoo Ram is working since June 72 at Rs. 50 per month and his duty hours per week is 6 hours. The workman has also filed photo copy of the letter of the branch manager Mardah Branch dt. 15-10-81 addressed to the Head Office Bombay recommending 1/3 scale to the workman. The third letter filed by the workman is the recommendation of the branch manager dt. 6-7-82 in which the branch manager had recommended that the workman be given 1/3rd of the basic pay. In bipartite settlement of 1966 para 4.5 (b) it is laid down "That a part time workman who are members of the subordinate staff shall be paid 1/3rd of the scale wages with proportionate annual increment if their normal daily working hours per week range between 6 hours to 13 hours". As per document No. 1 filed by the workman on 11-2-85 Algoo Ram is working since June 72 for 6 hours in a week in the bank. In the settlement it is not mentioned as to what should be the carpet area of the bank and payment is based on the area (carpet) of the bank. In view of these letters filed by the management and also by the admission made in the letters filed by the management it is clear that the workman is working in the bank from before his appointment since 1st Oct. 1979 for hours ranging between 6 to 12 hours per week and it is also clear in view of the statement of MFW-2 Sri Rastogi who was at that time working in the said branch of the management bank.

I, therefore, believing the workman and his witness, hold that the workman was working in the bank from June 72 and also that he was not working less than 6 hours per week in the bank. The workman is therefore, entitled to 1/3rd scale of wages in view of the Bi-Partite Settlement.

I, therefore, give my award that the action of the management of Union Bank of India, in relation to their Ghazipur Branch in not paying 1/3rd scale of wages to Sri Algoo Ram, Part-time Sweeper as well as not regularising him in that post is not justified. The workman Sri Algoo Ram will be entitled to the said regularisation w.e.f. June 1972 and shall get balance of amount found due on that account.

I, therefore, give my AWARD accordingly.

Let six copies of this AWARD be sent to the Government for publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012/58/82-D.II(A)]

का.प्र. 2090. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक, प्राफ इंडिया के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कांपुर के पक्ष को प्रकाशित करती है। जो केन्द्रीय सरकार को 17-4-85 को प्राप्त हुआ था।

S.O.2090.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen which was received by the Central Government on the 19th April, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR, COURT KANPUR

I, D. No. 21 of 1983

In the matter of dispute between :—

Shri Daya Ram Misra, (Sub Staff), C/o Shri O. P. Nigam, Vice President UPBEC, 295/387, Deen Dayal Road, Lucknow.

AND

The Chief Manager, Central Bank Of India, Divisional Office, Gorakhpur.

AWARD

Shri : O. P. Nigam, representative for Workman, &  
Shri S. P. Tiwedi, representative for the Management.

The Central Government Ministry of Labour vide its order no. L-12012(302)/81-D.II(A), dated 20th July, 1982, referred the following dispute for adjudication:—

"Whether the action of the management of Central Bank of India in relation to their Gorakhpur Branch office in not absorbing Shri Daya Ram Misra Sub-staff in regular service of the bank is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

The case of the workman Shri Daya Ram Misra is that he was appointed as temporary peon in 1969 and continuously worked as such upto the year 1978 and during that span worked for full 1111 days. Out of the above said days he was paid total wages for 561 days initially, and thereafter, for the next 550 days he got regular salary applicable to the bank staff. According to the details supplied in the statement of claim from 1969 to 1975, he was given regular salary for 550 days and from 1974 to 1978, he was paid daily wages for 561 days. The bank opp. party was taking work from the workman in exigencies for bank work but the payment was made to him by bank through some other agency i.e. Zamadar of that bank on separate voucher declaring labour wages which was malafide. That the management bank was exploiting the service of the workman by keeping him on daily wages on the assurances that he may be get permanent job in the bank and utilising him in vacancies at Gorakhpur Branch created on retirements on permanent hands during the period 1972 to 78 without making permanent arrangements to fill up those vacancies. Further the workman is an approved candidate and as he passed the written test and interview in 1972, his place being 143 in the merit list. Thus he was entitled for permanent absorption in view of the Head Office Circular No. 4 of 1968. The workman has shown that in the span from 22-9-76 to 13-8-77 which would be one continuous year, he worked for more than 240 days i.e. in all 255 days, but the management did not care to absorb him on the permanent cadre. It is further averred in the statement of claim that the workman was discriminated by the management bank in not allowing him to complete 240 days for permanent appointment in the bank and the persons below him in the panel list of 1972 were allowed to complete 240 days and later observed in the bank as permanent employees. The names of four such persons are (i) Shri Anil Kumar Duta, (ii) Daya Nand Goswami, (iii) R. C. Bhatt and C. M. Tondon who were ranked in the merit list at serial nos 160, 167, 170 and 172 respectively. Further the approved list according to the Annexure M-I dt. 31st July, 1972 was to remain enforced upto 31st December, 1973, but Shri Chandia Prakash and Krishna Prasad temporary workman were taken in the employment just before the expiry date i.e. 31-12-73, and 1-5-73 and allowed to complete 240 days which was malafide and with a view to help some particular employees. Even if the lapse of time of merit list in December 73, persons were employed from that list in the year 1974, 75 and 76 to complete the back log of Schedule Caste and Schedule Tribe candidates. From the details supplied by the bank even general candidates were appointed from the said list in the year 1974, 75 and 76. Even according to the quota fixed for Schedule Caste and Schedule Tribe candidates, the back log on 31-12-77 show that only one S. C. and 5 S. T. were employed. Even

then the recruitment of 4 Scheduled Caste and 1 Scheduled Tribe was made in the year 1978 and 1979 which show that the merit list of July 72 was continued up to 1979, for recruitment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates.

It is also averred that the bank management violated the provisions of article 14 and 16 of the Constitution of India and made discrimination by keeping alive the merit list of 1972 upto December, 1979, for the appointment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates, but it was made non existing for the general candidates after December, 1973. In the end it is averred that the management did not give any letter in terminating the services of the workman and thus violated the mandatory provisions of the Shastri's Award and has prayed that the workman's termination be declared illegal and unjustified and orders be issued for permanent absorption of the workman with full back wages and other privileges.

The opposite party management bank raised preliminary objection in their written statement but did not press the same, hence no issue was framed on them. It is admitted that Shri Daya Shanker Misra worked in the bank from 17-2-69 as a sub-staff temporarily on leave vacancies and also on daily wages. He did not complete 240 days in all his continuous service hence he has no legal claim for appointment. The management has further admitted that some times outsiders were engaged on casual basis for work in the Gorakhpur Branch by Zamadar (Head Peon) of that branch and in such contingencies the zamadar could hire the services of any one on daily wages and payments was reimbursed to the zamadar. It is not disputed and averred that zamadar might have engaged the workman but it does not confer any right to the casual labour who was so engaged to claim full time service or full time wages applicable to the regular employees of the bank staff (sub-staff) cadre. It is further admitted that the workman Shri Mishra appeared for written test for post of sub-staff on permanent basis in the year 1972. A panel of successful candidates was thereafter drawn and the workman Sri Daya Ram Misra stood at serial no. 143 in the general category. The said list is Annexure M-I of the written statement. It is further averred that according to the time limit given in he said list it was to remain enforced upto 31st December, 73 only and the workman could not be absorbed by 31-12-72 and the panel was thereafter, scrapped. Thus according to the bank management the list prepared in the year 1972 outlived its operation and the workman could not claim any right on the basis thereof. It is further averred that mere impediment does not confer any right on the workman to be absorbed, in the bank service. The management has further admitted that Mr. Anil Kumar Dutta, Dayananad Goswami, R. C. Bhat and Chandra Mohan Toandon had completed 240 days in a calendar year, hence were given permanent appointment in the bank. It is further admitted that as per directives of the Govt. and obligations in the constitution, the bank had to fill the backlog of Scheduled Caste and Scheduled Tribe and hence the candidates belonging to such categories were given preference the management bank has averred that there was no obligation on the part of the management to declare vacancies and the recruitment was purely management's prerogative and no notice was required for termination of temporary service.

In the rejoinder it is averred on behalf of the workman that in the year 1976-77 during span of 22-9-76 to 13-8-77, the workman served in the bank for 255 days and thus completed more than 240 days in a year. The workman was appointed in the bank as peon, hence can not be equated with casual labour and as he was performing the duties of peon in the branch The bank was adopting unfair labour practice by paying the workman through Zamadar as street labourers.

The workman representative referred me circular no. 4 of 68 of the management bank regarding the policy for recruitment of staff. In rule 3 of the said circular all vacancies of clerks and sub-staff was to be notified in press and in the end of the said circular it is mentioned that from the final list of the candidates selected the names of those candidates who have been approved but could not be given any appointment for want of vacancy will be kept on a

waiting list. Such a list will have to be prepared for each category of staff and any vacancy arising in these categories during the course of year should be first offered to such candidates whose names appeared in the waiting list in the order of merit. Temporary staff if required at any time, should also be strictly drawn from this list. The rule does not lay down that after completion of one year or from any particular date from 31-12-73, as mentioned in the instant case in Annexure M-1, will stand abrogated. The normal interpretation would be that the list was to subsist till a fresh list was prepared adjudging the requirements of the ensuing year. Thus during that period existence of vacancies gives no right to candidate for appointment and the management was free to decide as to how many appointments is to be made from the waiting list and that the names of the candidates appears in the list of approved candidates will not entitle him for appointment in the bank. The workman would be entitled if he can substantiate malafide on the part of management bank in appointing person junior to him in the approved list or showing that he had completed 240 days in one calendar year and yet was not absorbed on the regular side.

It has been argued on behalf of the management that in view of Annexure X & Y filed by the management bank, a back log of Scheduled caste and scheduled tribe was to be prepared and for the recruitment special recruitment test was to be held mentioning the number of vacancies for scheduled caste and scheduled tribe candidates. In Annexure Y it was mentioned that it would be futile to adverse for all type of post in clerk and sub cadre and thus maintaining a long list to fill the post in a year or so. If scheduled caste backlog was to be filled a fresh recruitment test should have been taken and the entire backlog would have filled from that and not from the list which was expected to come an end on 31st Dec. 73. The management bank has conceded in cross examination with its witness that despite cancellation of list prepared in 72, the scheduled caste candidates were carried over as back log and were appointed subsequently. This shows that the annexure M-I, was not scrapped after 31st December, 1973, but the appointments of Scheduled caste and scheduled tribe candidates were made from that list till much later period. If this was the position and if no fresh examination of general candidates was held, the list should have been continued and not stopped after 31st December, 1973. Para 493 of the Shastri's Award lays down as follows :—

"We also recommend that the bank should give first preference to those members of their retrenched staff who were then qualified to fill up the vacancies. The bank should also maintain register of candidates in which their names, qualifications, previous experience and special merit recommendations should be entered and such register should be periodically and kept upto date. Such register should also have the names of retrenched and temporary employee whose work has been found satisfactory".

No such register has been maintained by the bank management to ensure the principle of last come first go in the matter of retrenchment. The management bank has conceded that the list Annexure M-I was continued much after 31-12-73 and the persons from that list were appointed on compassionate ground. From their averments and the documents filed it also emerges that the persons of those list, who had completed 240 days of work were made regular and appointed even though they were junior to the workman Sri Daya Ram Misra. A question arises why these juniors to Shri Daya Ram Misra were allowed to complete 240 days when the workman was working as temporary hand from before and was terminated, but if the termination was essential, the persons junior to him should have been terminated and not the workman. The practice of allowing the juniors from the merit list to complete 240 days and making them permanent shows the malafide intention of the management bank in giving preference to those who are not entitled to it and terminating the service of person senior in the merit list.

The representative for management bank has argued that all those temporary hands working in the bank from the above said list who had completed 240 days were made regular and permanent irrespective whether they were senior in the list or junior to Sri Daya Shankar Misra. On the said principle the workman who had completed 240 days during the span 22-9-76 to 13-8-77 should have been made regular and permanent. Further it has come in the evidence that one Ram Prakash Tewari whose names appear in the list of General Candidate was given appointment on 21-5-75 and was allowed to complete 240 days of work and was made regular. In not observing the principle of LAST COME FIRST GO, the management has infringed the provisions sec. 25(g) of the I.D. Act and similarly employing persons junior to the workman after terminating his services treating him temporary infringes the provisions of section 25(h) of the said act. As no opportunity was given to the workman before employing the persons junior to him to ward off mole practice on the part of the management bank it was laid down in the last lines of paragraph 495 of Shastri's Award :

"We further direct that on a candidate's appointment as temporary employ of probationer or a permanent member of a staff, bank shall give him written order specifying the ground of appointments and the pay and allowances to which he would be entitled and that such a written order shall give on the appointment order or part time employee also."

This was observed by the management bank in the case of the workman. My attention was also drawn to sub para 4 of para 522 of the Shastri's Award which lays down :

"The services of any employee thereafter then of a permanent employee or probationer may be terminated and he may leave after 14 days notice. Thus minimum 14 days notice of either said was a must which was not observed in the instant case."

The workman in his cross examination has mentioned the nature of his work in the bank which was to take drinking waters, of officials and customers and to do bank work of taking out vouchers other payment books taking ledgers and shorting out vouchers etc. He has admitted that at times he was paid but the rate was daily wages. He did not raised any objection as he was assured by the bank officials that his services would be regularised. He has stated that after 1977 he got payments through jamadar and prior to that year he used to get his payments under his signatures. It may be mentioned that it was on 13-8-77 counting from 22-9-76 that he had completed 240 days in span of one year and he has stated that he was not informed that the list of 1972 has exhausted and that he had to appear in the next test. The management witness Sri P. K. Dey has admitted in para 4 of his affidavit that in view of the bank policy those temporary workmen who has completed 240 days services in 12 calendar months should be absorbed in the service of the bank and should be taken in the employment on probation. He has admitted that despite cancellation of the list 1972 the scheduled caste candidates were carried over as backlog and were appointed subsequently.

Before termination of the services of the workman, the Branch Manager, Gorakhpur, recommended the case of the workman wherein, he recommended that the workman is in the touch with the banking duties as a peon and is well conversant with the all banking routine of the subordinate nature. As he is intelligent and labourious, he recommend his case for consideration. A similar representation was sent to the Assistant General Manager by number of staff members.

The workman vide application date 5-9-83 required the number of the appointments made from the list to fill up vacant existing vacancies with the date and place of appointment and also their names alongwith serial nos., given in the merit list dt. 31-7-72. The management replied

by filing the documents on point no. 3 showing the number of appointments made from the merit list. From the list supplied on point no. 3 it appears that Shri Ram Prakash Tewari, who was at serial no. 9 in the merit list was appointed on 21-5-75. Sri Dayanand Goswami was also appointed but his date and place of posting of appointment has not been mentioned in the list. Sri R. C. Bhat and Sri C. M. Tondon, who were at sl. nos 170 and 172 were also appointed on 15-5-79 and 18-6-79 respectively. It is alleged that they were given appointments in the bank, as they have completed 240 days work, in view of the bank's direction photo copy of which has been filed by the bank management. The management bank in its circular dt. 21st September, 79, on the point of absorption of the temporary employees who had worked 240 days or above in a year as mentioned in para 1 as follows:—

"Those candidates who have passed the bank's written test and interview and were placed on the approved waiting list and have worked for 240 days or more in a period of 12 months will be taken up for appointment and the need that the appointments should have been spread over the 12 months will not be insisted upon in their case."

This circular clearly shows applied to the workman's case and he should have been made permanent. Thus in view of the matter and in view of the discussions made above, the workman should have been made permanent on the basis of fact of having worked for more than 240 days as mentioned earlier.

I accordingly hold that the action of the management bank of Central Bank Of India in relation to their Gorakhpur Branch in not absorbing Shri Daya Shanker Misra in regular service of the bank is not justified. As persons junior to the workman in the merit list were given permanent appointments in May or June 1979 and as the services of the workman were terminated in 1978, he shall be absorbed in permanent appointment and shall be given the seniority from January, 1979. He will be entitled to all back wages and benefits accruing to the case.

In view of the long contest and representation, the workman's representative shall get Rs. 100/- as cost, from the bank management.

I, therefore, give the AWARD accordingly.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12012(302)/81 D II(A)]

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

का.प्र. 2091—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, स्टेट बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन में सम्बद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधि-करण, नई दिल्ली के पत्राट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-4-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 26th April, 1985

S.O. 2091.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the State Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 18th April, 1985.

## ANNEXURE

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I.D. No. 183/83

In the matter in dispute between :

Shri K. K. Razadan S/o Shri Karta Kishan, R/o J-11/72,  
Rajouri Garden, New Delhi.

Versus

State Bank of India through The Chief Regional Manager,  
11, Parliament Street, New Delhi.

2. Regional Manager, State Bank of India Region III,  
New Delhi.

## APPEARANCES :

Miss Deepika Law Assistant—for the Management.

None—for the workman.

## AWARD

Central Government, Ministry of Labour in April, 1983 vide Order No. L-12012(133)/82-D.II.A. made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of State Bank of India, in relation to their Delhi Region in refusing to correct the date of birth of Sri K.K. Razdan, Head Clerk at Region III, Delhi, Regional Office in the relevant records of the Bank on the basis of date of birth mentioned in his Matriculation Certificate is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The workman K. K. Razdan raised dispute through to the State Bank of India Staff Association about his date of birth and consequently his date of retirement. He joined the Management on 23-3-1944 as a clerk and was retired on the basis of his date of birth recorded in the Imperial Bank of India Employees Provident Fund records as 1-11-25 in November, 1985. His claim is that his actual date of birth is 1-11-26 and he ought to be retired only on 30-10-86 in accordance with that date of birth recorded in the Punjab University Matriculation Examination Certificate. Sl. No. 2420 Roll No. 27978 issued on August 24 1955 Punjab University Solan as a result of examination held in 1943.

3. The matter has been tried and the Management's case is that their recent circular is that the date of birth recorded earlier shall not be disturbed whereas the workman's case is that correct date of birth is recorded in the Matriculation certificate of which he offered the duplicate because the original have been lost.

4. It is to be seen that the workman in his own hand filled the Imperial Bank Employees Provident Fund Form on 19-4-45 wherein he declared his date of birth as 1-11-25 and it is common knowledge that in the Matriculation or other records a later date of birth is recorded for obtaining certain advantages there is no evidence of anyone or any parent giving his date of birth and the arbitrary date of birth written by him in his own matriculation certificate cannot have precedence over the date of birth given by him to the bank in writing on 19-4-55 and fault cannot be found with the management in insisting that the date of birth in their records should prevail. Accordingly the retirement by the Management the date of birth recorded with them since 1985 cannot be said to be unjustified and the workman is not entitled to any relief.

April 15, 1985.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O. P. SINGLA, Presiding Officer  
[No. L-12012/133/82-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

आदेश

का० आ० 2092.—समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपराधों के बारे में न्यायालय में शिकायत करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[सं०-एस-27013/1/85-महिला सैल]

अशोक गुप्ता, सयुक्त सचिव

New Delhi, the 26th April, 1985

## ORDER

S.O. 2092.—In pursuance of sub-section 3 of Section 12 of the Equal Remuneration Act 1976 (25 of 1976), the Central Government hereby authorises the Regional Labour Commissioners (Central) to sanction the making of complaints in Court in respect of offences under section 10 of the said Act.

[No. S-27013/1/85-Women's Cell]

ASOK GUPTA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

का० आ० 2093.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत कोकिंग कोल लि० की मुराईह कोलियरी के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं० 2, धनबाद के पचाट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 24-4-1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 26th April, 1985

S.O. 2093.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Muraidih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th April, 1985

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

## PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer

Reference No. 37 of 1983

In the matter of Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Muraidih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

## APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate

On behalf of the workmen—Shri B. K. Ghosh, Member, Executive Committee, Janta Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 18th April, 1985

## AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(469)/82-D.III(A) dated the 7th April, 1983.

## SCHEDULE

"Whether the action of the management of Muraidih Colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited in paying category-II wages plus some difference of wages to Shri Deva Bhuiya, Payloader Operator is justified in terms of the Joint Bipartite Committee for Coal Industry decision No. CSC/IBCCI/JR[94]/IMP/1167 dt. 2-2-1981 annexure-B, on grading of Excavation employees? If not, to what relief is the said workman entitled and from when?"

The case of the workmen is that the concerned workman Shri Dev Bhuiya was originally a category II workman and was being deployed as Payloader operator. He was transferred to Muraidih Colliery Area No. I to work as Payloader operator and since then he is continuing the job of Payloader operator. During the period of his work at Nudkharkee Colliery, Damoda Colliery and Muraidih Colliery he was sometimes mentioned as Payloader Khalasi/Helper and sometime as Payloader operator although he was taken the job of Payloader operator although. The Agent Muraidih Colliery by an office order dated 12-2-81 designated him as Payloader Operator but the management was paying him wages of Cat. II only upto March, 1982 and from April, 1982 he was sanctioned for payment of difference of wages between excavation Grade-D and Cat. II wages. The concerned workman is entitled to excavation Grade-D wages with effect from the date of operation of the decision of the Joint Bipartite Committee for the Coal Industry. The action of the management in paying the concerned workman only Cat. II wages, and difference of wages for working as Payloader is not justified and that the concerned workman deserves the wages of excavation grade-B as per JBCCI recommendation with effect from its date of operation.

The case of the management is that the concerned workman was on time rated job in Cat.II before he was given the chance to work as Payloader operator with effect from 12-2-81. The concerned workman was holding the substantive post of time rated work in Cat.II and he was allowed to work as Payloader operator during leave and sick vacancies of permanent Payloader operators or during the period of necessity for extra hands. The concerned workman had not been permanently absorbed as Payloader operator. The concerned workman received the difference of wages between Excavation Grade-D and Cat.II wages during the period for which he worked as Payloader operator. Before the workman is confirmed as Payloader operator he is required to pass the requisite trade test. The concerned workman could not pass the trade test for his confirmation in Grade-D or promotion to higher grade and as such till such period of his promotion the concerned workman was to get only the difference of wages between Grade-D and Cat-II for the period he had worked as Payloader Operator. The concerned workman cannot claim as a matter of right to be permanently absorbed as Payloader Operator in Grade-D unless the management finds him suitable and confirms him. On the facts it is submitted on behalf of the management that the claim of the concerned workman is not justified.

The point to be considered in this case is whether the concerned workman is entitled to the wages of Excavation grade-B, as per JBCCI recommendations.

The management examined one witness who is the Superintendent of Muraidih Colliery. He was cross-examined on behalf of the concerned workman. No witnesses has been examined on behalf of the concerned workman. The management has got two documents exhibited as Ext. M-1 and M-2. The workman has also got two documents exhibited which are marked as Ext.W-1 and W-2.

It will appear from the evidence of MW-1 who is the Superintendent of Muraidih Colliery that the concerned work-

man was known in Cat.II and that the concerned workman was transferred in 1982 from Muraidih Colliery to Barora Washery as Khalasi. He has stated that the concerned workman was authorised to work as Payloader operator in sick and leave vacancies and that the said authorisation was not the appointment of the concerned workman as Payloader Operator. He has stated that a Payloader Operator at the initial stage gets the wages of Grade-D excavation and that whenever the concerned workman had worked as Payloader Operator he was given difference of pay between Cat.II and Grade-D excavation. He has further stated that the concerned workman was not found fit to work as Payloader Operator and therefore he was not regularised as Payloader Operator. Ext.M-2 dated 12-2-81 is an office order issued by the Agent, Muraidih Colliery which shows that the concerned workman who was formerly working as, Payloader Khalasi was authorised to work as Payloader Operator with immediate effect. Ext. M-1 dated 2-2-81 is the copy of circular of the Joint Bipartite Committee for the coal industry which shows that Group-D Payloader operator Grade-III has to be skilled workman having two years experience in heavy equipment and heavy vehicles and capable of operating all types of payloaders of capacity 2 C.M. and less and that he should have also knowledge of the mechanism of the equipment and should be able to undertake minor running repairs. He is also required to hold valid heavy vehicle driving licence. There is no evidence that the concerned workman was fulfilling all the qualifications required for a Payloader Operator. The evidence of MW-1 shows that the concerned workman was not found fit and therefore he was not regularised as Payloader Operator. Ext.W-1 dated 18-7-79 is an Office order which shows that the Manager of Nudkharkee Colliery had directed the concerned workman who was working as Payloader Operator to report for his duty to the Superintendent, Damoda Colliery. Ext.W-2 is the original of Ext.M-2. There is no evidence to show that the concerned workman was permanently and regularly working as Payloader Operator. It also appears to be admitted from the W.S. of the concerned workman that he was paid the difference of wages between Cat.II to which he belonged and the wages of excavation Grade-D. MW-1 has also stated that the concerned workman got the difference of wages whenever he worked as Payloader Operator. It is clear, therefore that the concerned workman had not worked regularly as Payloader Operator and that whenever he had worked as Payloader Operator he had been given the difference of wages of Excavation Grade-D.

A petition was filed on behalf of the concerned workman on 15-4-85 that the concerned workman had been transferred by the management to Barora Washery project where neither Payloaders are used nor the excavation grades are applicable and as such the workman is not interested.

Taking the entire facts and evidence into consideration I hold that the action of the management of Muraidih colliery of M/s.B.C.C.Ltd, in paying Cat. II wages plus difference of wages to the concerned workman while working as Payloader Operator was justified in terms of JBCCI decision dated 2-2-81 on grading of excavation employees and as such the concerned workman is not entitled to any relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer  
[No. L-20012(469)/82-D.III.A]  
A.V.S. SARMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1985

का० आ० 2094—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मैनेजमेंट आफ वाशडा ब्रिगस बोर्ड नागस के प्रबंधन से सम्बन्धित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंबई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 15 अप्रैल, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 26th April, 1985

S.O. 2094.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhakra Beas Management Board, Nangal and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th April, 1985.

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
CHANDIGARH

Case No. I.D. 127/83 (Delhi), 77 of 1983 (CHD)

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhakra Beas Management Board, Nangal Township, Nangal.

#### AND

Their workmen S/Shri Roshan Lal and Malik Singh..

#### APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. L. Kaith.

For the Workmen—Shri R. K. Singh.

ACTIVITY : Bhakra Beas Management Board.

AREA : Punjab.

#### AWARD

Dated the 11th of April, '1985

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947, hereinafter referred to as the Act, vide their Order No. L-42012(1)/82-D.II(B) dated the 23rd of August, 1982 read with S.O.No.S-11025 (2)/83 dated the 8th August, 1983 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of B.B.M.B. in promoting Shri Sat Pal Shah from the post of Supervisor to Chargeman w.e.f 1-9-78 while superseding S/Shri Roshan Lal and Malik Singh (Senior Supervisors) is justified? If not, to what relief the workmen are entitled?"

2. To trace a short history of the matter, petitioner Roshan Lal Token No.228-M and Malik Singh Token No.332-M joined service in the trade of Grouting Inspection Drill in workcharge capacity under the Respdtd.Board w.e.f. 1-12-56 and 20-1-57 respectively, they were promoted as supervisors w.e.f. 1-5-60 and 1-3-61 respectively. The petitioners averred that they had a junior colleague in Shri Sat Paul Shah Token No.337-M who also joined service in their trade on 8-1-1960 and was promoted as supervisor w.e.f. 1-5-61. It was complained that in flagrant violation of the promotion rules, practice and convention the Management superseded both of them and promoted the aforesaid Shri Sat Paul Shah as Chargeman Misc w.e.f. 1-9-78 even though the Chairman Bhakra Beas Management Board had already circulated his decision that seniority alone was to be the decisive factor to grant promotion unless there was anything inherently wrong with an employee. The petitioners complained that besides being junior to them Shri Shah did not have even the elementary knowledge of the job because he had no field experience and had rather been working on the office seats.

3. They, therefore, raised a demand and tried to impress upon the management the desirability of withdrawing the promotion order of Shri Sat Paul Shah and redress their grievance on promoting them. However the dispute could not be settled amicably despite the intervention of the A.I.C.C. in the Conciliation proceedings and hence the reference.

4. Resisting the proceedings, the Management disputed the validity of Reference for want of an existing or apprehended dispute as well as locus standi of Shri Ram Kishan Singh

to file the Claim Statement on petitioners' behalf. It was further pleaded that their cause was not properly espoused by the majority Union. Of course, most of averments of fact were left uncontroverted but it was seriously asserted that Shri Sat Paul Shah belonged, to an entirely different trade of Gunniting which had nothing in common with Grouting Inspection Drill and, as such, the petitioner's seniority in the later category was absolutely irrelevant for deciding the promotion matter of Shri Sat Paul Shah. As a necessary corollary the Management denied having violated any rules, practice, convention or the instructions of the B.B.M.B. Chairman in dealing with the impugned promotion.

5. The parties were taken to trial on the following issues framed over and above the terms of Reference.

1. Whether the reference is legally infirm and incompetent as alleged? OPR
2. Whether the dispute is not properly espoused? OPR
3. Relief.

In support of their respective versions the parties adduced verbal as well as documentary evidence which I have carefully perused and heard them at length. My issue-wise discussion and findings are as follows :—

#### Issue No. 1 & 2

7. Both these issues are interconnected and have been jointly argued before me, therefore, I propose to deal with them at a stroke. The Management had three fold arguments, firstly, that the petitioner's case was not espoused by a Union enjoying majority support, secondly, that their claim statement was not filed by a duly authorised person and thirdly, that there was no pending or apprehended did dispute to warrant adjudication.

8. A bare reference to the Claim-Statement alongwith the duly filled in from (F) under Rule 36 attached therewith should leave no manner of doubt that Shri R. K. Singh who was the General Secretary of the Nangal Bhakra Mazdoor Sangh and a member of the Executive Committee of the INTUC (Punjab), was duly authorised by them to file the Claim Statement as their representative in these proceedings. In the same sequence, parties correspondence at the demand stage and in the conciliation proceedings before A.L.C.(C) would suffice to establish the propriety of espousal of their cause by the Bhakra Beas Employees Union which was a recognised and registered body having considerable strength and support amongst the workmen, moreover its locus-standi was conceded even by the Management in the Conciliation proceedings.

9. Similarly it would be quite preposterous to say that there was no pending or apprehended dispute between the parties because a bare perusal of the pleadings would leave no matter of doubt that there was a long standing controversy between them on the point of petitioners' promotion, to fall with in the purview of an "industrial dispute" as defined by Section 2(k) of the Act. Accordingly on over ruling all the technical objections raised by the Management I answer both the issues against them.

#### Terms of Reference and Relief

10. On behalf of the Management it was strenuously argued that since Gunniting and Grouting Inspection Drill were two distinct and different trades, therefore, the petitioners effort in pressing home the point of their over all seniority on Shri Sat Pal Shah, to claim promotion, was thoroughly misconceived. Support was drawn from the testimony of Shri I. P. Sharda MW1 who was working as Officer Incharge in the designation of Junior Engineer (Mechanical) and looking after the performance of Shri Sat Paul Shah, who, in turn, was the sole supervisor in his trade. Reliance was also placed on the relevant seniority list Ex. C2 to show that there was no other person in his trade to claim seniority over him.

11. Despite seeming attraction the submission failed to carry conviction with me primarily because the deposition

of Shri Sharda and the seniority list Ex. C2 were sought to be magnified in isolation. On the other hand when we appraise their evidentiary value in the context of seniority list of the Workcharged establishment circulated in March 1977 vide letter Ex. W5, we cannot possibly resist the inference that for all intents and purposes, Gunniting and Grouting Inspection Drill belong to the one and the same common Trade from which different channels in the shape of Gunniting etc. have been devised by the management; which might be for administrative convenience or some such other reason. To be precise, in this document Shri Sat Pal Shah has been shown to be a Supervisor in the parent Trade of Grouting Inspection Drill at serial no. 122 and significantly enough, the Management skipped over to reveal the names of any of his colleagues, senior or junior, employed in that trade. As the risk of reptition it may also be pointed out that both in the matter of his initial recruitment as well as promotion to the post of a Supervisor, Shri Sat Paul Shah was admittedly junior to the petitioners. It, therefore, follow that despite his juniority he was allowed promotion to the rank of a Chageman Misc. over and above the petitioners.

12. This directly confronts the Tribunal with the task of finding out as to how far such an action was justified. The Management had projected a sort of double defence one of which stands discarded as above. The second line of defence was that the promotion was regulated on seniority-cum-merit basis. However they did not elaborate as to on what basis Sat Paul Shah's service was assessed as qualitatively superior to that of the petitioners. Usually such assessment is based either on the past entries in service record, educational or professional efficiency, trade test or interview etc. but no such exercise was undertaken in the instant case. As a matter of fact it was not even propagated by the Management either by way of pleadings or evidence. On the other hand perusal of the minutes of a meeting held on 9-5-75 in the Board's office by the Chairman of the B.B.M.B. with the representatives of the Trade Unions, as circulated by their Secretary per his endst No. 384-86/B.B.M.B. with the representatives of the Trade Unions, as had to be regulated strictly in accordance to one's seniority unless the person concerned was found unfit on the basis of his previous record, and it goes without saying that there was nothing wrong with the petitioners' record.

13. Thus sustaining the petitioners' cause I hold that the Management had no justification in superseding them while awarding the promotion to their junior colleague Shri Sat Paul Shah to the post of a Chageman Misc.

14. Accordingly I return my award in their favour with a direction to the Management to re-examine and decide the entire case of promotions in the light of my aforesaid findings.

Dated 11-4-1985.

Chandigarh

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42012(1)/82-D.II(B)]

प्रा.अ. 2095:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, पी एण्ड टी, डिपार्टमेंट, उलसूर, बैंगलोर टेलीफोन बैंगलोर के प्रबंधन से सम्बद्ध कर्मियों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, बैंगलोर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो पंचाट के नगर को 15 अप्रैल को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2095.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of P&T Department Ulsoor, Bangalore Telephones, Bangalore and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th April, 1985.

127 GJ/85—22

## BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL IN KARNATAKA, BANGLORE

Dated this the 30th day of March, 1985

PRESENT :

Sri R. Ramakrishna, B.A., B.L., Presiding Officer.  
PRESIDING OFFICER

Central Reference No. 17 of 1984

I PARTY.

Smt. Polina,  
C/o Shri G. Isaac,  
No. 23, Kaliammal Koil  
Street, Ulsoor,  
Bangalore-560008.

-Vs-

II PARTY

The Assistant Engineer,  
P & T Department, Ulsoor,  
II(Cross Bar), Bangalore  
Telephones.

APPEARANCES :

For the I Party :—Sri V. Gopala Gowda, Advocate  
Bangalore.

For the II Party :— None present

REFERENCE

(Government Order No. L-40012(6)/83-D.II(B) dated 7-6-1984).

AWARD

The Government of India in exercise its power conferred under Section 7A clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (short called as Act) has made his reference for adjudication of the existing industrial dispute between the parties. The points of dispute in the order of reference read as follows :—

SCHEDULE

"Whether the action of P&T Department in relation to their Assistant Engineer of Telephone Exchange, Bangalore in terminating the services of Smt. Polina, a casual labourer with effect from 16-9-82 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. After receipt of this reference, notices are issued to both the parties on 14-6-84 posting the case to 30-6-84 and on that date one Mr. V. Gopala Gowda, filed Vakalat for the I Party and one Sri T. R. Rangaraju, filed Memo of appearance for the II Party. On 31st August, 1984 the I Party filed her claim statement and the case was adjourned for counter statement of the II Party and in spite of giving 8 adjournments the II Party neither appeared nor filed the counter statement and hence on 16-1-85 the II party has been placed ex parte. Thereafter, the I Party Smt. Polina has examined herself in support of her claim statement. In view of the continuous absence of the II Party, the case is proceeded further.

3. The I Party contended in her claim statement that she has been employed in the II Party-management on 1-8-1978 as a casual mazdoor with 7 hours duty per day and was drawing Rs. 3.96 per day. After giving one month's break in service she has again taken on 24-3-79 which is a clear case of unfair labour practice. During her second period of employment she was paid Rs. 4.81 per day and she was discharging her duties honestly and to the best satisfaction of her superiors.

4. She has further contended that from June 1980 she was placed in 1st category as a full time casual mazdoor with 8 hours work per day with Rs. 172/- wages per month. On June 1981, she was promoted to 2nd category with a salary of Rs. 330/- per month. From then onwards she was doing her duties continuously without any break in service until she has been terminated by the II Party on 16-9-82 without any notice being served on her. She has further alleged that she has been victimised for demanding her legitimate rights as the



II Party was not provided basic amenities and she has been harassed mainly times morally and was extracting over time frequently without wages. She has not been given any labour statutory benefits, such as, provident fund, E.S.I. etc. for which a Government servant is entitled and she was placed continuously under the discretionary powers of the II Party-management for the whole service of 4 years rendered by her. She has further contended that the II Party-management developed an unreasonable and adamant attitude towards her for having taken part in the trade union activities and finally terminated her.

5. She has further alleged that she has not been given any charge sheet, notice of termination and any reason for termination and no enquiry was held which goes to prove the determined and planned termination as a measure of victimisation for the trade union activities.

6. She has further contended that the refusal of employment is also violative of Section 25-F clauses (a) and (b) and Section 25-G of the Industrial Disputes Act and further violative of natural justice, hence it is a clear case of unfair labour practice committed by the II Party. She has further contended that without assigning any reason refusing employment tantamounts to retrenchment which is defined under Sec. 2(oo) of the Act, the II Party has not complied with the mandatory requirements of the Act which are conditions precedent before refusing employment.

7. She has further contended that she is a widow having one son and two daughter and finding it very difficult to keep her body alive. Hence the termination without taking into consideration is illegal, arbitrary, capricious, unjust, unreasonable and vexatious and the same is liable to be set aside. She has further contended that as per the latest decisions of all the Courts she must be confirmed having served 240 days continuously in a year, therefore an award has to be passed in her favour for reinstatement with continuity of service, full back wages and other consequential benefits with costs.

8. Since the II Party have failed to file their counter statement and failed to appear before this Tribunal an Interim Relief was granted by an Interim Award dated 26-12-1984.

9. Now the only issue that arises for determination is :-

- (1) Whether the II Party is justified in terminating the services of Smt. Polina with effect from 16-9-1982?
- (2) What order ?

10. Issue No. 1 :- Smt. Polina has adduced her oral evidence supporting her claim statement reiterating the allegations made by her and produced the appointment order dated 1/16-8-78 as Ext. W-1 and another appointment order dated 27-3-79 marked as Ext. W-2. She has further deposed that before her removal she has not been served with any charge sheet and she has been appointed after verifying the Employment Exchange card which management kept in their custody. She has further deposed she has been victimised by the II Party when she started demanding her legitimate legal rights and she has not been provided the basic amenities and she has been harassed morally as she was the lowest paid employee and they were extracting overtime work without any wages and hence she reported this matter to the union and thereafter she has been removed from service. She has further deposed that the juniors who have been appointed subsequently are continued in their work and if she was continued, her services would have been confirmed as a permanent employee from June 1983. She has further deposed that the bonus that was sanctioned to her was not paid by the management and her husband died during 1976 due to an accident leaving her three children and she was solely depending on the salary for herself and for her children and prayed for reinstatement with back wages and continuity of service.

11. In view of no rebuttal evidence by the II Party and non filing of counter statement the stand taken by the I Party is unchallenged. The allegations made in the claim statement and the evidence adduced by the party reveals a very sorry state of affairs on the part of the II Party which has refused work without resorting to statutory provisions as contemplated in the Industrial law. This Tribunal is failed

to understand the tendency adopted by the II Party in not co-operating for the progress of the case though 8 months have been lapsed from the date of reference to the date of final arguments.

12. The allegation of the I Party that she has not been served with any notice before refusal of work which amounts to termination without conducting any enquiry about any misconduct attract the provisions of Section 25-F and Section 2(oo) of the Act. In a decision reported in AIR 1974 SC 1166 (M/s Willcox Buckwell India Ltd., vs. Jagannath & others) when some of the workmen were terminated on the ground of surplus labour it was held :-

"Termination of services even of a temporary employee on the ground of surplus labour amounts to retrenchment and the employee is entitled to claim retrenchment compensation. As that was not done, the Labour Court was fully justified in ordering their reinstatement".

13. In Mohan Lal, Bharat Electronics Ltd., reported in 1981 II I.J. 70 Their Lordships of the Supreme Court when the services of a Salesman was abruptly terminated by a letter have held :-

"On facts, the termination of service of the appellant did not fall within any of the excepted, or to be precise, excluded categories. Undoubtedly, therefore, the termination would constitute retrenchment and by a catena of decisions it was well-settled that where prerequisite for valid retrenchment, as laid down in Section 25F had not been complied with, retrenchment bringing about termination of service was ab initio void."

14. This view was reiterated by the Hon'ble Supreme Court in AIR 1983 SC 1320 (Management of Karnataka State Road Transport Corporation, Bangalore vs N. Ramiah and another) that where the discharge of a probationer was held to be violative of Section 25 F of the Act and termination held to be bad

15. In view of the pleadings, evidence, documents and the decided case laws on this point, the termination or refusal of work of Smt. Polina by the II Party is unjustified. Hence I make the following award :-

#### AWARD

The Assistant Engineer of Telephone Exchange P & T Department, Bangalore, in terminating the services of Smt. Polina a casual labourer with effect from 16-9-82 is not justified. Consequently, it is ordered that she shall be reinstated with back wages, continuity of service and other consequential benefits. The II Party shall also pay a cost of Rs. 1000/-. If any Interim relief has been paid in view of an Interim Award passed by this Tribunal dated 26-12-1984 the same shall be adjusted in the arrears of her wages payable to her.

(Dictated to the Stenographer, transcribed and typed by him and corrected by me).

R. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[No. L-40012(6)/83-D.II(B)]

का० आ० ३०५६ :- औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ (१९४७ क १४) की धारा १७ के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, डी०पी०ओ० एण्ड डी०एम० सी० सार्वजनिक रेलवे, लखनऊ के प्रबंधन में सरकार नियंत्रकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनवरत में निरन्तर औद्योगिक विवाद में में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को १२ अप्रैल को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 2096.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employees in relation to the management of D.P.O. and D.S.F.II, N. Railway, Lucknow and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th April, 1985



BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR, COURT, KANPUR

I.D.'s Nos. 3, 4 and 10 of 1984

In the matter of dispute between :

1. Shri Ram Chandra,
2. Shri Safiq Ahmad, &
3. Shri Umesh Chandra

Workmen.

Through B. D. Tewari, 96/196, Roshan Bajaj Lane, Ganesh Ganj, Lucknow.

AND

The Divisional Manager, Northern Railway, Lucknow—

Management.

Shri B. D. Tewari representative for the workmen &  
Shri B. P. S. Chauhan representative for the management.

### AWARD

The Central Government, Ministry of Labour vide order No. L-41012/33/83-D-II-B, dated 7-1-84, order No. L-41012/32/83-D-II-B, dated 7-1-84 and order No. L-41012/35/83-D-II-B, dated 21st January 1984 referred the following dispute for adjudication :—

1. "Whether the action of the Railway Administration in relation to senior Civil Engineer, Northern Railway Charbagh, Lucknow in terminating the services of Shri Shafi Ahmad S/o Shri Habib Khan Khalasi w.e.f. 1-9-77 is justified. If not, to what relief if any, is the workman concerned is entitled?"
2. "Whether the action of the Railway Administration in relation to the Divisional Superintending Engineer-II Northern Railway Lucknow in terminating the services of Shri Ram Chander S/o Shri Babu Lal Khalasi w.e.f. 15-1-75 is justified? If not, to what relief if any is the workman concerned is entitled?"
3. "Whether the action of the Northern Railway Administration in relation to the Divisional Railway Manager, Lucknow is justified in terminating the services of Shri Umesh Chand S/o of Shri Benchoo Lal, ES/79 casual labour under I.O.W. Locoworkshop Charbagh Lucknow w.e.f. 15-10-77? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

The above three cases were consolidated on the request of the representative for the workmen as common question of fact and law arose in them and I.D. No. 4/84 was made the leading case.

The case of the workman Shafiq Ahmad is that he was recruited as casual labour on 2-12-72 and worked continuously upto 31-12-73. His services thereafter were terminated without compliance of Sec. 25(F) of the I.D. Act even though he had worked for 378 days.

Similarly workman Ram Chandra of the I.O. No. 3/84 worked under Civil Engineer Charbagh as casual labour from 20-1-74 and continued till 14-1-75 when his services were terminated without having retrenchment compensation though in fact he had worked continuously for 349 days.

Lastly in the case of Shri Umesh Chandra workman I.D. No. 10/84 the workman was appointed on 9-9-77 and worked upto 15-10-77 continuously. He was told not to come on duty on 15-10-77. At the time of termination he was not paid retrenchment compensation though he had completed 240 days of continuous service on one calendar year.

The management despite notice of the cases did not file written statement or adduced any evidence to contest the case, consequently the case against the management proceeded ex-parte. Safiq Ahmad, Ram Chandra and Umesh Chandra have filed affidavits in support of their case. Ram Chandra has filed photo copy of his casual labour card which corroborate his case that he from 21-2-71 to 14-1-75 which sub-

stantiate that he worked for more than 240 days in one continuous year counting backward from 14-1-75.

Workman Shri Shafiq Ahmad has supported his claims statement by affidavit and has filed Annexure A record of service as casual labour which on calculation comes to 260 days in one continuous year counting back from the date of termination i.e. 31-8-77.

Before a workman can complain of retrenchment being not in consonance with Sec. 25(F) he has to show that he has been in continuous service for not less than 12 months under any employer who has retrenched him from service. Further the Sec. 25B (ii) prescribes a situation which is in the instant case where a workman is not under employment for a period of 12 calendar months but has rendered services for a period of 240 days within the period of 12 calendar months commencing and counting backward from the relevant date i.e. the date of retrenchment.

In Robert D'Souza Vs. Executive Engineer Southern Railway and another S.C. Cases (I&S) page 121, it was observed in para 12 thus :

"The test provided in rule 2501 in chapter 15 of the Indian Railway Establishment Manual is that for the purposes of treating the eligibility of casual labour to be treated as temporary, the criterion should be the period of continuous work put in by each individual labour on the same type of work and not the period put in collectively by any particular gang or group of labours. Therefore, if a person belonging to the category of casual labour employed in construction work other than work charged projects renders six months continuous service without a break by operation of statutory rule the person would be treated as temporary continuous workman.

It was further observed in para 21:

"Although a casual labour employed in a project irrespective of duration can be by virtue of rule 2501 (b)(i) even construction work does not imply project. Project is correlated to a planned project in which the workman is treated as work-charged. Construction Unit is a regular unit all over Railways. It is a permanent unit and can not be equated to project.

It was lastly observed in paragraph 27 as follows :

"Even assuming that he was a daily rated worker once he has rendered uninterrupted continuous service for a period of one year or more within the meaning of Sec. 25(F) of the Act and his services is terminated for any reason whatsoever, the case does not fall in any of the accepted category of Sec. 25(F) of the I.D. Act notwithstanding the fact that rule 2505 would be attracted would have to be read subject to the provision of the Act. Accordingly the termination of the service in this case would constitute retrenchment and for not complying with the precondition to valid retrenchment, the order of termination would be illegal and invalid."

In the instant case the workman were casual labour of the construction division of railway and had worked more than 240 days in one continuous year. Thus they were temporary workmen of the Railway and retrenchment without paying retrenchment compensation, notice pay etc. as required under Sec 25(F) of the Act, the retrenchment is void ab-initio.

The result is that the workmen are entitled to be reinstated in service with all back wages and full benefits.

With the discussions made above I hold that the action of the management in terminating the services of the workmen are not justified and the workmen are entitled to be reinstated with full back wages and all benefits.

I, therefore, give my Award accordingly.

Let 6 copies of this award be sent to the Government for Publication.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-41012(33)/83-D II(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

